बंगाल का अकाल

डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी

(अनुवादक)

भगवती प्रसाद चन्दोला
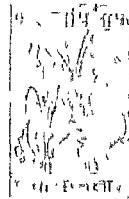
सं च यि नी * क ल क त्ता
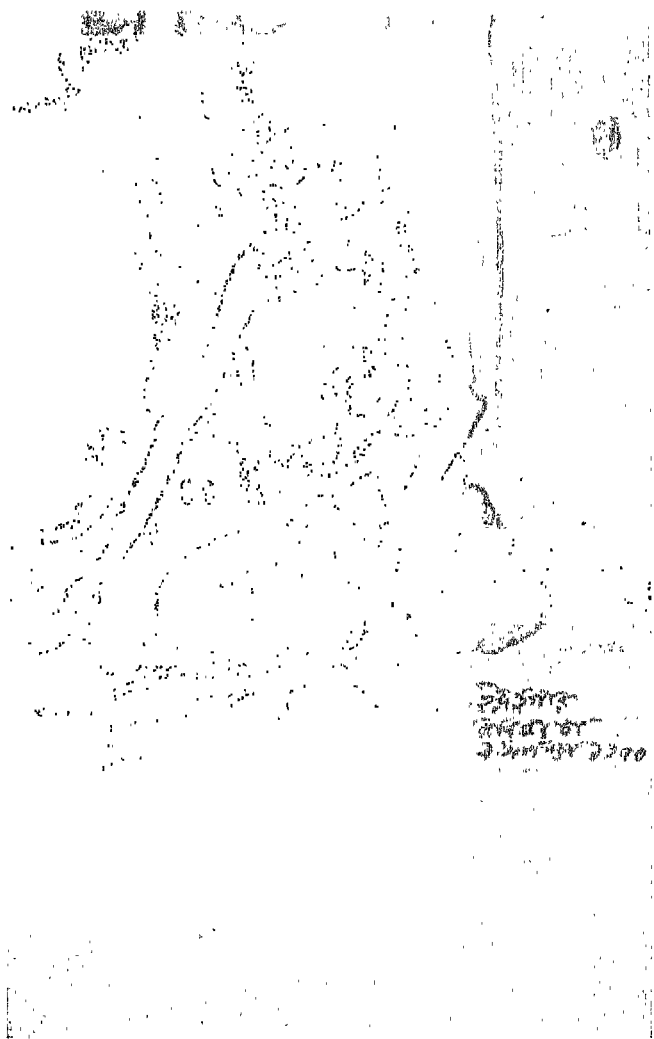
कलाकार श्री इन्द्र दुगाड़ द्वारा खींचे हुए इस पुस्तकमें चार स्केच भी हैं।
ये कल्पित नहीं, बल्कि उनकी आंखों देखे दृश्योंके नमूने हैं।

घर-गृहस्थी, लज्जा-
सङ्कोच सभी कुछ
गया, किसान-माता
कलकत्ते की सड़कों
पर आ खड़ी हुई है।
सूखी छातीपर एक
बूँद भी दूधका नहीं,
औलाद को कौन
बचायेगा ?

खुलेआम हरिसन
रोडके ऊपर :
इन्सान डाँगरों के
साथ 'डस्टबिन' से
जूठन खा रहा है।

—शून्यमें लोप हुई उन अगणित आत्माओंको,
जिनकी मूक-वेदनाओंने बेकसीका नाच देखा,
झूठे दंभका दम देखा और देखी बची-खुची
मनुष्यता की समवेदना और सहानुभूति।

अपनी ओरसे—

अमेरिकन ऋषि एमर्सनका कथन है कि जब मैं एक 'सुन्दर पुस्तक' पढ़ता हूँ तो यही सोचता हूँ कि मेरी उम्र हजार वर्षकी हो। यह अमूल्य वाक्य सचमुच हमेशा याद रखने लायक है।

'संचयिनी'के रूपमें जब हमने हिन्दी-प्रकाशन क्षेत्रमें आनेका संकल्प किया, तो, हम ऐसे ही सपनेको लेकर चले थे। पर हम इस बातसे भी अजान न थे कि सही मायनोंमें एक 'सुन्दर पुस्तक'को पाठकके हाथोंमें रखना कितना कठिन काम है। फिर भी एक ऊँची-सी बातका सहारा एक भव्य आदर्शकी प्रेरणा, क्या अपने आप ही हमें वह ताकत नहीं देती, जो कठिनाइयोंको बहुत-कुछ सहल बनादे? बस यही बूता है जिसके भरोसे हम अपने काममें आगे बढ़नेकी आशा रखते हैं।

पर अभी तो खड़े हो ही न पाये थे कि सरकारी चाप—'पेपर कन्ट्रोल (इकनामी) आर्डर ' ४४ आ पड़ा। पाँव कुछ लड़खड़ाने लगे। फिर भी यही सोचकर हिम्मत करते हैं कि हमें तो अपने हकोंके लिये पग-पगपर लड़ना है।

हमें खुशी है कि 'संचयिनी'की पहली भेंटके रूपमें हम डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जीकी पुस्तकको लेकर पाठकोंके सामने आ रहे हैं। आजके बंगालकी समस्याओंने उनके हृदयमें जो विद्रोह और बेचैनी पैदा कर दी है, वह उनके हरेक लफ्जसे जाहिर होती है, बंगालकी परिस्थितिपर, डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जीसे बढ़कर ऐसा कौन व्यक्ति है जो अधिकारके साथ कुछ कह सके? मौजूदा पुस्तकमें संग्रहीत भाषण और वक्तव्य सभी दर्दसे सने हैं। इसके अलावा आपके सामने उन्होंने, भीषण अकालके उन संकटके दिनोंमें यहाँके तथा सात-समुद्र-पारके अधिकारियों द्वारा अख्तियार की हुई नीति और उनकी अकर्मण्यताका निहायत मार्मिक शब्दोंमें वर्णन कर उन्हें मूर्त रूपमें प्रकट कर दिया है।

'बंगालका अकाल'के प्रकाशनके द्वारा हम अपने पाठकोंके दिमागमें उन घटनाओंकी स्मृतिको, जिन्हें उन्होंने पिछले साल बंगालके हर कस्बे, हरेक गाँव तथा कलकत्तेकी सड़कोंपर देखा था, हमेशाके लिये तरोताजा रखना चाहते हैं। निस्सन्देह, आज कलकत्ता नगरीकी सड़कें, पेटकी ज्वालाओंसे पीड़ित हाथ फैलाये हुए उन नर-कंकालोंसे साफ है, मगर उनकी छाया अभी भी बंगालके बहुतेरे स्थानोंमें यत्रतत्र नजर आती है। भय यह है कि कहीं यह छाया फिर अकालका रूप न धारण कर ले।

'बंगालका अकाल' हमेशा आपको इसका स्मरण दिलाता रहेगा, ऐसी हमें उम्मीद है; उसके निराकरणके लिये हमें अग्रसर करता रहेगा, ऐसा हमें विश्वास है।

कलकत्ता —प्रकाशक

सूर्य्य ग्रहण
श्रावण बदी ३०
वि० सम्वत् २००१

निवेदन

कतिपय उत्साही कार्यकर्त्ताओंके शान्त आग्रहसे यह पुस्तक प्रकाशित हुई है।

यह शान्त आवेष्टनके वीच सम्पूर्ण निरासक्त दृष्टि लेकर लिखी हुई पुस्तक नहीं। मुझे अकालके सम्बन्धमें धारा- सभा और अन्यत्र अनेकों वक्तृता देनी पड़ी हैं। कामके आवश्यक प्रयोजनसे कतिपय वक्तव्य भी दिये हैं। उनका भावानुवाद इस पुस्तकमें दिया गया है। मरघटके डरावनेपनके बीच पीड़ितोंकी दर्दभरी पुकार सुनते-सुनते जो लिखा या कहा है, वही इस पुस्तकके रूपमें प्रकाशित होगा, कुछेक हफ्ते पहले भी यह कल्पनातीत था।

एक ही विषयको लेकर बहुतसे स्थानोंपर बोलना पड़ा है, इससे अनेक पुनरुक्तियाँ हुई हैं। भाषणमें जो सब बातें मैंने कही हैं, पराधीन देशके अवस्था-दोषसे उनमें बहुत-सी बातें छपी ही नहीं; इसलिये कहीं-कहीं भावकी असंगति हो सकती है। अनुवादमें (अँगरेजीसे बंगलामें) भाषाकी स्वच्छन्दता भी शायद किसी-किसी जगहपर नष्ट हुई है।

तब भी इसमें कतिपय मर्मस्पर्शी सत्योंका उद्घाटन हुआ है। कार्य-क्षेत्रमें हजारों दुखी देशवासियोंके सम्पर्कमें आनेसे ही इस सब सत्यकी उप-

लब्धि हुई है। इसमें दोष और त्रुटियोंके रहते हुए भी, एकत्र संकलित होनेके कारण, अपनी असहाय अवस्थाको समझनेमें, इससे सभीको सहूलियत होगी। इसीलिये मैंने उद्योगी लोगोंको इस कामसे रोका नहीं।

और भी एक कारण है। अकालसे सम्बन्धित पूरी बातोंका इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। उससे बहुतसे राज़ खुलेंगे। इस तरहका संकट फिर न आ सके, देशवासी इस सम्बन्धमें यथासम्भव सतर्क हो जायँगे। जिनके पास शक्ति और समय है, यह पुस्तक यदि उनकी खोज करनेकी इच्छाको जगा सके, तो हमारा उद्देश्य सफल होगा।

सरकारके कृपापात्र दलने हमारे कार्योंकी लगातार विकृत व्याख्या की है। पीड़ितोंकी सेवाकी चेष्टाओंमें राजनीतिक धोखाधड़ी आरोपित हुई हैं। जिसे मानसिकताने चरमतम दुःसमयमें भी कुत्सा रचना की है और बार-बार अकर्मण्यताका परिचय देकर भी जो झेंप नहीं मानती उसका जवाब देना उसको सम्मान देना है। संकटकी तुलनामें हमने बहुत ही थोड़ा आयोजन करके काम शुरू किया। जी-तोड़ कोशिश करनेसे सहायताका प्रबन्ध जो हो सका है, उसका सौगुना और होना चाहिये था। किन्तु एक काम हुआ है—पर्वताकार दुष्कर्म और निष्क्रियताको छिपानेकी जो चेष्टा हुई थी, हमने उसे नाकामयाब कर दिया। लोग मरे हैं; किन्तु मरनेवालोंकी दर्दभरी पुकारको सूबेकी सीमाके भीतर बँद करके न रखा जा सका; समुद्र पार कर देश-विदेश तक वह पहुँच गयी है।

मेरे लेखों और भाषणोंसे अगर कोई आहत हुए हों, तो मेरी लाचारी है। जिनके जिपनसेही मेरे देशवासियोंकी यह बेहद बरबादी हुई है, किसी वजहसे भी हम उन्हें क्षमा नहीं कर सकते। इतिहास चिरकाल तक उनको

कलंकयुक्त रूपमें दिखलायगा, जुबानी तौर पर हम उनको क्या सजा दे पाये हैं।

कराल अकालके बीच मनुष्यकी दुःख-दुर्गति और नीचाशयताको देखा है। वैसे ही फिर मनुष्यकी उदार महानुभावतासे भी विमुग्ध हुआ हूं। देशवासियोंसे हमने आवेदन किया था। जो लोग अधिकारकी जगहोंपर बैठे हैं, हालतको मामूली बनाकर दिखाकर और धोखाधड़ीका आरोप करके वे एक तरहसे सहायताकी चेष्टाको नष्ट ही कर रहे थे। यह होते हुए भी भारतवर्ष और भारतके बाहरसे बहुत सहायता आयी है। पीड़ित मनुष्यको बचानेके आग्रहसे प्रांतीयताका विभेद और साम्प्रदायिक संकीर्णता कहां डूब गई है।

हजारों दाताओंके अटूट विश्वास और प्रीति-धारासे हम अभिभूत हुए हैं। बंगाल रिलीफ कमेटी और बंगाल प्रांतीय हिन्दू-महासभा रिलीफ कमेटीसे मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध है। इन दो संस्थाओंने जो किया है, परिशिष्टमें उसका संक्षिप्त विवरण दिया गया है। सैकड़ों सेवा करने वालोंने रात-दिन श्रम किया है। खिलाफ कहने वाले भौंहें चढ़ायें, किन्तु संकटके समय देशवासियोंने फिर एक बार एकता और असीम सेवा-भावका परिचय दिया है।

किन्तु पीड़ितोंके मुँहमें अन्न देना ही एकमात्र या प्रधानतम काम नहीं। अकालने मनुष्यकी घरगृहस्थीको तोड़ डाला है; जीवन-व्यवस्था और आर्थिक बुनियाद उलट गयी है। बंगाली लोग दूसरोंके मुहताज भिखमंगोंकी जाति होने चली है। मध्यवित्त श्रेणी और; जिन्हें अनुन्नत श्रेणीका कहा जाता है, उन्हींकी हालत सबसे ज्यादा खराब है। लाखों देशवासियोंकी—खासकर

इन दो श्रेणियोंकी हृदय-मर्यादाको ऊपर उठाकर सभीको समाज-जीवनमें पुनः प्रतिष्ठित करना इस वक्त हमारा व्यापक कर्त्तव्य है ।

बीसवीं सदीके लगभग बीचके हिस्सेमें महीनेपर-महीने क्या चिन्ता-जनक दृश्य आंखोंके सामने हमने देखे हैं ! ऐसी हालत क्या सचमुच ही हो सकती है, भावी युगका मनुष्य यह विश्वास करना न चाहेगा। इस वक्त खेतकी फसल घरमें आ रही है। बद-इन्तजामी और बद-नीति न दिखलाई दी तो अच्छे दिन लौट आयंगे। किन्तु लाखों सुखी घराने एकदम ही बेनिशान हो गये हैं, निरपराध नर-नारीका दल तिलतिल करके सड़कपर पड़े-पड़े मर गया---उनके असहाय विनाशका दृश्य जीवन भर हमारे लिये नयी विभीषिका होकर बना रहेगा।

७७ आशुतोष मुकर्जी रोड,
कलकत्ता। } डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी

बंगालका अकाल

"गहनोंका बटवारा हो जानेपर एक दस्यु बोला—'हम लोग सोना-चाँदी लेकर क्या करेंगे, एक गहना लेकर कोई मुझे मुट्ठी भर चावल दो, भूखसे जान निकल रही है,—आज सिर्फ पेड़के पत्ते खाये हुए हूँ।' एक आदमीके यह बात कहनेपर, सब इसी तरह कह-कहकर लगे रोला मचाने,—चावल दो, चावल दो, भूखसे जान निकल रही है, सोना-चाँदी नहीं चाहिये। सरदार उन लोगों को चुप करने लगा, कोई रुकता नहीं, क्रमशः जोर-जोरसे आवाजें उठने लगीं, गाली गलौज होने लगी, मार-पीटकी नौबत आ गयी। जो-जो गहने बाँटमें आये थे, उन्हें गुस्सेमें अपने सरदारके ऊपर दे मारा। सरदारने दो-एक आदमियोंको पीटा। तब सभी सरदारपर हमलाकर उसपर चोटें करने लगे। सरदार भूखके मारे दुबला और कमज़ोर था ही, दो-एक चोटोंसे भूमिपर गिरकर दम छोड़ दिया। तब भूखे, रुष्ट, उत्तेजित, हतज्ञान, दस्युओंमेंसे एक आदमी बोला,—'सियारने कुत्तोंका मांस खाया है, भूखसे जान निकल रही है, भाई आओ! आज इसी बच्चेको खायें।'......यह कह उन सब भग्नदेह, कृशकाय, प्रेतवत् मूर्तियोंने अन्धेरेमें खल-खल हँसते, तालियाँ बजाते नाचना आरम्भ कर दिया। सरदारके शवका दाह करनेके लिये एक आदमी आग जलानेमें लग गया।"

—आनन्दमठ

बंगालका अकाल

—::※::—

सन् छअत्तर (१८७६) के अकालकी भयावह याद बंगाली भूल नहीं सकते। सन तितालिस (१९४३ ई०) के अकालको भी बंगालका इतिहास चिरकाल तक काले-काले हरफोंमें चित्रित करके रखेगा।

१२ अगस्त सन् १७६५ ई० को क्लाइवने ईस्ट इण्डिया कम्पनीके नामपर बंगाल, बिहार और उड़ीसाकी दीवानी ले ली। देशमें उस समय जो हालत चल रही थी, उसमें और अराजकतामें सिर्फ नामका ही अन्तर था। कई मालिक और असंख्य शासन-विधियां थीं। शोषण तो भरपूर चल ही रहा था, उसपर अवर्षण और अल्प वर्षणके कारण भयंकर अजन्मा और फसलकी हानि हुई। इसीका अवश्यम्भावी परिणाम था सन् १७७० ई० का अकाल। तमाम मुल्क मरघट बन गया। सन् छअत्तरकी थोड़ी-बहुत सफाई दी जा सकती है—अङ्गरेज लोग अपनी जिस शासन-महिमाका दुनियां भरमें ढोल पीटते फिरते हैं, सिर्फ पांच सालके अरसेके भीतर वह तब तक मजबूत होनेका मौका न पा सकी थी।

किन्तु सन १९४३ ई० में इस तरहकी कोई सफाई रुप नहीं सकती। पौने-दो सौ सालसे भी अधिक समय तक प्रचण्ड प्रतापसे श्वेत-राजत्व चला है। बीसवीं सदीने अजस्र सुयोग-सुविधाएं मनुष्यके हाथमें लाकर रख दी हैं; विज्ञानकी करामातसे सारी दुनियाका आपसमें मेलजोल हो चला है। अब भी दूधके अभावमें कितने ही बच्चे मांओंकी गोदमें मर गये। कूड़ेके ढेरसे इन्सानने जानवरोंके साथ छीना-झपटी करके जूठन खाई। यह दृश्य महीने पर महीने हमने अपनी आँखों देखा है।

बंगालके गैरफौजी सिविल सप्लाई मन्त्रीने सन् ४३ के अकालके १२ कारण दिये थे, जो ये हैं—

(१) सन् १९४२ में 'आउस' की फसल अच्छी नहीं हुई।

(२) सन् १९४२-४३ में अमनका धान भी कम फला।

(३) मेदिनीपुर और चौबीस परगनाके जिले तूफानसे क्षतिग्रस्त होनेसे (अनाजका) उत्पादन कम हुआ।

(४) कीड़ोंके ऊधमसे फसल बरबाद हुई।

(५) सरकारी नौका-नियन्त्रण नीतिने आमदरफ्तमें विघ्न उपस्थित किया।

(६) समुद्र तटकी आबादीको खाली करानेके फलस्वरूप खेतीकी उपजमें कमी हुई।

(७) बर्मा और अराकानसे आये हुए लोगोंने बहुत भीड़ जमा दी।

(८) कल-कारखानोंके केन्द्रोंमें दूसरे हिस्सोंसे आये हुए मजदूरोंकी संख्या काफी बढ़ गयी।

(९) बर्मासे चावलका आयात बन्द होनेपर उसकी कमीको दूर करनेका कोई उपाय नहीं किया गया।

(१०) सूबे भरमें बहुतसे हवाई अड्डे बननेसे सब स्थान खेती-बारीके काममें न आ सके।

(११) फौजी लोगोंकी संख्या बहुत बढ़ जानेसे खाद्य पदार्थोंका खर्च भी बढ़ गया।

(१२) अन्य स्थानोंसे खाद्य पदार्थोंकी आमद कम हुई।

४ नवम्बर (१९४३) को पार्लमेंटमें भारत-सम्बन्धी एक बहस हुई थी। उसमें इनफ्लेशन अथवा सिक्केकी वृद्धिको सन् ४३ की भुखमरीका सबसे खास कारण ठहराया गया। सरबराह-सचिवके दिये हुए उपर्युक्त बारह कारणोंमें इसका कहीं उल्लेख भी नहीं। यह साफ ही है कि उन्होंने मामूली कारणोंके ऊपर जोर देकर असली मामलेको दबा दिया है। सरकारने लड़ाईके सिलसिलेमें जो माल खरीदा उसकी कीमत चुकानेमें उसने काफी कागजी नोट बाजारमें छोड़ दिये। जो लोग सरकारी काम करते हैं, लड़ाईका मालमत्ता जुटाते हैं, कल-कारखानोंमें कई तरहके युद्ध-सम्बन्धी सामानको तैयार करते हैं, उन्होंने कागजी नोट भारी तादादमें पाये और उन नोटोंसे बड़ी तेजीके साथ लगे सामान खरीदने। देशके अधिकांश लोगोंने इसके बहुत पहले ही अपेक्षाकृत अच्छे दामोंपर माल बेच दिया। बढ़े हुए सिक्केका हिस्सा उनके पल्ले नहीं पड़ा। चीजें उनकी खरीदके बहुत ही बाहर हो चलीं। लाखों आदमी बिना खाये मरने लगे। सिक्केको बढ़ाने

की नीतिके लिये भारत-सरकार और ब्रिटिश शासन-तन्त्र जवाबदेह हैं। सरबराह-सचिव इस मामलेमें साफगोईसे चलते तो साहस और सत्य-भाषणके लिये उनकी प्रशंसा की जाती।

पार्लमिण्टकी वितर्क-सभामें पेथिक लोरेन्सने कुछ एक खरी-खरी बातें कही थीं। 'जीवित रहनेके लिये जिन खाने-पीनेकी चीजोंकी जरूरत होती है, उन्हें खरीदनेकी ताकत असंख्य लोगोंके पास नहीं। सिक्केकी वृद्धि इस तरहसे ज्यादा मंहगाईका कारण है। इसकी जवाबदेही और किसीके ऊपर न होकर अकेले भारत-सरकारके ही ऊपर है। मि० एमरीने भी सकपकाते हुए इस बातको एक प्रकारसे स्वीकार किया है। उन्होंने कहा, 'समस्या है बेहद मँहगाई और खाने-पीनेके सामानकी प्रचुरता। जन-साधारण के पल्ले खरीदनेको पैसा न था, यह सही है। यह सब होनेपर भी हालत आजकी जैसी शोचनीय न हो सकती थी।'

एक बात ध्यानमें रखनी होगी। पैसा पास होनेसे ही कुछ नहीं बनता। बहुतसे लोग रोजाना जो लाते वही खाते हैं। उनकी हालत चीजोंके क्रमसे बढ़ते हुए दामोंके मेलमें न रह सकी। दाने-दानेको मुंहताज होकर इस हालत वाले लोग बहुत बड़ी संख्यामें मौतके घाट उतर गये। इतने पर भी सिक्केकी बहुतायतको रोकनेके लिये कोई उल्लेखनीय चेष्टा बिलकुल ही नहीं हुई। हालत जब हदसे बाहर हो गयी तब अधिकारी लोग हिले-डुले।

सिविल सप्लाई मन्त्रीके हिसाबसे अन्न नष्ट होनेकी बात भी ठीक नहीं। किसान, मध्यम वर्गके खरीदार, दुकानदार आदिके विरुद्ध अबतक खूब खिलाफत चली है। मि० एमरीके गुटका कहना है कि मालको मुट्ठीमें करके

इन्हीं लोगोंने दुर्भिक्ष की सृष्टि की है। असलमें जहां गड़बड़ी है उस ओरसे इस तरह सबकी नजरोंपर पर्दा डालकर रक्खा गया है। बाजारमें सबसे बड़ी खरीदार खुद सरकार ही है, एवं इसी सरकारके मददगार कल-कारखानों के मालिक और पैसेवाले लोग हैं। जमा किये हुए अनाजमेंसे कितना बरबाद हुआ है, इसका हिसाब कौन देगा? बर्माकी सरहद पर जंगी गोदाममें बेशुमार खाने-पीनेकी सामग्री बरबाद हुई है। भारत-सरकारद्वारा संचित आटा, मैदा, चना, सत्तू आदि किस परिमाणमें नष्ट हुआ, उसका ठीक-ठीक हिसाब मिल सकनेपर वर्त्तमान भुखमरीका बहुत कुछ रहस्य खुल जायगा। कलकत्तेमें ए० आर० पी० के पास 'दुश्मन-दुश्मन' द्वारा आतंकित लोगोंके लिये मामूली परिमाणमें जो चीजें जमा की गयी थीं, उनमें भी बहुत फिजूलखर्ची हुई, यह बात सभीको मालूम है।

अकाल एक ही दिनमें नहीं आता। सरबराह-सचिवने जो ऊपरकी बारह धाराओंको मुख्य कारण बतलाया है, उन्हींसे समझमें आ जायगा कि भयंकर अकालने धीरे-धीरे ही बङ्गालको ग्रास किया है। इसका सामना करनेमें केंद्रीय सरकारने शोचनीय उदासीनता दिखायी है। देश-बिदेशके झुंडके झुंड सिपाहियोंने आकर बङ्गालको भर दिया। हजारों दुश्मनोंको कैदी बनाके लाया गया। उनमेंसे बहुतोंका बोझा बङ्गालके कन्धेपर आ गया। बर्मासे बेशुमार भागे हुए लोग आ जुटे। कल-कारखानोंमें देशके भिन्न-भिन्न हिस्सोंसे असंख्य मजदूर यहां आ गये। केन्द्रीय सरकार अब भी समझे हुए है कि बङ्गाल आसानीसे इन सबके लिये अन्न जुटा देगा, अन्य किसी तरहके ऊपरी बन्दोबस्तकी जरूरत नहीं।

सिपाहियोंका भोजन साधारण लोगोंके मुकाबलेमें बहुत अधिक होता है। खाली चावल ही नहीं—फल-फूल, तरकारी, मछली, अण्डे, मांस आदि भी उन लोगोंके लिये बहुत बड़े परिमाणमें खरीदे जाते हैं। उन सब चीजोंके बढ़े-मूल्य और दुष्प्राप्य होनेसे चावलके ऊपर खिंचाव बढ़ गया। तिसपर सरकार फौजोंके लिये दस लाख टन खाद्य सामग्री हमेशा ही जमा रखने लगी। बड़े-बड़े कारखानोंके मालिक लोग भी लड़ाईकी तिजारतमें बहुत फायदा उठाकर मजदूर और कर्मचारियोंके लिये भविष्यका खाद्य सञ्चय करने लगे। सरकारने पोशीदा तौरसे इनकी सहायता की। जनसाधारणकी बातको किसीने ध्यान नहीं दिया।

दुश्मनके आक्रमणकी आशंकासे कईएक जिलोंसे धान हटा दिया गया। धान हटाते ही स्थानीय लोगोंके पेटकी भूख उसीके साथ लोप तो नहीं हो जाती। खाद्य सामग्रीकी खोजमें वे इधर-उधर फिरने लगे। चावलकी दर एकदम ही बहुत बढ़ गयी। इसके अलावा नावोंको डुबाकर, नावोंकी आमद-रफ्तपर रोक लगाकर जन-साधारणको और भी अधिक भयभीत कर दिया गया। ऐसे लोगोंके मनमें विश्वासको जीवित रखनेकी चेष्टा करना उचित है। सरकार हड़बड़ीमें ऐसे सब अंट-संट काम करने लगी कि साधारण जनता सरकारके ऊपर क्रमशः भरोसा खो बैठी। दुर्भिक्ष देशव्यापी हो उठा।

सन् ७६ के अकालका चित्र बंकिमचन्द्रके 'आनन्दमठ'में दमक रहा है। इस वर्णनमें साहित्यकोचित अतिशयोक्ति बिलकुल भी नहीं। सन् १७७६ ई० में एक अकाल-कमीशन बैठा था। कमीशनने जो रिपोर्ट दी थी, आनन्दमठ का वर्णन उसके किसी-किसी अंशका हूबहू बङ्गला अनुवाद है। 'आनन्दमठ'

के चित्रके साथ आजकी दुर्वस्थाका मिलान करके देखनेसे मालूम होगा कि इस बार भी इतिहासकी पुनरावृत्ति हुई है ।

सन्, ७६ के बाद भी अनेक बार अकाल पड़ा । जैसे :—१७८३, १८६६, १८७३-७४; १८७५-७६, १८८४, १८९१-९२, १८९७ १९०० इत्यादिमें । इनमेंसे सन् १८७३-७४ ई० के अकालके दौरानमें दो करोड़ लोगोंको अन्न-कष्ट हुआ था । किन्तु उस समय जल्दी ही यथायोग्य व्यवस्था की गयी थी । इसीसे उस बार जन-हानि सामान्य ही हुई । दुर्भिक्ष-दमनमें एकमात्र इसी बार सरकारने कुछ कर दिखलाया था । किन्तु सन्, ७३-७४ की व्यवस्था इस बार एकदम उपेक्षित हुई है । बरंच सन् १७७०, १७८३ और १८६६ में अदूरदर्शिता और अव्यवस्थाके फलस्वरूप जो भयावह अवस्था हुई थी, सन्, ४३ के अकालमें ठीक वही बातें दिखलाई दे रही हैं । बेशक आजकी तरह उस समय विदेशी हमलेकी आशंका न थी, इस एक बातके अलावा और सब चारों ओरकी बातें आश्चर्यजनक रूपसे आपसमें मिलती हैं ।

सन् १७७० ई० में अकालकी सम्भावना हुई । वैसे ही अधिकारियोंने 'फौजोंके लिये, ६ महीनेकी खुराक खरीदकर गोदाममें भरनेकी बात सोची'। अक्टूबरके महीनेसे देशमें हाहाकार मचा; नवम्बरके महीनेमें जिसके दो-एक मन अनाज हुआ था, राजकर्मचारियोंने उसे सिपाहियोंके लिये खरीदकर रख लिया ।' इसी नवम्बरके महीनेमें ही 'कलक्टर जनरल'ने आशंका प्रकट की कि देश वीरान हो जायगा ।

सन् १९४३ की अवस्था क्या इसके अनुरूप नहीं ? सरकारी भाषा ही में उद्धृत कर रहा हूं—'हमलेसे देशकी रक्षा करने वालोंकी क्रमसे बढ़ती हुई

आवश्यकताओंके कारण फौजी महकमेकी तरफसे प्रचुर परिमाणमें खाद्य सामग्री खरीदी गयी; इसके अतिरिक्त तंग दिनोंके लिये भी खाद्य सामग्री खरीदनी पड़ी है।'

उस ज़मानेमें चावल संग्रहके ऐसे ही मौकेपर इलाहाबाद और फैज़ाबादके अंगरेज अफसरोंसे कम्पनी चावल न खरीद सकी थी। इस बार भी देखा गया है कि अन्य प्रान्तोंसे, खासकर लाट-शासित सूबोंसे, चावल खरीदनेमें बङ्गाल-सरकार सुविधा न पा सकी।

सन् १८७६ के अकालके बारेमें सन्देह किया गया है कि 'व्यक्तिगत मुनाफाखोरोंका कारबार खूब चला था।' कम्पनीके कर्मचारियोंने ऐसी हालत कर दी कि बाजारमें चावल मिलनेकी कोई राह न रही। देशमें हाहाकार मच गया, प्रतिवाद उठने लगा। यहां तक कि कम्पनीके डाइरेक्टरोंने कर्मचारियोंकी धांधली और अर्थ-लोलुपताकी अजस्र निन्दा की थी। किन्तु उससे कोई नतीजा न निकला।

सन् १९४३ ई० में भी उसी तरह हुआ। चारों ओर प्रचुर कोलाहल उठते ही उठते १५ वीं सितम्बरको सिविल सप्लाई मन्त्रीने स्वीकार किया कि अन्य प्रांतोंका चावल बंगालमें बेचकर सरकारको लाभ हुआ तो सही, फिर भी यह आरम्भमें ही! इत्यादि इत्यादि।

उस ज़मानेमें भी अधिक परिमाणमें माल खरीदने और जमा करनेके खिलाफ हुक्म जारी हुआ था। अन्नके अभावमें लोग मर रहे थे, फिर भी अन्नकी रफ्त चल रही थी। जार्ज टामसनके मतमें 'अकालके समय यदि यह रफतनी बन्द होती तो चावल काम भर पूरा हो जाता—मनुष्य

दस

भूखों न मरते।' यह रफ्तनी कब शुरू हुई थी, यह मालूम नहीं। १४ नवम्बर (१७७०) को अनेक चेष्टाओं के बाद अन्नका निर्यात बन्द कर दिया गया, इतिहासमें यह विवरण विद्यमान है।

इस बार भी अन्न-निर्यातके खिलाफ काफी चिल्ल-पों मची थी, पर अधिकारी-वर्गके कानोंपर जूँ तक न रेंगी। बहुत देरीसे २२ जुलाईके बाद अन्न का निर्यात कुछ हदतक बन्द हुआ, पर एकदम बन्द नहीं हुआ। अब भी कुछेक बातोंके सिलसिलेमें विदेशको चावलका निर्यात हो सकेगा। तब भी सरकारी हिसाबसे हर महीने एक हजार टनके ऊपर न होगा। सरबराह सचिवने सन्, ४३ के अकालके जो सब कारण दिये हैं उनमें इस निर्यातका कोई उल्लेख नहीं।

सन् १७७० ई० के अकालका धक्का बङ्गाल आसानीसे न सम्भाल सका, अभाव चला ही आ रहा था। सन् १७८३ में फिरसे अकाल दिखलाई दिया। इस बार अधिकारियोंने कुछ सुबुद्धिका परिचय यह दिया कि जलमार्ग से खाद्योंका निर्यात एकदम बन्द करवा दिया गया। एक कमेटी तैयार कर उसे दण्ड देनेका चरम अधिकार दे दिया गया। हुक्म जारी किया गया कि अगर कोई व्यवसायी खाने-पीनेकी सामग्री छिपा कर जमा रखे, बाजारमें ले जाकर उचित दामोंमें बेचना अस्वीकार करे, तो उसे कड़ी सजा तो मिलेगी ही, साथ ही उसका माल जप्त करके गरीबोंके बीच बांट दिया जायगा।

सन् १९४३ के अकालके मौकेपर भी इसी तरह हुक्म दिया गया था। नतीजा क्या हुआ कि हजारों आदमियोंने जान गंवायी, यह देखा ही गया है।

सरकारी हुक्मकी बेरोक-टोक और अक्सर व्यापक रूपसे अवहेलना हुई। सरकार भी संशोधनमें हुक्मपर हुक्म निकालती चली गयी!

सन् १७८३ ई० के अकालके मौकेपर एक और उल्लेखनीय प्रस्ताव हुआ था—वह यह कि बङ्गाल और बिहार, इन दोनों सूबोंके लिये एक स्थायी अनाज-गोदाम तैयार किया जायगा। इसके मुताबिक पटनामें पक्की चुनाईका एक विशाल गोलाघर बनाया गया। उसके ऊपर लिखा है—For the perpetual prevention of famines in India (भारतवर्षमें हमेशाको अकाल रोकनेके लिये)। किन्तु गोलाघर हमेशा ही खाली रहा, कभी एक मुट्ठी धान भी उसमें न पड़ा।

इस अकालके मौकेपर भी फूडग्रेन कमेटीने एक केन्द्रीय अनाज-गोदाम तैयार करनेकी सिफारिश की है। इस अनाज-गोदामके लिये पक्की इमारत खड़ी होगी कि नहीं और आखिर इसमें किस परिमाणमें अनाज जमा होगा, यह बात अभी देखनेको है।

सन् १८६६ ई० में जो अकाल पड़ा था, उसे आमतौरपर उड़ीसाका अकाल कहा जाता है। 'सर्वग्राही' दुर्भिक्षके समुद्रमें समूचा उड़ीसा डूब गया था। बङ्गालके मेदिनीपुर, बांकुड़ा, वर्दमान, नदिया, हुगली और मुर्शिदाबाद-के जिलोंतक उसकी लहरें पहुँची थीं। इस अकालके मौकेपर उड़ीसाकी जो हालत कही जाती है, आज बङ्गालकी हालत भी ठीक उसी तरहकी है। देशके एक हिस्सेसे दूसरे हिस्सेतक, रोजाना अनगिनत भूखे लोग मर रहे हैं। सियार और कुत्ते मनुष्यके शवको झिंझोड़ रहे हैं। सिविल सप्लाई मन्त्री बेशक यह कहना चाहते हैं कि बङ्गालके सभी हिस्से अकालग्रस्त नहीं हुए।

किन्तु परदा डालकर सत्यको छिपाया नहीं जा सकता। सन् १८६६ ई० के अकालमें लगभग दस लाख लोग मरे थे। यदि किसी दिन सन् १९४३ ई० के अकालकी सही बातें प्रकट हुईं तो पता चलेगा कि इस बारकी जन-हानि पहलेके सभी दुर्भिक्षोंकी संख्याको बहुत पीछे छोड़ गयी है।

सन् १८६५ ई० में अलग जिलोंके हाकिमोंने कुछ अंशतक खेती उगता देखकर इसकी असली हालत मालूम करनेकी कोशिश की थी। किन्तु लगान माफी देनेकी भी बात हुई। पर कमिश्नरोंने इस बातका समर्थन न किया। रेवेन्यू बोर्डने भी इस तरहका सुझाव रद्द कर दिया। बोर्डने एक लम्बे-चौड़े वक्तव्यमें बङ्गाल-सरकारको बतलाया कि फसल कुछ कम हो सकती है, किन्तु इसमें चिन्ताकी कोई बात नहीं; इस फसलसे लोगोंको खानेभरको मिल ही जायगा; आगामी सालके लिये जमा अवश्य कम हो सकती है, किन्तु अकाल पड़नेकी कोई सम्भावना नहीं।

सन् १९४३ ई० की भी वैसी ही हालत है। बर्माके हाथसे निकल जानेके बाद यह बात चली कि सालके आखिरमें बङ्गालमें अकाल पड़ सकता है। यह बात चलायी भारत-सरकारके खूब मोटी तनख्वाह पानेवाले एक कर्मचारी महोदयने। बस, केवल इतना ही! ३० वीं अप्रैल (१९४३) के अखबारोंमें खबर निकली कि एक आदमीके शवकी चीर-फाड़से पेटके अन्दर घास पायी गयी! भूखके मारे इस अभागेने घास खायी थी, उसे हजम न कर सका। पर इसीके एक हफ्ते बाद (७ वीं मईको) सिविल सप्लाई मन्त्रीने कहा—'इस संकटका समाधान दूर नहीं है।' दूसरे दिन ८ वीं मईको उन्होंने फरमाया 'वास्तवमें बङ्गालके अन्दर यथेष्ट अनाज मौजूद है।' उस समयके

खाद्य-विभागके बड़े हाकिम मेजर जनरल उडने १३ वीं मईको बहुत काफी हिसाब लगाकर यह दिखलाया कि बङ्गालमें कोई अभाव नहीं। केन्द्रीय सरकारके सदस्य माननीय सर अजीज़ुल हकने १५वीं मईको कृष्णनगरमें कहा—"बङ्गालमें अब भी चावलकी कमी नहीं हुई।" ३० वीं तारीखको भी अपर्याप्त खाद्य रह गया है, अथवा खाद्यका आयात कम हो रहा है, यह बात सुहरावर्दी साहब नहीं कह सके।

सन् १८६६ ई० में उस समयके लाट सर सिसिल विडनेकी सरकारने कहा था कि देशमें प्रकृत अन्नाभाव नहीं हुआ; व्यापारियोंके हाथोंमें प्रचुर अनाज है, ऊपरी मुनाफाखोरीके लिये उन लोगोंने वह जमा कर रखा है। सन् १९४२ में बङ्गाल सरकारने कहा—"बङ्गालमें जिस परिमाणमें खाद्य-सामग्री मौजूद है, उसी हिसाबसे महंगाई असङ्गत है। उस मालको बाहर बाजारमें निकाल सकते ही संकट दूर हो जायगा।

सन् १८६६ ई० के मार्चमें बाहरसे चावल मंगवानेकी मांग हुई थी। उस वक्त घरबार छोड़कर लोगोंने इधर-उधर घूमना शुरू कर दिया, जगह-जगह अनाज लूटा जाने लगा। किन्तु सरकार आसन्न संकटका मुकाबला न कर सकी। २८ वीं मार्चको सर आर्थर काटनने अकाल-निवारणके लिये सरकारको खबरदार होनेकी बात कही! अप्रेलके महीनेमें कलकत्तामें चन्दा इकट्ठा करके भूखोंको खिलाये-पिलाये जानेकी व्यवस्था हुई। किन्तु रेवेन्यू बोर्डको तब भी सन्देह ही था कि सचमुच अनाजकी कमी हुई या नहीं। कुछ दिनों बाद चावल एकदम अप्राप्य हो गया। फौज, सरकारी नौकर-चाकर एवं कैदियोंके लिये भी चावल न मिलने लगा। तब लेफ्टनेण्ट गवर्नरने बाहर

से चावल मंगानेका हुक्म दिया। सरकारकी अकर्मण्यतासे इस दुर्भिक्षसे प्रायः दस लाख आदमी मरे। इसके लिये अकाल कमीशनने रेवेन्यू बोर्डको दोषी ठहराया। ११ अगस्त सन् १८६७ ई० को रेवेन्यू बोर्डने गलती स्वीकार करते हुए कहा—"ठीक वक्तसे काममें हाथ न देने एवं जरूरतके मुताबिक काफी इन्तजाम न होनेसे यह महासंकट आ पड़ा। कर्मचारियोंमें अनाड़ी लोग थे, अकालके लक्षण देखते हुए भी वे लोग कुछ समझ न सके। काममें लगनेमें बहुत विलम्ब होनेकी वजहसे ऐसी दशा हुई कि रुपया देनेपर भी अनाज न मिला।" रेवेन्यू बोर्डने स्वीकार किया कि मि० वेविन शाका तार पाते ही यदि काममें जुटा जाता तो असंख्य जानें बच गयी होतीं।

सन् १९४३ ई० के अकालकी भी ठीक यही हालत है। अनाड़ी लोगोंपर भार सौंपनेसे बहुत-सी मुसीबतें आ पड़ीं। एक व्यक्तिको एक कामका भार सौंपा गया। इस विषयकी थोड़ी-सी जानकारी हासिल करनेके पहले ही उस-का तबादला दूसरे महकमेमें कर दिया गया। बंगाल और केन्द्रीय, दोनों सरकारोंने खाद्य-विभागके कर्मचारियोंमें इतना रद्दोबदल किया कि तेजीमें इनके सामने सिनेमाकी तस्वीर भी हार मान जाय! सन् १९३९ ई० के अक्टूबरके महीनेसे लेकर सन् १९४३ ई० के सितम्बरतक केन्द्रीय सरकारने मूल्य-निर्धारणके लिये ६ कानफरेन्सें कीं। सन् १९४२ ई० के दिसम्बर महीनेमें खाद्य-विभागकी सृष्टि हुई। अप्रैल सन १९४२ ई० को फुड एड-वाइजरी कौंसिल हुई। १९४२ ई० को रिजनल फुड कमिश्नर नियुक्त हुए। दो-एक मासके अन्तरसे एकके बाद दूसरे सज्जन फुड-मेम्बर हुए। यह रही

केन्द्रीय सरकारकी हालत । बङ्गालमें कितनी तरहके पट-परिवर्तन हुए हैं, वह सब हम लोगोंने अपनी आंखोंके सामने देखा ही है ।

सरकारी उदासीनताके फलस्वरूप सन् १९४३ ई० की अवस्था ठीक सन् १८६६ ई० की तरह अति शोचनीय हो गयी । रुपया फेंकनेपर भी चावल मिलता नहीं ! चन्दा करके बहुत सारे संगठनोंने भूखोंको खिलाने-पिलानेकी व्यवस्था की । सरकार समझी कि इस तरह कई हजार लोगोंको खाना खिला कर आमलोग शोर मचाना बन्द कर देंगे, उन्हें (सरकार को) मगज मारने की जरूरत न होगी । पेटकी ज्वाला से लोग घर,बार छोड़कर रास्तेपर निकल पड़े हैं, शहर की ओर दौड़ने लगे हैं—अधिकारियों की इस ओर निगाह भी न पड़ी ।

यही अवस्था है सबसे अधिक खतरनाक । गांवोंमें खाद्य पहुंचा देनेसे लोगोंकी घर-गृहस्थी कुछ तो बच रहती । वे लोग कुछ आय कर ही लेते । यथासम्भव शीघ्र स्वावलम्बी होकर फिरसे सिर उठानेकी चाह उनके मनमें जगी रहती । अकाल गांवके लोगोंको भगाकर शहरमें लाता है । जो रहते हैं घर-द्वारवाले, आत्मसम्मान खोकर वे पथके भिखारी बन जाते हैं । सन् १८७८ ई० के अकाल कमीशनमें सर रिचर्ड टेम्पलने इस सम्बन्धमें कहा था, 'खाद्यकी खोजमें मनुष्य घर-द्वार छोड़कर जब चक्कर लगाना शुरू करता है, तो अकाल की वही हालत सबसे ज्यादा डरावनी होती है । इसका परिणाम यह होता है कि लोग चरित्रभ्रष्ट हो जाते हैं । गांवोंमें सुचारु रूपसे सहायताका प्रबन्ध करके इस घूम-फिरको बन्द कर देना चाहिये । कुछेक गांवोंको लेकर

विपत्तिमें उबलता हुआ एक बेबस परिवार।

एमरी साहबकी रायमें, अति-भोजनके कारण ही तो बङ्गालमें खाद्य-सङ्कट आया है !

बेटेका कष्ट असह्य देखकर माँ उसे जिन्दा ही दफ़ना रही थी। सिर्फ सिर उसका ढँका न था, इसी वक्त स्कूलके लड़कोंने आकर उसे बचाया। लड़का कांथी हिन्दू मिशनके आश्रयमें है।
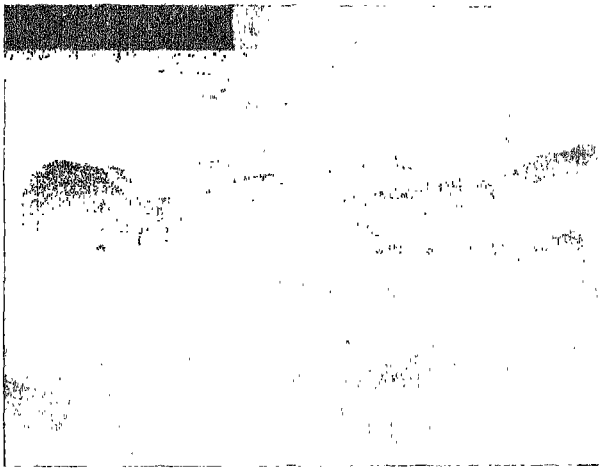
एक सहायता-केन्द्र होगा। ठीक समयपर सहायताकी व्यवस्था करनेसे घूम-फिर बन्द हो जायगी।

सन् १८६६ ई० में भी लोगोंने घर-द्वार छोड़ा था। सन् १९४३ ई० की तरह ही आम सड़कोंपर अधमरी हालतमें लोग पड़े रहते। अगस्तके महीनेकी वर्षामें भींग कर उस बार बहुत से लोग मर गये। झुण्डके झुण्ड अस्थिपंजरवाले मनुष्य लंगरखानेमें इकट्ठे होते। उनके रहनेका कोई ठिकाना न था। सरकारने देखा कि बाहरके लोग आकर शहरके स्वास्थ्यको नष्ट कर रहे हैं। उस समय एक तरहसे जबर्दस्ती शहरके अन्नाशय बन्द करवा दिये गये। निराश्रितोंको बाहर भेज दिया गया। सत्तर सालके बाद उसी घटनाकी पुनारावृत्ति देखनेको मिल रही है; उस बार कलकत्ता शहरमें जो भूखे लोग जमा हुए थे वे १५-१६ हजार होंगे। सन् १९४३ ई० का सरकारी अनुमान एक लाखका है।

इस बार भी पकाया हुआ अन्न बाँटा गया। इस सम्बन्धमें कुछ आपत्ति की गयी थी। कटकके रिलीफ मैनेजर मि० कार्कउड के मतानुसार इस प्रकार सहायता देनेसे इमदाद पाने वालेका नैतिक पतन होता है। यह बात भी ठीक है कि लोगबाग पकाये हुए खानेको छिपाकर बेचनेकी नीयतसे उसका अपव्यय नहीं कर सकते। किन्तु और एक बात सोचने की है। बहुत से परिवार इस रूपमें इमदाद लेते हुए अपमान समझते हैं। वे लोग चुपचाप मृत्युपथके राहगीर बन जाते हैं। सन् १९४३ ई० में भी यह समस्या दिखलाई दी। जो लोग लंगरखानेमें नहीं जा सकते थे, उनको मौतके मुंहसे बचाने के लिये क्या खास इन्तजाम किया गया था?

सत्तरह

सन् १८७३-७४ ई० के अकाल की सुरसुराहट पाते ही सरकार चौकन्नी हो गयी थी। इसीसे उस बार अधिक जनहानि नहीं हो पायी थी। खाद्यकी खोजमें लोगोंके गांव छोड़नेसे पहले ही उन्हें सहायता पहुंच जाय, शरीरकी शक्ति घट जानेसे पहले ही वे काम-काज पा जायँ—बड़ी तेजीके साथ इन बातोंकी व्यवस्था हुई थी। कोई मुंहताज सहायताका पात्र है या नहीं, इस विषयमें स्थानीय लोगोंकी गवाही सबसे अधिक प्रामाणिक होती है। शहरमें सदाव्रत खोलनेसे इस गवाहीका मिलना मुमकिन नहीं होता और बहुत से अंटसंट लोग इमदाद पा जाते हैं, जहां अधिकांश लोग सेवाकेन्द्रोंमें पहुंच भी नहीं पाते। इस प्रकार कोई गोलमाल न हो, इस बातके लिये उस वक्तके छोटे लाट सर जार्ज केम्पबेल इस विषयमें विशेषकर उद्योगशील हुए थे। लोगोंको घर-घर ही रोककर नामवार और गाँवके सिलसिलेसे न बाँटे बिना सुसंगठित सहायता असम्भव है, यह उनका मत था। पचासमेंसे इक्कीस गाँवोंको लेकर एक-एक सहायता-केन्द्र खोला गया, सारे बंगालको इसी प्रकार अलग-अलग हिस्सोंमें बाँट दिया गया। हरेक केन्द्रमें एक बड़ा अनाज-गोदाम कायम हुआ। वहाँसे गांवोंके अनाज-गोदाममें अनाज भेजा जाता था। एक जिम्मेदार कर्मचारी हर हफ्ते काम-काज की जांचपड़ताल करता था। सन् १८७३-७४ ई० के दुर्भिक्ष-दमनकी इस चेष्टाको सब दृष्टियोंसे आदर्श कोटिका कहा जा सकता है। पर मौजूदा अकालमें इसकी एकदम ही अवहेलना हुई है।

किन्तु सेवाकी इतनी सुव्यवस्थाके बीच भी चावलका निर्यात होता रहा। सर जार्ज कैम्पबेलने इसका बड़ा विरोध किया था। १२ अक्तूबर (१८७३) को आनेवाली मुसीबतके सम्बन्धमें उन्होंने भारत-सरकारको सतर्क कर यह

अनुरोध किया—(१) बिना देरी किये इमदाद देनेका कार्य शुरू किया जाय, (२) बाहरसे चावल मंगानेका बन्दोबस्त हो, एवं (३) भारतवर्षसे चावलका निर्यात एकदम बन्द कर दिया जाय। बड़े लाट चावलका निर्यात बन्द करने पर राजी न हुए। सेक्रेटरी आव स्टेटको उन्होंने अपने एतराजकी बाबत सूचित किया। जो भारतीय कुली मौरिशस और ईस्ट इण्डीज, लंका तथा अन्यान्य देशोंमें हैं, (अधिकांशमें योरोपियन मालिकों के बागीचोंमें काम करने को) चावलका निर्यात बन्द करनेसे उनका क्या होगा? सन् १९४३ ई० में ठीक इसीकी प्रतिध्वनि सुनी गयी। लंकाके भारतीय कुली, भूमध्य सागरके भारतीय फौजी—उन सभीकी बात हमीको सोचनी पड़ती है। सन १८७३-७४ की सुव्यवस्था कुछ भी रही, वह इस बार बिलकुल ही ग्रहण न की गयी; केवल उस बारकी चावल-निर्यात नीति बहाल रखी गयी।

बंगालका संकट

—:•:—

आज एक विराट् जातीय संकटसे हमारा मुकाबला है। सरकारी प्रमुख वक्ताओंमें से किन्हीं-किन्हींकी ओरसे यह बात घुमा-फिराकर कहनेकी चेष्टा हुई हैं कि भूतपूर्व मन्त्रिमण्डलकी करतूतोंकी बदौलत ही मौजूदा मुसीबत आयी है। उस मन्त्रिमण्डलके दोष-गुणके सम्बन्धमें लम्बी-चौड़ी आलोचना करनेकी मेरी इच्छा नहीं। किन्तु एक बात तो हम सभीके सामने जाहिर है। भूतपूर्व मन्त्रिमण्डलने खाद्य-समस्याको हल करनेके लिये अकपट चेष्टा की थी। जहाँ उनकी चेष्टा सफल न हुई वहाँ उन्होंने इसका कारण बंगालके आम लोगों या धारा-सभासे छिपाकर नहीं रखा। बंगालमें ऐसी अनेक बातें गुजरी हैं, जिसके लिये मन्त्रियोंकी कुछ भी जिम्मेदारी न थी। एक ओर भारत-सरकारकी नीति एवं दूसरी ओर गवर्नरकी दस्तन्दाजी और अड़ंगेबाजी ही उसके लिये जिम्मेदार हैं। उदाहरणार्थ, अपसारण-नीति याने भारतवर्षसे बाहर अनाजकी रवानगी एवं भारत-सरकारकी ओरसे चावल खरीदनेके विषय का उल्लेख किया जा सकता है।

उस वक्त हफ्तेपर-हफ्ते और महीनेपर-महीने कठोर आशंकाके बीच

बीत रहे थे। अधिकारी लोग समझे कि बर्माको जीतनेके बाद जापान बंगालपर चढ़ाई करेगा। दुश्मनको असुविधामें डालनेके लिये समुद्रतटके हिस्सोंसे नावों और दूसरी सवारियों तथा चावलको हटाना बहुत ही जरूरी था। तबके प्रधान मन्त्री फजलुल हक साहबने साफ-साफ कहा था कि गवर्नर और कुछेक स्थायी कर्मचारी अड़ङ्गा लगानेके मनोभावको लेकर कार्य कर रहे हैं। इसके फलस्वरूप मन्त्रिमण्डल द्वारा ग्रहण की हुई नीतिको कार्यरूपमें लाना नामुमकिन है। सिविल सप्लाई विभागको इस बातपर नाज़ है कि उस महकमेमें ख्यातनामा हिन्दुस्तानी कर्मचारी हैं। भूतपूर्व मन्त्रि-मण्डलने जब इस महकमेमें भारतीय कर्मचारी लेनेकी चेष्टा की तो गवर्नरने अपने विशेष अधिकारोंके बलपर उसे रद्द कर दिया। इस महकमेमें कोई बड़ा पद यूरोपियनोंको छोड़ अन्य किसीको भी देनेपर वह राजी न थे। उन सब कर्मचारियोंके खिलाफ व्यक्तिगत रूपमें मुझे कुछ नहीं कहना है। पर यह बात मानी नहीं जा सकती कि उन्होंने जिस नीतिको चलानेकी चेष्टा की थी, वह सरासर असफल हुई है। वही कर्मचारी अब भी अपने-अपने पदों पर कायम हैं—किसी-किसीकी तरक्की भी हुई है। किन्तु बंगालमें उन्होंने जो डरावनी हालत पैदा की है, उसका हिसाब लगाकर देखेगा कौन? सिविल सप्लाईज महकमेको चलानेके लिये हाईकोर्टसे एक जजको लाया गया। उन्होंने जल्दी ही अपनी जगहपर लौटकर आरामकी साँस ली।

भूतपूर्व मन्त्रिमण्डलने क्या-क्या किया था और वह क्या-क्या करने पाया, आज यह आलोचना प्रासंगिक नहीं। पिछले मार्चके महीनेमें धारा-सभाके अधिवेशनमें उसीके ऊपर आक्रमण जारी हुआ। आक्रमणका मुख्य

अब था खाद्य-समस्याको सुलझानेमें उक्त मन्त्रिमण्डलकी तथाकथित असमर्थता। मौजूदा मन्त्रिमण्डलने उस विषयमें क्या किया है, मैं आज वही सवाल पूछता हूँ। अधिकार पानेके आरम्भसे लेकर इस मन्त्रिमण्डलने जो मौका पाया, उसका पूरा-पूरा उपयोग हुआ है या नहीं, एवं इस सूबेके व्यापक हितोंको ध्यानमें रखकर इसने काम किया है या नहीं, इस बातपर निष्पक्ष भावसे विचार कर देखनेकी आवश्यकता है।

सिविल सप्लाइज़ मन्त्रीने नया पद पानेके बाद वक्तव्यपर-वक्तव्य निकाले हैं। इस सम्बन्धमें मुझे दो-एक बातें कहनी हैं। भूतपूर्व मन्त्रिमण्डलने कमसे-कम एक बड़ा काम किया था—बंगालमें खाद्य-सामग्रीका अभाव है, इस बातकी उन्होंने मुक्तकण्ठसे घोषणा की थी। केन्द्रीय सरकारके द्वारा उन्होंने स्वीकार करवाया था कि खाद्य-पदार्थोंकी कमीसे सूबेको एक बड़ी समस्याका मुकाबला करना पड़ रहा है। यह पिछले मार्चकी बात है। अप्रैलके महीनेमें सुहरावर्दी साहबने सिविल सप्लाइज महकमेका भार पाया। मनोरम भाषामें उन्होंने बहुतसे वक्तव्य दिये हैं। नये मन्त्रिमण्डलकी ओरसे भी दूसरे-दूसरे बहुत-से वक्तव्य प्रकाशित हुए हैं। उन सब बयानोंको मैंने गौरके साथ पढ़ा है।

बंगालमें खाद्यकी कमी नहीं, चावलका अभाव नहीं;—वितरण-व्यवस्थाके दोषसे छोटे-छोटे जमाखोर, साधारण गृहस्थ और किसानोंकी गलतीसे शोचनीय अवस्था आ पड़ी है—इसी बातकी बार-बार घोषणा करके बंगालके अभागे निवासियोंके साथ सिविल-सप्लाइज मन्त्रीने बड़ी ठगैती की है। उन्होंने ऐसा क्यों किया, यह भगवान ही जाने!

सुहरावर्दी साहबने एक बयानमें कहा है कि भूतपूर्व मन्त्रिमण्डल खाद्य सामग्रीकी कमीकी ओर ही जोर देता था ; उसकी खाद्य-नीतिका यह दोषपूर्ण अंश है। यह १७ मईकी बात है। सिविल-सप्लाइज मन्त्रीने कहा है कि यथार्थमें बंगालके रहनेवालोंको जरूरतको पूरा करने लायक काफी खाद्य-सामग्री मौजूद है। हमारे विरोधी सदस्यगण मन्त्रिमण्डलका समर्थन करनेके लिये बेताब होकर बैठे हैं। हमारा अनुरोध है कि वे इस सम्बन्धमें सुहरावर्दी साहबसे सफाईकी मांग करें। किस बातपर भरोसा रखकर उन्होंने यह कहा था कि बंगालके निवासियोंके लिये काफी खाद्य-सामग्री मौजूद है ? सुहरावर्दी साहबने और भी यह फरमाया कि इस सिलसिलेमें विस्तृत हिसाबके आँकड़े जल्दी ही प्रकाशित किये जायँगे। उससे साफ-साफ साबित हो जायगा कि खाद्य-सामग्रीकी प्रचुरता है। कहाँ है वह हिसाब ?

बंगाल सरकारकी ओरसे बंगला और अङ्गरेजीमें निम्नलिखित रूपमें एक वक्तव्य प्रकाशित हुआ :—

आवेदन और सतर्कवाणी।

An Appeal and a Warning.

दरिद्र जन-साधारणका उत्पीड़न अब न चल सकेगा।

You must not grind the faces of the poor.

सुहरावर्दी साहब किसको सम्बोधन कर यह बात कह रहे हैं ? बंगालके लोगोंको ? नहीं, आइने के सामने खड़े होकर क्या खुद अपने-आपको ही सम्बोधन कर रहे हैं ?

सचमुच ही क्या बंगालके अन्दर खाद्य-सामग्रीकी कमी हुई है ? नहीं, कदापि नहीं।

Is there a real shortage of food in Bengal? No, most certainly no.

सामानके बढ़े-चढ़े दाम एवं लाखों आदमियोंकी अवर्णनीय दुर्गति होते हुए भी सुहरावर्दी साहब फरमाते हैं कि अनाजका स्वाभाविक अभाव नहीं है। वे कहते हैं—

तो असल बात है क्या? इस सालके आखिर तक हमारे अभावको मिटानेके लिये काफी परिमाणमें खाद्य हमारे पास था एवं उसके अलावा अन्यान्य हिस्सोंसे आज तक काफी परिमाणमें खाद्य सामग्री आ रही है। आढ़ती, व्यवसायी, खुशहाल किसान एवं और भी बहुतोंने आतंकवश अथवा जनसाधारणका बेरहमीके साथ शोषण करनेके इरादेसे, प्रचुर अनाज छिपाकर जमा कर लिया है और अब भी कर रहे हैं।

वर्त्तमान मन्त्रिमण्डल द्वारा सरकारी हैसियतसे जो सब कागजात प्रकाशित हुए हैं, उपरोक्त वक्तव्य उनमें अन्यतम है। खाद्य सामग्रीका अभाव नहीं, काफी अन्न-राशि जमा है, देशके लोग ही अपनी दुःख-दुर्गतिको लानेके लिये जवाबदेह हैं—है सिर्फ यही बात!

बड़े-बड़े जमाखोर, बड़े-बड़े आढ़तदार या बड़े-बड़े मुनाफाखोरोंके जमा मालकी खोज नहीं की गयी। एकदम मामूली गृहस्थ और किसानोंके खिलाफ मामला चलाया गया। उन्हींने तो दरिद्र जन-साधारणको उत्पीड़ित किया है! उन्हींके ऊपर धावा बोल दिया गया! गवर्नर और स्थायी सरकारी कर्मचारियोंके कृपाभाजन बंगालके नवीन मन्त्रिमण्डलने ज्यों ही यह घोषणा की, प्रायः उसीके साथ-साथ विलायतमें कामन्स-सभाके अन्दर भी इसीके अनुरूप बातें कही गयीं। मि० एमरीने कहा कि भारतवर्ष एवं बंगालमें कुछ

गड़बड़ी हुई है जरूर, किन्तु मुल्कमें अनाजका अभाव नहीं। लोग अनाज जमा कर रहे हैं और वितरणकी अव्यवस्था है। सरकार इस समस्याके बारेमें व्यवस्था कर रही है।

बंगालके मंत्रिमण्डलने यह जो चित्र अंकित किया तो ब्रिटिश सरकारके प्रतिनिधि इसे हाथमें कर पार्लमेंटमें दुनियाके सामने यह घोषणा कर सके कि पूर्वीय युद्ध-भूमिके प्रान्तवर्ती बंगालमें एक गुरुतर परिस्थिति उठ खड़ी हुई है—दिल्ली और कलकत्ता की सरकारों द्वारा बर्ती हुई किसी गलत नीतिके कारण यह नहीं हुआ। अधिवासी लोग ही खुदगर्ज हैं। उनके द्वारा अड्डा लगानेकी वृत्तिका अवलंबन होनेसे ही यह अनर्थ हुआ है।

सुहरावर्दी साहबने घोषणा की कि बंगालमें काफी खाद्य है; उनका काम है इस खाद्य-संचयको ढूंढ़ निकालना। भाषणमें उन्होंने घोषणा की कि चावलको बाहर निकालनेके लिये जरूरत होनेपर वे खुद गृहस्थोंके तख्तपोशके नीचे प्रवेश करेंगे। रातमें क्या, यहाँ तक कि दिनके वक्त भी यदि सुहरावर्दी सचमुच ही गृहस्थोंके घरमें घुसकर तख्तपोशके नीचे जाना आरम्भ करें तो! मुझे मालूम है, बहुतसे गृहस्थ यह खबर सुनकर भयभीत हो उठे थे। जगदीश्वर गृहस्थोंकी रक्षा करें! जिससे लाखों देशवासियोंका जीवन विपन्न हुआ है, उस समस्याको लेकर इससे अधिक बेसमझ आचरण और हो ही क्या सकता है?

सुहरावर्दी साहबने और भी कारण दिखलाया है। उन्होंने कहा है कि समस्या मनोविज्ञानसे सम्बन्ध रखती है। विकृत मनस्तत्त्वपर उन्होंने कब

सबक लिया था, मुझे यह मालूम नहीं ; वर्ना उनका स्थान कलकत्तेमें न हो कर रांची होना उचित था।

समस्या मनोविज्ञान-सम्बन्धित है ! अतएव कौन-सी व्यवस्था ग्रहण की जायगी ? लोगोंको खाली यह कहना होगा, 'आतंकग्रस्त न होना। मैं सिविल-सप्लाइज विभागमें मंत्री होकर बैठा हूं। तुम लोगोंसे कहता हूं—तुम लोगोंसे कहता हूं कि काफी अनाज मौजूद है ! हमारे पास हिसाब के आँकड़े हैं—उन्हें प्रकाशित करने की हमारी इच्छा नहीं। सब ठीक हो जायगा। भयभीत न होना।' सरकारी मुखियाके रूपमें शायद उन्होंने जनताको भरोसा दिलाने की चेष्टा करना प्रयोजनीय समझा हो; किन्तु राइटर्स बिल्डिंग * से केवल इसी तरह जादूकी लकड़ी घुमाकर ही क्या वह कामयाबी हासिल करना चाहते हैं ?

अन्यान्य दलोंसे सलाह-मशवरेकी जरूरत न हुई; वे केवल मनोविज्ञानकी बात और कुछ ढिलाईके साथ सहयोगकी बात कहने लगे। लोकमतका समर्थन उन्होंने न माँगा। अकपट भावसे सबके सहयोगकी कामना उन्होंने नहीं की। दलबन्दीकी नीतिको वे लाँघ न सके। १७ मईको विभिन्न दलोंके नेताओंको बुलाया गया। सभीने (मन्त्रिमण्डलकी प्रशंसामें मुखर यूरोपियन दल तक) इस बातकी माँग की कि कोई मत प्रकट करनेके पहले सरकारका सारा कार्यक्रम नेताओंके सामने उपस्थित किया जाय। सिविल सप्लाइज मन्त्री और प्रधान मन्त्री, दोनोंने वचन दिया कि जिस मसौदेपर सरकार विचार कर रही है, उसकी नकल विभिन्न दलोंके नेताओंको दी जायगी। इसके

* कलकत्तेमें बंगाल सरकारका सेक्रेटरियट भवन !

बाद दिनपर-दिन और हफ्तेपर-हफ्ते बीत चले। नितान्त अनाड़ी और निकम्मे लोगों द्वारा परिचालित खाद्य-आन्दोलन कार्यतः आरम्भ होनेके कुछ ही दिन पहले अचानक विभिन्न दलोंके नेताओंको सभा-भवनमें बुलाया गया। इसी बीच हमलोगोंको मुफस्सल शहरोंमें जाना पड़ा। वहां अन्य लोगोंने सरकारी मसौदेकी नकल हमारे हाथमें दी। यह उन्हीं लोगोंको दी गयी थी। ८ वीं अथवा ९ वीं जूनसे उस मसौदेके अनुसार काम होगा—इस उपदेशके साथ यह सारे सूबे भरमें बाँटी गयी थी। खाद्य आन्दोलनके जब शुरू होनेकी बात थी, उसके कुछेक दिन पहले विभिन्न दलोंके नेताओं और मन्त्रियोंके बीच विचार-विनिमयका यह स्वांग रचा गया!

इस खाद्य-आन्दोलनके मसौदेके विस्तृत विवरण द्वारा मैं परिषद्को परे-शान नहीं करना चाहता। देशमें ऐसा कोई भी नहीं कि जो जमा अनाजका हिसाब लेनेमें कोई आपत्ति करे। वस्तुतः यह हिसाब बहुत पहले ही ले लेना उचित था। भूतपूर्व मन्त्रिमण्डलने यही उसूल सामने रखा था। गवर्नरने वह उसूल रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि इस बातका प्रयोजन नहीं। बङ्गालके समुद्र-तटके हिस्सोंसे किश्तियों और चावलको हटा देनेका ज्यादा जरूरी काम पड़ा है, वर्ना जापानियोंके आ पड़नेपर उस सारी सम्पत्तिकी उन्हें सहूलियत मिलेगी।

खाली अगर हिसाब लेनेकी बात होती तो उसमें कोई आपत्तिका कारण न होता। किन्तु जैसा कि विचार किया गया था, हिसाब ग्रहणकी अपेक्षा उसकी व्यापकता बहुत ज्यादा थी। बंगालके एक सुदूर कोनेसे मुझे आज सुबह ही एक बंगला इश्तहार मिला है। जिस मसौदेके लिये सुहरावर्दी

साहबका मौलिकताका दावा है, यह इश्तहार ही है उसकी बुनियाद। नया मन्त्रिमण्डल कायम होनेके पहले ही ग्राम-सुधार महकमेकी ओरसे मि० इसहाकके हस्ताक्षरोंपर एक सर्कुलर प्रकाशित हुआ। कई दिनोंके बाद विचार करके मन्त्रिमण्डलने बंगालके अधिवासियोंके उपकारार्थ जिस मसौदेको ईजाद किया है—देखते क्या हैं कि इसी सर्कुलरसे उसकी उत्पत्ति है! केवल एक बातमें सुहरावर्दी साहबकी विशेषता है। उन्होंने हुक्म दिया है कि दाल और धानका हिसाब लगाते समय दरिद्र परिवारके चार सालसे कम उम्रवाले लड़के-लड़कियोंको छोड़ देना होगा। वे भात नहीं खाते, यह मान लिया जायगा। सुहरावर्दी साहब क्या इस सीधी-सी बातको भी नहीं जानते कि 'हारलिक्स मिल्क' अथवा अमीर घरोंवाली और कोई बच्चोंकी गिज़ा गरीबों के लड़कोंको नसीब नहीं होती? पर ग्राम-सुधार महकमेके डाइरेक्टर मि० इसहाकने तो चार सालके लड़के-लड़कियोंकी गिनती की थी। सुहरावर्दी साहबके मसौदेमें बच्चोंके लिये सचमुचमें लंघन ही रखनेकी व्यवस्था हुई थी।

खाद्य-आन्दोलनका नतीजा क्या रहा? शुरूसे ही हमलोग कह रहे थे कि अत्यन्त कीमती समयकी भोंड़ी बरबादीके अलावा इस आन्दोलनसे और कोई लाभ न होगा। भारत-रक्षा कानूनके अनुसार एक हुक्म जारी किया गया कि स्वराष्ट्र-विभागके सामने जाँचके लिये पेश न हुए बिना कोई अखबार खाद्य-आन्दोलनके सम्बन्धमें सम्पादकीय राय जाहिर न कर सकेगा। मि० सिद्दिकीके शब्दोंमें 'जो लोग स्वाधीनताको बाधामुक्त कर रहे हैं' —यह उनकी करतूतोंका एक नमूना है। जो कोई मसौदेकी बुनियादी कमीको बतलाना चाहते हैं, इस तरह उनका मुख बन्द कर दिया गया। सभामें हमने सरकारी

कर्मचारियों और सुहरावर्दी साहबसे सवाल किया था कि मन्त्रिमण्डल सचमुचमें करना क्या चाहता है, जिसको लेकर यह हो-हल्ला हुआ है ? वह मसौदा वास्तवमें है क्या ? (आजकी) कमीको पूरा किया जायगा, इस तरहका कोई वायदा उस परिकल्पनाके अन्दर न था। एक जगह मन्त्रिमण्डलने कहा है कि गांवोंको वे स्वावलम्बी बनाना चाहते हैं—स्थानीय स्वावलम्बनकी स्थापना ही उनका उद्देश्य है। स्थानीय जरूरतोंको पूरा किये बिना किसी भी जगहसे वह (मन्त्रिमण्डल) दाल और चावल दूसरी जगह नहीं भेजना चाहता। किन्तु साथ ही साथ यह भी देखता हूं कि धनी व्यवसायी और मुनाफाखोरोंको बङ्गालमें हर जगह बे-रोक-टोक अपना काम चलाते रहनेकी राय दी जा रही है। गीधोंकी तरह ये सब व्यवसायी और मुनाफाखोर विचरण करने लगे। भारत-रक्षा कानून बढ़ता जायगा, जबर्दस्ती चावल रोका जायगा—इसी तरहकी अनेक आशंकाओंसे भयभीत लोगोंने जो चावल बाहर निकाला, तो ये लोग उसको बड़े-बड़े दामोंपर खरीदकर कलकत्तेके इलाकेमें ले आये। नतीजा यह हुआ कि गांवोंमें जो चावल मिल रहा था, या मिल सकता था, वह वहांसे हट गया। गांवोंका सारा इलाका इस तरह चावल-रहित हो गया। सिवाय कागजी कार्यवाहीके कमीको दूर करनेकी चेष्टा ही न हुई। सुहरावर्दी साहबने अपने वक्तव्यमें कहा है कि खाद्य-आन्दोलनके फलस्वरूप दाम बहुत नीचे आ गये हैं। इस तरहके तीन वक्तव्य प्रकाशित हुए थे। पर जब चावल लोप होने लगा तो और तेजीके साथ दाम बढ़ने लगे। तब उन सभी वक्तव्यों का भी खातमा हो गया। पिछले एक पखवारे भर भावके बारेमें चुप्पी साधकर सुहरावर्दी साहबने बुद्धिमत्ताका परिचय दिया है। अभी तक बंगाल

के सब हिस्सोंसे मेरे पास खबरें नहीं आयीं। किन्तु यथोचित जिम्मेदारीके साथ मैं यह कह सकता हूं कि २१ जुलाई १९४३ ई० के आसपास चावलका जो भाव था, ८ जुलाई तक उससे फी मन ३) रु० से ५) रु० तक बढ़ गया था। शिलिगुड़ीमें ४॥), रङ्गपुरमें ४), मानिकगञ्जमें ४), मैमनसिंहमें ४), नेत्रकोनामें ६), जसोहरमें ५॥), खुलनामें ५) और सातक्षीरायमें ५) तक बढ़ गया था। अन्यान्य स्थानोंकी भी प्रायः यही हालत थी। खाद्य-आन्दोलनसे हमें यही लाभ हुआ।

कलकत्ता और हवड़ाको इस आन्दोलनसे अलग रखा गया? मन्त्रि-मण्डल अगर अकपट इच्छा लेकर जी-जानसे काममें लगता तो कलकत्ता और हवड़ामें ही सबसे पहले काम शुरू होता। इसपहानी कम्पनी और अन्यान्य सभी मुनाफाखोरोंके जमा मालका हिसाब किस वजहसे नहीं लिया गया? सिविल सप्लाइज मन्त्रीने ही कहा है कि इस हिस्सेके गरीब निवासियोंके लिये इसपहानी कम्पनीने चालीस लाख रुपयेके मुनाफेको छोड़ दिया है। इसी तरह से और भी अनेक यूरोपियन और भारतीय व्यवसायी-मण्डल हो सकते हैं। खाद्य-आन्दोलनके समय क्यों ये लोग अलग छूट गये?

कारण यह है कि उन सब व्यवसायी-मण्डलोंको हाथ लगाना आसान नहीं। ऐसी बहुत-सी जगहें हैं, जिनके नजदीक जानेका दुर्दान्त प्रताप सुहरावर्दी साहब के बूतेका नहीं। मन्त्रिमंडलके अस्तित्वको कायम रखनेके लिये इन्हींके ऊपर निर्भर रहना पड़ रहा है। तभी तो आन्दोलन प्रधानतः दरिद्र गृहस्थों और किसानोंके खिलाफ चला। अब जरूर कलकत्तेका हिसाब लेनेकी बात कहना एकदम निरर्थक है। सुहरावर्दी साहबके ही एक हिमायतीने एक इश्तहारमें

कहा है कि अगर कलकत्तेमें अन्न खाद्य-आन्दोलन चलाया जाय तो उससे सत्यका संधान नहीं मिल सकेगा। इस बीच ही चावल वहांसे अन्यत्र हट जायगा।

अनाजकी कमीकी बावत सुहरावर्दी साहबने हमें कोई खबर नहीं दी। वह कह रहे हैं कि अब भी तथ्योंका संग्रह पूरा नहीं हो पाया है। यह तथ्य कभी भी प्रकाशित नहीं होंगे। कारण यह कि उनसे हरेक हिस्सेमें भारी कमीका विवरण प्रकट हो जायगा। उन्होंने फरमाया है कि जहांतक खबर मिली है, साठ-सत्तर लाख मन दाल और चावल हस्तगत हुए हैं। यह हिसाब बिलकुल ही यकीनके लायक नहीं; कारण कि इसमें कमीका हिसाब शामिल नहीं है। किन्तु वह चाहे हो भी, उन्होंने जिस परिमाणका उल्लेख किया है, उसमें क्या गलती नहीं है? आशा है, सुहराबर्दी साहब जवाब देते वक्त अपने वक्तव्य की फिर जांच करवा लेंगे। कुछ ही दिन पहले कलकत्तेके एक अखबारमें कहा गया कि दाल और चावलका परिमाण आठ-नौ लाख मन होगा, साठ-सत्तर नहीं। साठ-सत्तर लाख और आठ-नौ लाखके बीच बड़ा फर्क है। किन्तु सत्तर लाख मन भी अगर हो तो इसपर भी मि० डेविड हेनड्रीने जैसा कहा था यह है बंगालके रहने वालोंका सिर्फ पन्द्रह दिनका खाना; यह भी जब किसी हिस्सेमें अनाजकी कुछ भी कमी न हो। इसके बाद क्या होगा? सुहरावर्दी साहबसे मैं इसी बादकी हालतकी बात पूछता हूँ। उनके यह कार्य-क्रम ग्रहण करनेके पहले हमने उन्हें खबरदार कर दिया था कि खाद्य आन्दोलन में जमा मालमेंसे लोगोंकी जरूरतोंके मुताबिक अनाज कदापि बाहर न निकलेगा। हमने कहा था, 'आपलोग अपना उत्तरदायित्व टालकर सारी

जिम्मेदारी आमलोगोंके ऊपर लाद रहे हैं। इस बातमें असफल होनेके बाद आपलोग क्या करेंगे?' वह कहते हैं—"यह मैं नहीं जानता।"

[मि० सुहरावर्दीने कहा कि यह बात उन्होंने नहीं कही।]

आपने जरूर कहा है, "मैं नहीं जानता!" आप अगर उस बातको वापस लेना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं।

[मि० सुहरावर्दीने कहा कि बादमें क्या किया जायगा, यह बात वे नहीं जानते—उन्होंने यही बात कही थी।]

वह स्वीकार करते हैं कि बादमें क्या किया जायगा, इसे वे जानते नहीं। आन्दोलन असफल होनेके बाद कौन-सी व्यवस्थाका अवलंबन करेंगे, इस सम्बन्धमें कुछ भी ठीक निश्चय न किये बिना ही किसी जिम्मेदार मंत्रीके लिये इस प्रकारके कार्यक्रमको ग्रहण कर लेना क्या उचित था? इसी प्रकार क्या वे अपनी जिम्मेदारीका पालन किया करते हैं?

[मि० सुहरावर्दीको अस्पष्ट तौरपर कुछ कहते हुए सुना गया।]

इस तरह कुछ कहनेसे कोई फायदा नहीं। यदि सुहरावर्दी साहब कहें कि खाद्य-आन्दोलनके असफल होनेपर कौन-सा रास्ता पकड़ा जायगा, इसे वह नहीं जानते थे, तो मैं कहूंगा कि वे जिम्मेदारीसे कन्नी काट गये हैं। अपने पदपर बने रहनेकी योग्यता उनमें नहीं!

मंत्रिमण्डलकी रचनात्मक कार्यवाही अर्थात् उत्तर-पूर्व भारतमें फैले अबाध वाणिज्यमंडल की बात मैं अब कुछ कहूँगा। सुहरावर्दी साहबने इसको बड़ी भारी जीत बतलाया है। सर नाजीमुद्दीनने और भी बातका फैलाव करके कहा, 'हमने पूर्व भारतमें अबाध-वाणिज्यका अधिकार पाया है।' बंगालमें एक दाना

चावल न लाकर ही अथवा आम लोगोंका रत्तीभर भी उपकार न करके ही आज वही अबाध-वाणिज्य लोप होने चला है। अवश्य इसी सुयोगसे सुहरावर्दी साहब रहस्यमय शर्तपर इस्पहानी साहबको बंगाल-सरकारकी ओरसे एकमात्र खरीददार नियुक्त कर पाये हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि टिकाऊ उसूलोंकी कमी, हड़बड़ी एवं खास-खास लोगों और व्यापारी-संस्थाओंको सहूलियतें देनेके आग्रहमें मंत्रिमण्डल अवाध-वाणिज्यके सौदेका सुयोग ग्रहण न कर सका। वह (मंत्रिमण्डल) बिसमिल्ला ही गलत कर गया। बंगालकी सेवा करनेका एक बड़ा अवसर वह इस तरह चूक गया है।

बिहार और उड़ीसाके सम्बन्धमें सुहरावर्दी साहबने क्या किया है? सभा-भवनमें मिजाज बिगाड़नेसे फायदा नहीं। उन्हें उत्तर देना ही होगा। मैंने ठोस बातें सामने रखी हैं। उन्हें भी तथ्यपूर्ण उत्तर देना होगा। सुहरावर्दी साहबने बिहार और उड़ीसा-सरकारसे क्यों सलाह-मशवरा नहीं किया? माल-दार व्यापारियों और दूसरे-दूसरे गैर-सरकारी लोगोंको उन्होंने चावल खरीदने की पूरी-पूरी आजादी देकर रवाना किया था। नतीजा क्या रहा? चावलका भाव वहां पर ६), ८) व १०) रुपये से लेकर १५) और १८) रु० के बीचतकका था। किसी भी भावपर चावल खरीदनेके लिये काफी रुपया लेकर बंगालसे लोग चले। अकाल भी साथ-साथ दावानलकी तरह बंगालसे उड़ीसा और बिहारमें फैल गया। बंगालके मंत्रि-मण्डल और उड़ीसाके मंत्रि-मंडलके व्यवहारमें अवश्य अन्तर है। उड़ीसाके मंत्रीने साहसके साथ भयंकर अवस्थाको स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि अकालके कारण सिर्फ एक ही जिलेमें (बालेश्वर) एक पखवारेके भीतर सत्तर आदमियोंकी भूख

से मौत हुई । किन्तु बंगालमें खबरोंको छिपाकर लगातार सरकारी जिम्मेदारी को टाला गया है । इसी तरह हमने आस-पासके प्रदेशोंकी सहानुभूति और सहयोगको खो दिया है ।

बिहार और उड़ीसा प्रदेशोंमें व्यापारियोंको बेरोक-टोक छोड़ दिया गया । सस्ते दामोंमें चावल खरीदकर मुनाफा उठाना ही उनकी नीयत थी । उड़ीसा-सरकारने इसमें रुकावट डाली, बिहार सरकारने भी वही रास्ता पकड़ा । बादमें सुहरावर्दी साहबने उनसे सलाह-मशवरेकी बात चलानेकी चेष्टा की थी । किन्तु मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले यह सलाह-मशवरा ही बंगाल मंत्रिमण्डलको करना उचित था । किस वजहसे सुहरावर्दी साहब उस वक्त उड़ीसा और बिहार जानेमें हिचकिचाये थे ? पाकिस्तानके समर्थक होनेके नाते भावी हिन्दुस्थानके अंश——बिहार और उड़ीसाके निकट कृपा-याचनाके लिये जाना उन्होंने पसन्द न किया ; क्या यही कारण है ? हायरे ! पाकिस्तानकी अर्थ-नीतिकी भीत ही धसी जा रही है ! पाकिस्तानके भावी दुर्ग बंगालको आस-पासके हिन्द-प्रदेशसमूहकी दानशीलताके ऊपर निर्भर हो कर जीना होगा । केन्द्रीय सरकारको छोड़ बंगाल और भारतवर्षकी समस्याका हल आखिर तक और किसीके किये भी सम्भव नहीं होगा ।

मैं पूछता हूँ कि किस वजहसे सुहरावर्दी साहबने बिहार-सरकार और उड़ीसा-मंत्रिमंडलके पास जाकर तड़के ही आपसी सलाह-मशवरेकी चेष्टा न की ? उन्होंने कहा क्यों नहीं कि हमलोग भूखेपेट हैं ; आपलोग क्या पांच-दस लाख मन करके बंगालको चावल नहीं दे सकते ? व्यापारियों और दलालोंने मनमाने तौरपर भावमें गड़बड़ी की है । इसका मौका न देकर बंगाल, बिहार

और उड़ीसाकी सरकारें एक जगह बैठ कर भावके सम्बन्धमें एक स्वतंत्र सलाह-मशवरा कर ही सकती थीं। मंत्रिमंडल इस तरीकेसे समस्याको हल करनेकी चेष्टा कर सकता था। किन्तु उन्होंने ऐसा किया नहीं।

इस्पहानी कम्पनीको बंगाल-सरकारकी ओरसे एकमात्र खरीददार नियुक्त करनेके सम्बन्धमें मैं अब कुछ कहूँगा। यह पहले ही कहे देता हूँ कि इस्पहानी साहबके खिलाफ निजी तौरपर मुझे कुछ भी कहने को नहीं। इस संस्थाके अन्यान्य हिस्सेदारोंको मैं पहचानता भी नहीं, यही कहना उचित होगा। वस्तुतः यह व्यक्तिगत सवाल नहीं, उसूलका सवाल है। मन्त्रिमंडलके लिये यह एक कलंककी बात है कि उन्होंने एक खास व्यापारी-संस्थाको सोल एजेंट नियुक्त किया है, और दस्तावेजके नामपर एक टुकड़ा कागज तक न लिये बिना उसे करीब दो करोड़ रुपया पेशगी दे दिया। बंगाल-सरकार और इस्पहानी कम्पनीके बीच शर्तोंके बारेमें क्या एक भी दस्तावेज सुहरावर्दी साहब दिखला सकते हैं? इस मामलेमें क्या बंगाल धारा-सभाका निर्देश लिया गया था? धारा-सभा के सदस्योंकी हैसियतसे हमलोग यहांपर बैठकर बंगालके भाग्यका निर्णय करने की चेष्टा कर रहे हैं। बजट को किस तरह जोड़-गांठकर पेश करनेकी चेष्टा हुई थी! उस बजटपर बहस नहीं हुई, यह ठीक है, किन्तु बहसके लिये पिछले हफ्ते वह पेश किया गया था। इस्पहानी कम्पनीको उपयुक्त क्षमताके अलावा जो दो करोड़ रुपया या उससे अधिक पेशगी दिया गया है, उस बजटमें इसका उल्लेख भी न था। साधारण तहवीलसे बाहर और एकदम ही गैर-कानूनी तौरपर यह व्यय किया गया है।

मेरा अभियोग है कि बंगाल-सरकार और इस्पहानी कम्पनीके बीच आज

तक कोई शर्त पक्की तौरपर तय नहीं हुई है। मंत्रिमंडलमें अगर साहस हो तो वह इस बातका प्रतिवाद करे। इस सिलसिलेमें कोई टेण्डर नहीं मांगे गये। इस कम्पनीके साथ जो भी शर्तें हुई हों, और किसीको तो उन शर्तों पर काम करनेका मौका नहीं दिया गया। बंगाल-सरकार जो जमानतका दावा करती है, इस्पहानी उसे देनेसे इनकार करते हैं। मौजूदा विपज्जनक परिस्थिति में इतना सारा रुपया एक व्यापारी संस्थाको दे दिया गया, जिसके एक हिस्से-दार मि० सुहरावर्दीके दलके प्रधान समर्थक हैं। इससे ज्यादा और कलंककी बात क्या हो सकती है? लाखों अभागी बंग-संतानोंकी सेवा ही है न उनका उद्देश्य! मैं पूछता हूं कि उनके लिये इस अनोखे मार्गका क्यों अवलंबन किया गया? टेण्डर क्यों नहीं मंगवाये गये? सुहरावर्दी साहब फरमाते हैं कि चेम्बर आफ कामर्सका परामर्श ले लिया गया था। सभा-गृहमें इतनी बड़ी मिथ्या बात पहले कभी भी न कही गयी होगी। बंगाल नेशनल चेम्बर आफ कामर्स की ओरसे कहा गया है कि आपका कोई परामर्श नहीं ग्रहण किया गया। विगत् मारवाड़ी चेम्बर आफ कामर्सके प्रतिनिधि कहते हैं कि उनके साथ परामर्श नहीं हुआ। बंगालके आमलोगों और धारा-सभाको धोखा देने की यह चेष्टा क्यों हुई? इस्पहानी कम्पनीने चालीस लाख रुपयेका मुनाफा छोड़ा है, यह कहा गया है। इससे क्या समझानेकी कोशिश हो रही है, यह मैं जानता नहीं। शायद सुहरावर्दी साहब इसे अच्छी तरह बता सकेंगे। मेरा अनुमान है कि मामला निम्न प्रकार है। यह ठीक है कि मेरे द्वारा दिये हुए ये आंकड़े पूर्ण रूपसे अन्दाजिया हैं। मान लिया जाय कि इस्पहानी कम्पनीके पास पांच लाख मन चावल है। कलकत्तेके बाजारमें वह चावल ३०) रु०

प्रतिमनके हिसाबसे बेचा जा सकता है। इस्पहानी कम्पनीने शायद इस समय यह कहा, "हम आपलोगोंके हाथ यह चावल २२) रु० प्रति मनके हिसाबसे बेचेंगे।" इसका मतलब यही ठहरा कि इस्पहानी कम्पनीने फी मन ८) रु० मुनाफा छोड़ दिया है। चावलका परिमाण पाँच लाख मन हो, तो मुनाफेमेंसे सब मिला कर चालीस लाख रुपया छोड़ देना हुआ। पर सवाल होता है कि किस भावपर इस्पहानी-कम्पनीने उस चावलको खरीदा था? दस रुपया, बारह रुपया, पन्द्रह रुपया—किस भावपर? इस सम्बन्धमें कोई अनुसंधान होना क्या जरूरी नहीं?

किस नीतिके अनुसार बंगाल-सरकार अपने अनुग्रहीत मुनाफाखोरोंको आश्रय दे रही है? बंगालके लोगोंको अनन्त दुःख-दुर्दशामें डुबाकर क्यों इन सब लोगोंको मोटा होने दिया गया है? मंत्रिमण्डलके समर्थक जो मुसलमान सदस्यगण बैठे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वे इस व्यापारको दलबंदीके प्रश्नके रूपमें न देखकर निरासक्त भावसे सारी परिस्थितिपर विचार करें। यह मुस्लिम लीग, कांग्रेस अथवा किसी दल-विशेषका प्रश्न नहीं है।

भूतपूर्व मंत्रिमंडलके कार्य-कालमें भी इस्पहानी कम्पनीके साथ एक बेनाम शर्त तय हुई थी। किन्तु मालूम हुआ है कि गवर्नरके हुक्मपर ज्वाइण्ट सेक्रेटरीने इसे तय किया था। इसी सभा-भवनमें फजलुलहक साहबने इस बातका जिक्र किया है। उनकी बातका आजतक भी कोई प्रतिवाद नहीं हुआ।

इस्पहानी-कम्पनी जब गवर्नमेण्टके एजेण्टके रूपमें काम करेगी, तो वह चावलको अपने हिसाबमें न खरीदेगी, इस प्रकारकी बात हुई थी। किन्तु इस्पहानी-कम्पनी इस शर्तपर राजी न हुई। उसने यह सुझाव पेश किया कि

सिविल-सप्लाइज विभागके डाइरेक्टरकी अनुमतिसे अपने हिसाबसे ही उसे (इस्पहानी-कम्पनीको) चावल खरीदनेकी अनुमति देनी होगी। इन सब महत्वपूर्ण शर्तोंके सम्बन्धमें अभी भी कुछ ठीक-ठाक नहीं हुआ, फिर भी इसी बीच मुसलिम लीग पार्टीके कृपा-पात्र इस सदस्यके हाथमें सरकारी खजाने-से करोड़-करोड़ रुपया दिया जा रहा है! इसकी तुलनामें बहुत-सी सामान्य बातोंपर मि० हेनड्री एवं उनका दल नाराज होकर भूतपूर्व मन्त्रिमण्डलका समर्थन करनेसे हाथ खींच गया था। भूतपूर्व मन्त्रिमण्डलके खिलाफ इस तरहका कोई अभियोग नहीं लगाया गया था। मि० हेनड्री और उनका दल अब क्या करेगा? वह तो उस जगहपर शान्त मेमनाकी तरह बैठे हैं। मि० हेनड्रीने *मन्त्रिमण्डलको सार्टिफिकेट दिया है एवं मन्त्रिमण्डलके* पाससे अब फिर वे वापसी-सार्टिफिकेटकी आशा करते हैं। "मैं तुम्हारी पीठ खुजलाये देता हूं, तुम भी मेरी पीठ खुजला दो"—बात इसी तरहकी है, और क्या?

[सरकारी पक्षसे एक साहब बोले—'इन्होंने आप लोगोंकी भी पीठ खुजलायी थी।']

इन्होंने हम लोगोंकी भी पीठ खुजलानेकी चेष्टा की थी, यह ठीक है। किन्तु बादमें पता चला कि जैसी उनकी उम्मीद थी, उससे बात सोलह आना भिन्न थी। हम लोग उन्हें प्रसन्न करनेके लिये बिलकुल ही तैयार नहीं थे। उस समय गत मार्चमें यूरोपियन दलने विरोधी दलका साथ दिया।

मि० मैकइन्सने क्यों पद-त्याग किया, यह बात परिषद् मि० सुहरावर्दीसे

मालूम करना चाहती है। मि० मेकइन्सने परेशान होकर पद-त्याग किया, क्या यह सच नहीं है ?

वर्तमान मन्त्रिमण्डलमें जिस तरह सिविल सप्लाइज महकमेका काम चल रहा था, उससे बहुत ज्यादा असन्तुष्ट होकर ही मि० मेकइन्स चले गये। क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि घनिष्ठरूपसे जानी-पहिचानी किसी विशेष व्यापारी-संस्थाके हितोंको ध्यानमें रखकर ही अगर महकमेका काम-धन्धा चलाया जाय, तब तो इस तरह लोकसे दिखलावे भरे मारफती तरीकेपर काम न कर, खुलेआम उस व्यापारी संस्थाके साथ गवर्नमेण्टका काम चलाना ठीक होगा। इस विषयमें मैं सिर्फ एक और बात कहूंगा----

(सिद्दिकी साहबने अस्पष्ट तौरपर कुछ कहा।)

सिद्दिकी साहब मुझे अटका रहे हैं। उनकी विवेक-बुद्धि जाग रही है, इस बातकी मुझे खुशी है। उस दिन सिद्दिकी साहबने घोषणा की थी कि वैधानिक मामलेमें वे किसी दल-विशेषका मुख देखकर काम नहीं करते। उन्हें धीरज खोनेकी जरूरत नहीं; मैं ही उनके पास अब एक वैधानिक समस्या उपस्थित करता हूं। 'मे' द्वारा लिखित 'पार्लमिण्टरी प्रैक्टिस' के पहले अध्यायमें ३४ वें पृष्ठपर लिखा है कि हाउस आव कामन्सका कोई सदस्य यदि गवर्नमेण्ट कंट्रैक्टर हो, तो उसे वोट देने अथवा हाउस आव कामन्सका सदस्य बने रहनेका अधिकार नहीं रहता। यह कानूनसे मानी हुई एक प्रथा है। ब्रिटिश पार्लमिण्टके सुस्पष्ट विधानके ऊपर यह प्रथा कायम है। मि० सिद्दिकी वैधानिकता एवं इंगलैंड, तुर्की, स्पेन, फ्रांस, बेलजियम, होनो-लुलु आदि सभी स्थानोंकी पार्लमिण्टीय ज्ञानके लिये विख्यात हैं। क्या वे

यह माननेको तैयार हैं कि, उपरोक्त नीतिके अनुसार, मि० इस्पहानी अथवा अन्य जो कोई भी गवर्नमेण्ट कंट्रैक्टरोंमेंसे हों, उनका भविष्यमें धारा-सभाका सदस्य बने रहना उचित न होगा ?

(मि० सुहरावर्दी साहब बोले कि भूतपूर्व मन्त्रिमण्डलके वक्त भी कंट्रैक्टर थे ।)

धारा-सभाका कोई सदस्य अगर उस वक्त गवर्नमेण्ट कंट्रैक्टरके रूपमें काम करते रहे हों, तो उनके साथ भी इसीके अनुरूप व्यवहार होना चाहिये था । इस मामलेमें किसी भी प्रकारकी सहानुभूति दिखलाना वैध नहीं । वस्तुतः इसी कपटको बङ्गालकी आम जनताके सामने नग्न रूपमें खोलकर रखनेकी आवश्यकता है ।

इसके बाद आलोचनाका विषय है खाद्य-वितरणका ढङ्ग । मैं बहुत संक्षेपमें इस प्रसंगकी आलोचना करूंगा । गवर्नमेण्ट कहती है कि कण्ट्रोल-दुकानें नाकामयाब रही हैं । वर्तमान समयमें वह आठ सौतक सरकारी दुकानें खोलनेका खयाल कर रही है । कण्ट्रोल-दुकानोंकी ओरसे मैं वकालत नहीं कर रहा हूं । मैं जानता हूं कि दो कारणोंसे कण्ट्रोल-दुकानें असफल हुई हैं—(१) सप्लाईका अभाव एवं (२) किसी-किसी पहलूमें अनाचार । अगर अनाचारकी वजहसे कण्ट्रोल-दुकानोंका उद्देश्य व्यर्थ होता हो, तो बेरहमीके साथ यह अनाचार दूर करना होगा । इसके लिये कोई किसी प्रकारका दोष न देगा । किन्तु व्यापारका स्वाभाविक पथ पूर्ण रूपसे नष्ट करनेका क्या प्रयोजन हो सकता है ? गवर्नमेण्टकी वितरण-नीतिके साथ भी इसका कोई सामं-

जस्य नहीं। पर खरीददारीके सम्बन्धमें मैं इस प्रकारकी बात नहीं कह रहा हूं; उस विषयकी तो बादमें आलोचना करूंगा।

वितरणके सम्बन्धमें किस लिये यह प्रस्ताव हो रहा है कि व्यापारके साधारण मार्गको छोड़कर सरकारी दुकानें खोलनी होंगी? प्रस्तावित दुकानों-का स्वरूप क्या होगा? किस हिसाबसे किन लोगोंके ऊपर उसका भार सौंपा जायगा? किस-किस विषयका विचार कर किन-किन हिस्सोंमें वे सब दुकानें खोली जायंगी? भूतपूर्व मन्त्रिमण्डलने यह उसूल बनाया था कि कोई आदमी, जिसे कमसे-कम तीन सालतक व्यापारका काम करते हुए न हो गये हों, उसको कण्ट्रोलकी दुकान पानेका अधिकार न होगा। यह नियम अनाचार-निवारणमें विशेष सहायक था। किस कारण इसकी उपेक्षा की गयी? सांप्र-दायिकता एवं दलबन्दीकी बिनापर अनुग्रहयुक्त वितरणमें क्या यह नियम रोड़ा बना हुआ पड़ा था?

अधिक खाद्य-उत्पादन-आन्दोलन किस तरह चल रहा है? इस विषयपर सरकारका रचनात्मक सुझाव पूरी तौरपर हम जानना चाहते हैं। प्रचार-कार्य तो केवल लोगोंको बहलानेका साधनमात्र है। कागजके ऊपर अनाज पैदा न होगा। रोजमर्रा हम बंगालके हर कोनेसे चिट्ठियां पा रहे हैं कि खेतीके काम आनेवाले जानवरोंका अभाव है। सरकार अगर अभीसे इन्त-जाम न करेगी, तो आनेवाले साल अच्छी अमनकी खेती न हो सकेगी। सारा प्रदेश प्रायः चावल-शून्य हो गया है। इसपर अगर इसके बादकी अमनकी फसलकी उम्मीदें भी लोप हो गयीं, तो बङ्गालकी क्या सोचनीय हालत होगी? मन्त्रिमण्डलको खबरें मिल रही हैं या नहीं, कुछ पता नहीं—

देशके विभिन्न स्थानोंमें अनेक रोगोंसे गवादि पशु मरते जा रहे हैं। युद्धके लिये भी बड़ी तादादमें गवादिकी खरीद हो रही है। इसी परिषद्के एक सदस्य हालहीमें अपने गांवसे आये हैं। उन्होंने कहा है कि उनके चौदह बैलोंमेंसे तेरह बैल चेचकसे मर गये हैं, सिर्फ एक जीवित है। यही बङ्गाल-की साधारण दशा है। आगामी कुछेक महीनोंके भीतर अनेक संक्रामक रोगोंके फैलनेसे बङ्गालके लोक-स्वास्थ्यकी शोचनीय हालत हो सकती है। इसकी बाबत भी क्या मन्त्रिमण्डल कुछ सोच रहा है? जीवनी-शक्ति-शून्य लाख-लाख बङ्गालियोंके ऊपर वह एक प्रबल प्रहारकी तरह टूट पड़ेगी। अन-शन और रोगसे मनुष्योंकी मृत्यु न हो, इसके लिये क्या व्यवस्था काममें लायी जा रही है?

इसका प्रतिकार कैसे हो?

उपाय यह है कि गवर्नमेंटको अकालकी घोषणा करनी होगी एवं अकालको रोकनेके लिये सहृदयताके साथ माकूल इन्तजाम करना होगा। गवर्नमेण्ट परिशोधका कोई भी वचन न देगी, ग्राम-कमेटियां अपनी सामर्थ्यके अनुसार जो होगा, करेंगी। इन बिनावपर बचे-खुचे चावलको जबर्दस्ती उधार लेनेकी नीतिका प्रयोग अथवा स्वावलम्बनके सम्बन्धमें सस्ते उपदेश—इन सबके बदले बंगालके लोगोंके लिये भोजन जुटानेकी पूर्ण जिम्मेदारी गवर्नमेण्टको अपने ऊपर लेनी होगी।

मन्त्रिमण्डल या तो जनताको खिलानेकी जिम्मेदारी ले, नहीं तो पदत्याग करे। जब कि कार्यतः ब्रिटिश गवर्नमेण्टका ही पूर्ण शासन चल रहा है, वही

यहांकी आम जनताको खिलाने और सूबेकी शान्ति-श्रृंखलाको बनाये रखनेका उत्तरदायित्व ग्रहण करे ।

मूल समस्याके समाधानके लिये मूल्य और सप्लाईके पूर्ण नियन्त्रणको जरूरत है । मि० हेनड्रीने ठीक ही कहा है कि इसको करनेके तीन मार्ग हैं । गवर्नमेंट अकेले ही सब माल खरीद सकती है, व्यपारी खरीद सकते हैं, अथवा गवर्नमेंट और व्यवसायी दोनों मिलकर खरीद सकते हैं । गवर्नमेंट के बाजारके बीच आते ही सारी परिस्थिति पलट गयी है । पूर्ण नियन्त्रण-व्यवस्थाके चालू न होने तक कदापि इसका प्रतिकार न हो सकेगा । व्यापारियोंको अबाध क्षमता देनेसे सूबेका अनाज एकदम चुक जायगा । उससे वितरण-व्यवस्थाका भी मेल और साम्य न रह सकेगा । एकमात्र गवर्नमेंट ही मूल्य और सप्लाईका पूर्ण नियन्त्रण कर सकती है और इसके फलस्वरूप राशनिंग चालू हो सकता है । राशनिंगका मतलब ही होता है सप्लाईके सम्बन्धमें सरकारी जिम्मेदारी । सप्लाईके अच्छे इन्तजामको छोड़कर राशनिंग चल ही नहीं सकती । गवर्नमेंट मौजूदा समयमें जो कर रही है, वह राशनिंग नहीं है; इससे लोगोंको असलमें भूखा रखा जा रहा है । सप्लाई अबाध नहीं है; एवं गवर्नमेंट भी यह नहीं कह रही है कि राशनिंग चलाकर वह सप्लाईकी जिम्मेदारी लेगी । अगर सभी वर्गोंमें सप्लाई और वितरण-सम्बन्धी न्याय और समताकी नीति बर्ती जाय, तो लोग दुख सहने और कुछ कुर्बानी करनेको भी तैयार हैं ।

किस प्रकार यह जिम्मेदारी लेना सरकारकी ओरसे सम्भव है ? बङ्गालके इस भयंकर संकटके समयमें किसी एक दलके लोगोंको लेकर बनी हुई गवर्नमेंट

के लिये मूल्य और सप्लाईका पूरा-पूरा नियन्त्रण जमाना एवं बङ्गालके छ करोड़ लोगोंके लिये भोजन जुटानेकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना सम्भव नहीं। हमारा यह विरोधी-दल अगर गवर्नमेंट बनावे और मुसलिम लीग विरोधी दलमें रहे, तो भी समस्याका सुलझाव न हो सकेगा। वस्तुतः आज दलगत विषमताको पूर्ण रूपसे भुला देना होगा। मन्त्रिमण्डलको सभी वर्गों का आस्थाभाजन बनना होगा। सहायता देनेकी चेष्टा अकपट होगी; समस्याको राष्ट्रीय दृष्टिसे ग्रहण करना होगा। राजनीतिक और दलगत हितोंसे अनुप्राणित होकर अग्रसर होनेसे किसी तरहका समाधान न होगा। जो सब दल और उप-दल एक साथ मिलकर काम करनेके इच्छुक हों, उन सबके प्रतिनिधि मंत्रिमंडलके अन्दर होंगे।

[श्रीयुक्त रसिकलाल विश्वासने कहा—'आप भी तो उनमेंसे होंगे' ?]

नहीं, मैं नहीं। दूसरोंके हाथका खिलौना मैं नहीं बनना चाहता। इस पर भी जिम्मेदारी ले सकनेवाले ऐसे काफ़ी तादादमें उपयुक्त लोगोंका अभाव न होगा। इस जातीय संकटके सामने दलगत मनोभाव एकदम ही त्याग देना होगा। ब्रिटिश-साहाय्यके ऊपर टिके रहनेवाले दल-विशेषके हितोंकी ओर कोई लक्ष न रखकर, जिससे सारे सूबेका मङ्गल-साधन हो सके, इस तरह किसी सिद्धान्तपर सब मिल सकें, तो तभी दलगत मनोभाव लोप हो जायगा।

दो-एक ऐतिहासिक प्रसंगोंका थोड़ेमें उल्लेखकर मैं वक्तव्यको समाप्त करूंगा। बंकिमचन्द्रकी बातको उद्धृत न करूंगा, कारण कि शायद उनकी राय पक्षपातपूर्ण कही जायगी। ब्रिटिश इतिहासकारोंने ही कहा है कि

बङ्गालमें अकाल और महामारी एकके बाद दूसरी अटूट रीति-क्रमसे होती आ रही हैं। जिस समय मुगल-साम्राज्यकी भुजा बङ्गालकी ओर बढ़ रही थी, उस समय गौड़-राज्यमें आकस्मिक महामारीका आविर्भाव हुआ था। विशाल सुन्दर नगर गौड़—सिर्फ बङ्गालका ही नहीं, सारे भारतका गौरव था। एक सालके भीतर ही वह एकदम चिन्ह-रहित हो गया। हण्टरने अपनी लाज-बाब भाषामें बयान किया है कि यह किसप्रकार बघेरों और बन्दरोंकी आवास-भूमिमें परिणत हुआ था। इसके बाद मुगल-साम्राज्यका आविर्भाव और तिरोभाव हुआ। कुछेक सदियोंके बाद, पलासीकी लड़ाईके ठीक बिल्कुल बादमें, छहत्तरके * अकालके नामसे मशहूर सन् १७७० का भीषण अकाल दिखाई दिया। अङ्गरेज लोग इसी समय बङ्गालमें अपनी हुकूमतको फैलाने की चेष्टा करनेमें लगे हुए थे। आज भी हमलोग फिर अकाल और एक बड़ी भारी आर्थिक उलट-फेरके सम्मुख हैं। बङ्गालके तमाम हिस्सोंसे दुर्गति, दुःख-भोग और मौतकी खबरें आ रही हैं। एकदम वशीभूत मन्त्रिमण्डल द्वारा प्रकाशित मधुर वाक्यालंकृत इश्तिहारोंमें अवस्थाका गुरुत्व छिपाने या इसे छोटा करके दिखानेकी जितनी भी कोशिश क्यों न हो, नियति इतिहास की अनोखी और भयानक पुनरावृत्तिकी ओर अचूक इशारा कर रही है। सन् १७७० के अकालके वक्त बङ्गालकी जो हालत हुई थी, मौजूदा वक्तमें भी हू-ब-हू वही दशा होती जा रही है। इस विषयको हमें लगनके साथ सोच कर देखना चाहिये। हण्टरने इस अकालका जो खाका खींचा है, मैं उसे उद्धृत कर रहा हूं। परिषद्के सदस्योंसे मेरा अनुरोध है कि वे जी लगाकर

---

* बङ्गला संवत् १२७६ अनु०

मामलेको देखें। उसके बाद अधिकारियोंसे पूछना होगा कि सन् १९४३ में वे किस तरह अपनी जिम्मेदारीको निभाने जा रहे हैं ?

[सिद्दिकी साहबने बीचमें रोकनेकी चेष्टा की।]

मैं जानता हूं, यह कहानी सिद्दिकी साहबको बहुत अधिक विचलित कर रही है।

[सिद्दिकी साहब बोले,—'जरूर']

किन्तु इस सभामें ऐसे अनेक लोग हैं, जो बङ्गालके अभागे अधिवासियोंके प्रति ज्यादा दयावान और सहानुभूतिपूर्ण हैं। सुदूर सिन्ध सूबेसे बङ्गालमें आकर सिद्दिकी साहबने बेशुमार रुपया बनाया है। इससे भी अगर वे संतुष्ट न हों, इस सूबेके लोगोंके प्रति अब भी उनकी थोड़ी-सी सहानुभूति न हुई हो, तो हमलोग उनपर दया करेंगे।

सन् १७७० के दुर्भिक्षके बारेमें हण्टरने जो चित्र अंकित किया है, उसका थोड़ा-सा हिस्सा नीचे दिया जाता है—

"सन् १७७० के सारे ग्रीष्म भर दम घोटनेवाली गरमीमें लोग मरने लगे। किसानोंने ढोरों और खेतीके औजार बेच डाले, बीजका धान खा डाला, लड़की-लड़के तक बेच डाले। बादमें लड़के-लड़कीके खरीददार भी न मिले। लोग पेड़ोंके पत्ते और मैदानोंकी घास खाने लगे। सन् १७७० में रेजीडेण्टने स्वीकार किया कि जीवित लोग मुर्दोंको भक्षण कर रहे हैं। दिन-रात भूखसे पीड़ित और रोगग्रस्त अभागे लोग जल-धाराकी तरह शहरमें प्रवेश करने लगे।............मरणोन्मुख और मुरदोंके ढेरके कारण रास्तोंपर लोगोंका चलना-फिरना बन्द हो गया। मुर्दोंका दाह-संस्कार भी अब मुमकिन न रहा—यहां तक कि प्रकृतिकी ओरसे सफाई रखनेवाले सियार और कुत्ते तक मुर्दोंको

खाकर खतम नहीं कर पाते। विकृत और गले हुए मुर्दोंके ढेरोंसे नागरिकोंका जीवन दूभर हो उठा।"

मेकौलेकी लिखी हुई लार्ड क्लाइवकी जीवनीमें भी इसी तरहकी तसवीर खींची गयी है—

"जो सब नितान्त कोमलांगी अन्तःपुरवासिनी स्त्रियाँ कभी भी घरके बाहर न आयी थीं, अवगुंठन कभी भी लोक-दृष्टिके सामने ऊपर न उठा था, वे ही रास्ते पर उठ खड़ी हो गयीं, बच्चोंके लिये एक मुट्ठी अन्न पानेके लिये भूमिपर लोटकर ऊँचे स्वरमें विलापकर राहगीरोंकी दयाकी भीख मांगने लगीं। विजेता अंगरेजों के प्रमोदोद्यान और अटारियोंके प्रवेश-द्वारके बहुत समीप हजारों मुर्दे प्रतिदिन हुगली नदीकी धारामें बह-बहकर आने लगे। मुर्दों और अधमरे लोगोंकी वजह से कलकत्तेकी सड़कोंपर आदमियोंका चलना-फिरना बन्द हो गया। रोगी और कमजोर देहको लेकर जो लोग बच रहे, अपने रिश्तेदारोंके शवका संस्कार करने अथवा गङ्गाजलमें मृत देहको छोड़नेका उत्साह भी उनमें न था। खुले-आम दिन-दहाड़े सियार और गीधोंके दल मुर्दोंको भक्षण करते थे। उनको खदेड़नेकी इच्छा भी किसीको न होती थी।"

यह अतिरञ्जित कहानी नहीं। आज बङ्गालके कोने-कोनेसे हम लगातार इसी तरहके विवरण पा रहे हैं। आज ही मुझे छ-सात चिट्ठियां मिली हैं। उनसे मालूम हुआ कि ऊपरकी वर्णित हालत शुरू होने लगी है। परिषदसे मैं प्रश्न करना चाहता हूँ कि इस दुर्दैवका प्रतिकार क्या है? बङ्गाल का जीवन-प्रवाह यदि अचानक लोप हो जाय, तो हम कहां रहेंगे, हमारा दल ही कहां रह जायगा?

यह अकाल किसी प्राकृतिक कारणवश नहीं हुआ। जो लोग भारतवर्ष और बङ्गालके शासनके लिये जिम्मेदार हैं, उन्हींके द्वारा बरती हुई गलत नीति

के फलस्वरूप यह हुआ है। करीब दो सदियोंसे फैली हुई पराधीनताके कारण जनता आज मौतके दरवाजेके पास जा पहुँची है।

सन् १७७० के अकालके कारण बतलाते हुए मेकौलेने कहा है—'प्राकृतिक कारण निस्सन्देह थे ही; किन्तु उससे भी बड़ा कारण था, उससे एकदम पहलेकी अङ्गरेजी शासनकी गड़बड़ी।' मेकौलेके शब्द नीचे दिये जाते हैं—

"ब्रिटिश फैक्टरीका हरएक नौकर अपने मालिकोंकी सब तरहकी ताकत का अधिकारी था; मालिक भी कम्पनीकी सब तरहकी क्षमताके अधिकारी थे। इस प्रकार कलकत्तेमें प्रचुर सम्पत्ति तेजीके साथ इकट्ठी हो गयी, और उसीके साथ तीन करोड़ आदमी दुर्गतिकी चरम अवस्थाको जा पहुँचे।"

महत्वशाली ब्रिटिश-शासनकी तब नींव सड़ रही थी। वह शोकपूर्ण चित्र मेकौलेकी अपेक्षा सुन्दर ढङ्गसे अन्य कोई भी आंक नहीं सका है।

"सूबेके लोग स्वेच्छाचारके बीच रहनेके आदी थे, किन्तु ऐसी स्वेच्छाचारिता उन्होंने कभी नहीं देखी थी। कम्पनीकी छोटी उँगली तक सिराजुद्दौलाकी कमर की अपेक्षा मजबूत थी। मुसलमानी ज़मानेमें कमसे-कम प्रतिकारका एक उपाय था। बुराई जब बहुत ही असह्य हो उठती, तो आम लोग बगावत कर गवर्नमेंट को चकनाचूर कर देते थे। किन्तु इस गवर्नमेंटको हटानेका कोई रास्ता न था। कम्पनीकी उस अमलदारीको मनुष्य-चालित गवर्नमेंट न कहकर, दुष्ट अप-देवताके साथ उसकी तुलना संगत है।"

प्रायः दो सदी आगे अङ्गरेजी राज आरम्भ हुआ था; यह उसी समयकी तसवीर है। आज हम सन् १९४३ में पहुँच गये हैं। किन्तु अपने देश और जातिकी सेवा करनेमें और देशभाइयोंकी रक्षा करनेमें हमारी सामर्थ्य

चिर निद्राकी गोदमें।
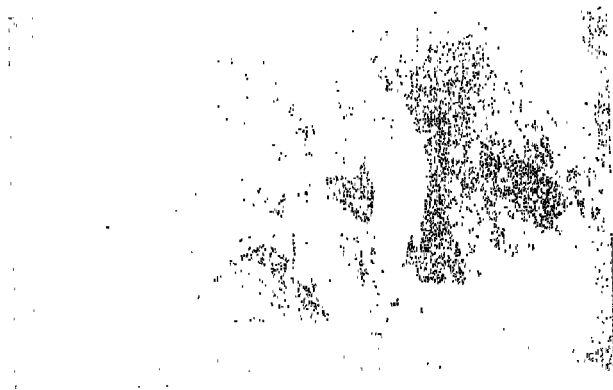
तामलुकमें :— कुत्ता मृत-देहको खा रहा है।

बायाँ हाथ, छातीका बायाँ हिस्सा और पञ्जर सियार खा गये। लड़कीका नाम था मोक्षदा, बनियाजुड़ि गांवमें घर। २६ अक्टूबर (१९४३) को मानिकगञ्जके बाजारमें इस हालतमें वह पाई गयी।

क्या कुछ भी बची है ? यहाँके अधिवासियोंको बचानेकी आखिरी जिम्मेदारी रखी गयी है ब्रिटिश-शासकवर्गके ऊपर। वे इस परम दायित्वको भूलकर, जो खुले या परोक्ष रूपसे लड़ाईके सिलसिलेमें काम कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं सब लोगोंको खाना देना चाहते हैं।

मि० डेविड हेनड्रीने हम लोगोंको याद दिलायी है कि हम पूर्वीय युद्ध-भूमिके निकट निवास कर रहे हैं। किस प्रकार यह लड़ाई जीती जायगी ? अगर बंगाल भूखा ही रहे, बंगाल अगर वीरान हो जाय, तो लड़ाई जीतनेमें क्या बड़ी आसानी रहेगी ? लोगोंके दिलोंका साहस और देशकी आन्तरिक शान्ति क्या उस हालतमें अटूट रखी जा सकेगी ? आज जो हम यह दुख भोग रहे हैं, इसमें बंगालका क्या अपराध है ? किसके दोषसे बरमाका पतन हुआ था ? या किसके दोषसे सिंगापुर हाथसे निकल गया ? बंगाल इसके लिये जवाबदेह नहीं। तो फिर बंगालके लोग क्यों दुख भोगें ? भारत-सरकारको बिना देरी किये हम लोगोंको अनाज लाकर देना होगा।

[यूरोपियन दलके बीचसे बोलते सुना गया, "अपने दोस्त तोजो * के पास क्यों नहीं जाते ?"]

यूरोपियन दलकी ओरसे हम इसी तरहकी बातोंकी आशा रखते हैं। सदस्य महोदय क्या सचमुच ही यह कहना चाहते हैं कि चावल और खाद्यके लिये ब्रिटिश गवर्नमेण्टकी ओर न ताक कर, तोजोसे मांगना हमारे लिये ठीक होगा ? हाउस आव कामन्समें इसी बातकी प्रत्यक्ष घोषणा करनेके लिये वे क्या मि० एमरीको सलाह देंगे ? वे कहते हैं कि तोजो हमारा दोस्त है।

* जापानी प्रधान मन्त्री।

हमारा दोस्त कौन है, यह भविष्यका इतिहास ही बतला देगा। इतना भर मैं कह सकता हूं कि आप लोगोंके साथ सम्बन्धित होनेके १७० साल बाद भी बंगालको इस प्रकार भूखा रहना पड़े, तो आप लोग अवश्य ही हमारे दोस्त नहीं।

भारत-सरकारकी जिम्मेदारीके बारेमें अब मैं कुछ कहूंगा। हिसाबके आंकड़ोंकी ओर एक बार नजर डालें। सन् १९४३ में बंगालकी खातिर दो लाख चालीस हजार टन गेहूं मंजूर हुआ था। साधारण अमन-चैनके समयमें बंगालके लिये मंजूरशुदा गेहूंका परिमाण ढाई लाख टन है। अतएव वर्तमान जरूरी अवस्थाके लिये बंगालको क्यों बकाया गेहूं नहीं दिया गया? फिर सन् १९४३ के लिये निर्दिष्ट इस गेहूँमेंसे किस परिमाणमें आजतक प्राप्त हुआ? केवल पचास हजार टनके लगभग, अर्थात् जो निर्दिष्ट हुआ था उसका सिर्फ पच्चीस फी-सदी हिस्सा! सुहरावर्दी साहबने फरमाया है कि चावलके बदले बंगालके लोगोंको ज्वार, भुट्टा और बाजरा खाना पड़ेगा। सन् १९४३ में बंगालके लिये वह दो लाख टन निर्दिष्ट हुआ था; किन्तु यहां पहुंचा है सिर्फ दस हजार टन। अतएव सुहरावर्दी साहबकी छूंछी वक्तृता और झूठे वायदेसे क्या लाभ होगा? अगर आस्ट्रेलियासे गेहूं न लाया गया और भारतके अन्यान्य हिस्सोंसे अनाज बंगालको न भेजा गया, तो भारत-सरकारकी बीच-बीचमें भ्रान्तिजनक इश्तहार प्रकाशित करनेकी सार्थकता ही कहां है? परिषद्के प्रत्येक भारतीय सदस्यको इसके लिये सचेष्ट होना होगा।

मन्त्रिमण्डलको ऐसा शक्तिशाली और प्रतिनिधित्वपूर्ण होना होगा कि भारत-सरकार अथवा बङ्गाल-सरकारके असली प्रभुगण उसकी अवज्ञा करने

में समर्थ न हों। इङ्गलैंडके प्रधान-मन्त्रीके पास इस प्रकारका संवाद भेजा जाय कि गुरुतर परिस्थिति पैदा हो गयी है। जरूरी खाद्य-सामग्री बंगालमें प्रवेश न करेगी, तो सभी जाति-वर्गोंके हितकी हानि होगी। इसे युद्ध-कालीन अवस्था माना जाय। इस सम्बन्धमें और कोई जोड़-तोड़ न चलने दिया जायगा। चोटीके अधिकारी अगर व्यवस्था करनेमें असमर्थ हों, तो मन्त्रिमण्डल पद–त्याग कर जिम्मेदारीसे अलग हट जाय। तब देखेंगे कि गवर्नर और उनके कर्मचारीगणकी मददसे देशका शासन-कार्य किस प्रकार चल सकेगा। सुहरावर्दी साहब अगर यह कर सकें—

(सुहरावर्दी साहब बोले कि वे इस विषयमें एकमत हैं।)

मैं जानता हूं कि सुहरावर्दी साहबको चेत आ रही है। सचमुच ही अगर वे एकमत हों, तो दलगत अनुसरण और दल-नेतृत्वका वे परित्याग करें। जाति, सम्प्रदाय और वर्णका विचार छोड़ बंगालकी जनताको ओरसे तब हम सम्मिलित मांग उपस्थित करेंगे और इस चरम संकटके मौकेपर एकयबद्ध होंगे। ×

× १८ जुलाई सन् १९४३ को बंगाल धारा-सभामें दी गयी वक्तृताका मर्मानुवाद।

जवाबदेह कौन ?

—:o:—

मैं प्रस्ताव करता हूँ—

"खाद्य-परिस्थितिके सम्बन्धमें सिविल-सप्लाइज मन्त्रीने जो वक्तव्य दिया है, सभाकी रायमें वह एकदम निराशाजनक है। अनाजके संग्रह और वितरण एवं बंगालमें अधिक अनाज पैदा करनेके विषयमें मंत्रिमण्डलने जिस नीतिका अनुसरण किया है, उसके पीछे कोई परिकल्पना न थी। वह नीति पूरी तरह नाकामयाब रही है। खाद्य-परिस्थितिमें गिरावट आनेसे सूबे भरमें हर जगह जो अकाल दिखलाई दिया, उसके लिये मन्त्रिमण्डल द्वारा वर्ती गयी नीति ही जिम्मेदार है। माल ढोनेका कोई अच्छा प्रबन्ध न कर, फिलहाल उन्होंने चावलके मूल्य-नियन्त्रणके सम्बन्धमें जो कानून जारी किया है, उसके फलस्वरूप लोगोंकी दुर्दशा दुगुनी बढ़ गयी है। जीवित रहनेके हेतु बहुत जरूरी सामान ढोने और लोगोंकी जानें बचानेके काममें नाकामयाब होनेसे मन्त्रिमण्डल, एक सभ्य सरकार के लिये अवश्य पालने योग्य अपना पहला फर्ज अदा न कर सका।"

सभाकी पिछली बैठकमें खाद्य-परिस्थितिकी आलोचनाके बाद अब हालत और भी खराब हो चली है। यह मौजूदा समयमें बंगालके लाखों अधि-वासियोंकी जिन्दगी और मौतका दूरतक असर रखने वाला सवाल हो उठा

है। सिविल सप्लाइज मन्त्रीका बयान जरा भी सन्तोषजनक नहीं। इसमें दूरकी सूझ-बूझ नहीं। यह सिर्फ छूंछे वाक्योंसे भरा पड़ा है। परिणामकी दृष्टिसे विचार करनेसे यह कहा जा सकता है कि सरकारी नीति एकदम ही विफल हुई है। मेरे लिये और दूसरे जो लोग जनताकी दुर्दशाको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके प्रति सुहरावर्दी साहबने जो व्यक्तिगत आक्षेप किये हैं, मैं उसका जिक्र करना नहीं चाहता। घृणा ही इस घृणाके लायक आक्षेपका एकमात्र उत्तर है। भारी अयोग्यता और नासमझीसे ही इस तरहके आक्रमणकी प्रवृत्ति होती है। सुहरावर्दी साहबने अपने ही मन और चरित्रके आलोकमें दूसरे लोगों और घटनाओंका विचार किया है।

आज हमारा एक देशव्यापी बेजोड़ संकटसे मुकाबला है। खासकर उन लोगोंकी दुःख-दुर्गतिका, जो देहातोंसे आ रहे हैं, मैं विस्तृत विवरण दे सकूं, इतना समय मेरे पास नहीं। इस कामको और कोई करेंगे। भुखमरी और भुखमरीसे पैदा होनेवाली बीमारियोंसे मौतका आहार बड़ी तेजीके साथ बढ़ चला है। लोग आत्महत्या कर रहे हैं, बेटा-बेटीको छोड़कर चले जा रहे हैं, बेवारिस मुर्दे जहां-तहां पड़े रहते हैं—इस तरहकी अनगिनत दिल दहलानेवाली खबरें जगह-जगहसे रोजमर्रा हमारे पास आ रही हैं। दिनके बाद दिन और हफ्तेके बाद हफ्ते कलकत्तेकी खुली सड़कोंपर पड़े-पड़े मनुष्य मर रहे हैं। ए० आर० पी० के 'बेड' खाली पड़े रहनेपर भी उन लोगों को अस्पतालमें जगह नहीं दी गयी। गवर्नमेंटने हालही में कलकत्तेमें अस्पताल खोले हैं, पर मुफस्सल शहरोंमें आज भी इस तरहकी कोई व्यवस्था नहीं हुई।

पिछले हफ्तेमें मेदिनीपुर गया था। लंगरखानेमें भोजनके लिये आकर मेरे सामने ही दो आदमियोंकी मौत हुई। भोजनको देखते ही एक आदमी इतना उत्तेजित हो उठा कि मुँहमें अन्न पहुँचनेके पहले ही बेचारा बेहोश होकर गिर पड़ा। तब उसे वहाँसे हटाया गया। शिकायत आयी है कि मेदिनीपुरके अस्पतालमें 'बेड' खाली रहनेपर भी लोग रास्तोंपर पड़े मर रहे हैं। मैंने सिविल सर्जन और उपस्थित लोगोंके पास इस विषयकी पूछ-ताछ की। मैंने मालूम किया कि मेदिनीपुरके अस्पतालमें ए० आर० पी० के लिये चालीस 'बेड' हर वक्त रिजर्व रखनेका नियम है। इन 'बेडों' को आरजी तौरपर भी काममें लानेकी इजाजत देनेकी ताकत कलक्टर तककी नहीं; गवर्नमेंटका हुक्म जरूरी है।

काँथीमें सियार और कुत्ते जी-भर मुर्दोंका भक्षण कर रहे हैं। इन सब जन्तुओंको गोलीसे मार डालनेका हुक्म दिया गया है। इस तरहकी एक घटना काँथीके कई-एक लोगोंने मुझे सुनायी है। जो कहानी मैंने सुनी वह विश्वासके बाहर है। कलकत्तामें आसरे-रहित और भूखसे पीड़ित लोगोंकी हालत चाहे जितनी भी दिल दहलानेवाली क्यों न हो,—मुफस्सल शहरों और गाँवोंमें जो रहा है, उसकी तुलनामें यह कुछ भी नहीं। चीथड़ोंसे ढँके कंकालवत् नर-नारी और बच्चोंका जातिवर्ण-निर्विशेष दल भोजनके अभावसे धीरे-धीरे मृत्युके मुँहमें जा रहा है। इस तरहके अनगिनत दृश्य मैंने प्रत्यक्ष देखे हैं। बेजमीन और बेघर गरीब दर्जेके आदमियोंकी बेहाली बेशक बहुत ज्यादा है। किन्तु मँझले दर्जेके लोगोंमें भी जो घराने मामूली समयमें अपनी हस्तीको बनाये रखते थे, आज बिलकुल दिल दहलानेवाले तरीकेसे उन्हें

मौतको अपनाना पड़ रहा है। वे ही हमारे सामाजिक और राजनीतिक जीवनकी रीढ़की हड्डी हैं। जातिकी बहुत जरूरी असली सेवा हमेशा वे ही करते आ रहे हैं। बंगालको बचानेके लिये इनकी रक्षा करनी ही होगी।

आनेवाले कुछेक महीनोंमें मौतका आहार कितना भयावह हो जायगा, उस बातको सोचकर कँपकँपी उठती है। जिन्होंने किसी तरह मौतके हाथ से छुटकारा पाया है, वे इतने बेजान हो गये हैं कि अब कभी भी वे काम-काजके लायक न हो सकेंगे। सभाकी पिछली बैठकमें मैंने हण्टरकी लिखी 'देहाती-बंगालकी कहानी' और 'लार्ड क्लाइव'की जीवनीसे सन् १७७० तथा उसके और-भौरेके समयमें बंगालकी बर्बादी और मृत्यु-वर्णन सुनाया था। उसके बाद १७० सालसे अधिक काल बीत चुका है। आज सन् १९४३ में बंगालके समाज और जीवन-चक्रके लिये हण्टर और मेकालेकी टिप्पणी समान रूपसे लागू हैं।

भारत-सरकारके स्वराष्ट्र-विभागके सेक्रेटरी मि० कर्डन स्मिथसे एकबार बंगालका मुआयना करनेका मैं सविनय अनुरोध करता हूँ। बंगालको अपनी आँखोंसे देखकर फिरनेके बाद फिर करें वे यह बेरहम आलोचना कि बंगालकी दुख-दुर्दशाके सम्बन्धमें नाटकीय अत्युक्ति हुई है। बंगालकी इस मुसीबतमें भारतवर्षके सब हिस्सोंके गैरसरकारी लोगोंसे भारी सहायता मिली है। रुपया, आश्रय-स्थान, अनाज और कार्यकर्त्ताओंसे सहायताके बहुतसे प्रस्ताव आये हैं। इसमें सन्देह नहीं कि जिस विराट संकटसे आज हमारा मुकाबला है, यह सारी मदद उसकी तुलनामें बहुत ही नाकाफी है। तब भी बंगालके लिये इस देशव्यापी सहानुभूतिने सूबे-सूबेकी भेदकी दीवालको तोड़कर समूचे

भारतवर्षके एका और मेलकी असलियतको सभीकी नजरोंमें स्पष्ट कर दिया है। इस हमदर्दीने लाखों पीड़ित लोगोंके हृदयमें साहस और दृढ़ता ला दी है। इसने लोक-मतको जगाया है, गवर्नमेंटको अपनी ज़िम्मेदारीकी बाबत चौकन्ना कर दिया है। इसके फलस्वरूप समूचे भारतवर्ष—यहां तक कि भारतसे बाहर के देशोंका भी खयाल बंगालकी दुख-दुर्दशाकी ओर खिंचा है। मैं बराबर ही कह रहा हूँ कि आम लोगोंमेंसे हरेक वर्गको—हरेक आदमीको पीड़ितोंका दुख दूर करनेमें अपनी ताकत भर कोशिश करनी होगी। किन्तु लोगोंको खिलाने, बाहरसे सामान लाने एव लोगोंका जीवन जिससे बच सके, इस तरह की अवस्थाको तैयार करनेकी ज़िम्मेदारी ठहरती है प्रधानतः देशकी गवर्नमेंट के ऊपर। सरकारी नीतिकी लम्बी-चौड़ी समालोचना करना आज मेरा उद्देश्य नहीं। वह तो शोचनीय रूपमें व्यर्थ हुई है। इस व्यर्थताका जो कारण हो सकता हो, उसके सम्बन्धमें स्वतन्त्र खोज बहुत ही ज़रूरी है। यह खोज दोष लगानेकी संकीर्ण मनोवृत्ति लेकर न चलायी जायगी। इसका उद्देश्य होगा आपसी तौरपर या लोक-मतका दबाव डालकर शासन-नीतिमें परिवर्त्तन लाना।

गवर्नमेण्टके खिलाफ मेरा पहला अभियोग यह है कि बंगालके भीतर और बाहरसे जिस तरीकेपर अनाज इकट्ठा किया गया है, वह विशेष आपत्ति-जनक है। मन्त्रिमण्डल पहले ही बेपरवाहीसे प्रचार करने लगा कि बंगालमें अनाजका अभाव नहीं; अनाज जमा करनेसे ही वर्तमान दुर्गतिकी सृष्टि हुई है। आज वह भ्रम टूट चला है। सिविल-सप्लाइज़ मन्त्रीने स्वीकार किया है कि अनाजका बड़ा अभाव है। इस बीच उन्होंने कीमती समय नष्ट

किया है। गलत बातोंके भरोसे रहकर पांच माहके अर्सेमें उन्होंने भ्रान्त नीतिका अनुसरण किया है।

जूनके महीनेमें जो खाद्य-आन्दोलन चला था, उसके सिलसिलेमें बंगालके देहाती हिस्सोंसे अनाज अन्यत्र चला गया। आन्दोलनका नतीजा आज भी प्रकाशित नहीं हुआ। उसे प्रकाशित करनेका साहस गवर्नमेण्टमें नहीं। हम हरेक जिले और हरेक महकमेका हिसाब जाननेकी मांग करते हैं। गवर्नमेण्टके मतमें कौन हिस्से कमीके हैं और कौन बढ़तीके, यह हमें मालूम होना चाहिये।

खाद्य-आन्दोलनके समय और उसके बाद भी व्यवसायियों और आढ़तियोंको जिस किसी कीमतपर चावल खरीदनेकी छुट्टी देकर गवर्नमेण्टने खतरनाक भूल की है। किस परिमाणमें अनाज खरीदा गया है, वह किस-किस जगह ले जाया गया और कहां जमा है, यह सब बातें हम जानना चाहते हैं। कमीवाले हिस्सोंमें काफी परिमाणमें अनाज भिजवानेके लिये काफी कोशिश नहीं हुई। कहीं-कहीं गोदामको रोककर उसपर मोहर कर दी गयी है। उन जगहोंमें लोग भूखके मारे जानें खो रहे हैं, तब भी गोदाममें पड़ा माल जमा ही रखा पड़ा है! सूबेके हर कोनेसे बरसातके धानकी खरीददारीकी खबरसे देहाती हिस्सोंकी हालत एकदम असहाय हो चली है। बर्दमान और मेदिनीपुर जैसे हिस्सोंसे अनाज खरीदकर बाहरको ढोनेमें गवर्नमेण्ट लोगोंको बढ़ावा दे रही है, यह बात सचमुच बहुत अचम्भेमें डालनेवाली है। आज सुबह ही एक सज्जनने कालनासे आकर खबर दी कि पिछले कुछेक दिनमें इस्पहानी-कम्पनीने, गवर्नमेण्टके एजेण्टके रूपमें, कालनासे

कमसे-कम पांच हजार मन चावल खरीदा है। सभी यह जानते हैं कि पिछली बाढ़के फलस्वरूप और भयंकर अर्थ-संकटसे कालनाके लोगोंकी दयनीय दुर्गति हुई है।

बाहरसे खाद्यके आयातके सम्बन्धमें मालूम हुआ है कि बंगालको भेजे जानेवाले सामानकी मात्रामें जुलाईके महीनेमें भारत-सरकारने संशोधन किया है। इसकी मात्रा कम कर दी गयी है। मैं कह नहीं सकता कि धारा-सभाके कितने सदस्य इस विषयकी जानकारी रखते हैं। शोचनीय संकटके मौकेपर खाद्यकी मात्रामें कटौती किये जानेपर बंगालका मंत्रिमण्डल क्यों सहमत हो गया? मन्त्रिमण्डलके लिये क्या और कोई राह न रही और क्या भारत-सरकार इस सम्बन्धमें और कोई बात ही सुननेको राजी न थी? मैं पूछता हूं कि मन्त्रिमण्डलने इस कटौतीके प्रस्तावको जी-जानसे रोका क्यों नहीं? बंगालको लेकर जिस वक्त यह अनाचार किया गया, तो उस वक्त आत्म-समर्पण न कर मन्त्रिमण्डलने पद-त्याग क्यों नहीं किया?

[सुहरावर्दी साहब बोले कि उनके एतराजपर भी यह कटौती की गयी है।]

सुहरावर्दी साहब फरमा रहे हैं कि बंगालके मन्त्रिमण्डलके एतराजपर भी कटौती की गयी है। यह सच हो, तो बंगाल जानना चाहेगा कि मन्त्रि-मण्डलने पहले यह व्यवस्था मान ही क्यों ली? उन्होंने यह कहा क्यों नहीं कि 'बंगालके लिये मंजूरशुदा अनाजकी मात्रामें कटौती होगी, तो हम पद-त्याग करनेमें ही श्रेय समझेंगे?'

सूबेके बाहरसे जो अनाज भीतर आया, उसके सम्बन्धमें हम सही-सही

हिसाब जानना चाहते हैं। बंगालके लिये जो अनाज मंजूर हुआ था, वह क्या सारा ही आ गया है? लाहौरसे लौटनेपर सुहरावर्दी साहबने कहा था कि नतीजा खूब ही सन्तोषजनक रहा। किन्तु उनके लौटनेके सिर्फ दो ही दिन बाद पंजाबके एक मन्त्रीने वक्तव्य दिया कि बंगाल-सरकार पंजाबसे जिन दामोंपर गेहूं खरीद रही है, उसकी अपेक्षा बहुत ज्यादे दामोंपर बंगालके भूखसे पीड़ित लोगोंके पास उसे बेच कर वह लाखों रुपयेका मुनाफा बना रही है।

इस्पहानी-कम्पनीको बंगाल-सरकारका सोल-एजेण्ट बनानेके मामलेमें मैंने उसे रोकनेकी मांग की, पर सिविल-सप्लाइज मन्त्रीने मुझपर तीव्र हमला किया है। नीचेकी बातोंके सम्बन्धमें पूरे-पूरे तथ्य मालूम करनेके लिये मैं मन्त्रि-मण्डलसे अनुरोध करता हूं—

(१) इस्पहानी-कम्पनीको कुल जो रुपया दिया गया है (अथवा पेशगी में जो दिया गया है) उस रुपयेको देनेकी तारीख और उसकी तादाद।

(२) गवर्नमेण्ट और इस्पहानी कम्पनीके बीच जो शर्त हुई है, उसकी नकल।

(३) बंगाल-गवर्नमेण्टकी ओरसे बंगालसे बाहरके जिन स्थानोंसे, जिन लोगों और एजेण्टोंकी मार्फत जिस तारीखको जिस कीमतपर इस्पहानी-कंपनीने अनाज खरीदा है, उसका विवरण।

साढ़ेचार करोड़से अधिक रुपया इस्पहानी-कम्पनीको दिया गया है। यह रुपया सुहरावर्दी साहबके व्यक्तिगत बैंकके हिसाबसे नहीं दिया गया; बंगालकी सरकारी तहबील (खजाना) से दिया गया है। अतएव जन-साधारणको

यह जाननेका हक है कि इस विपुल धनकी हरएक पाईका हिसाब ठीक-ठीक तरहसे रखा जा रहा है या नहीं। मन्त्रिमण्डलके साथ इस व्यवसायी-मण्डलके राजनीतिक-सम्पर्ककी बात याद रख कर इस विषयकी जरूरत विशेष रूपसे मालूम हो जायगी। हमें विश्वस्तसूत्रसे पता चला है कि बंगाल-सरकारको इस्पहानी कम्पनीने जिस कीमतपर चावल बेचा है वह उन-उन स्थानोंके प्रचलित भावसे बहुत ज्यादा था, जिन-जिन विभिन्न स्थानोंसे वह खरीदा गया था। इसके लिये सूक्ष्म अनुसन्धानकी आवश्यकता है। यह दोषारोपण या बदलेमें दोषारोपणकी बात नहीं। मन्त्रियोंमें सु-नामका अगर जरा भी अंश बाकी हो, तो मैं जो सब तथ्य जानना चाहता हूँ, उनका पूर्ण विवरण देना उनके लिये उचित होगा। मैं जो जानना चाहता हूं, वह लोक-हितसे मतलब रखता है। बहुत ही आपत्तिजनक तरीकेसे काम चलाया गया है, इसी एक बातसे उसका असली रूप प्रकट हो जायगा।

मन्त्रिमण्डलसे एक खतरनाक गलती हुई है—वह यह कि सामान खोजने-की व्यवस्था न कर मूल्य-नियन्त्रण जारी किया गया। गवर्नमेंटने पहले ही सारे सूबेका हिसाब ले लिया है, यह मान लिया जा सकता है। संचित माल पड़ा है, यह उनको मालूम होना जरूरी है। मालके आयातका सिलसिला जारी न रहनेपर मूल्य-नियन्त्रण कोई मायने नहीं रखता। अगर गवर्नमेंट खोजकर उसे बाहर नहीं निकाल सकती, तो उनका हिसाब-ग्रहण एक तमाशेकी बात ही रही है। असलियतमें उनकी अयोग्यता साबित हो चुकी है। मौजूदा वक्तमें भी गवर्नमेंटके एजेण्ट लोग नियन्त्रित दामोंपर और इससे भी अधिक दामोंपर चावल खरीद रहे हैं। जिन सब हिस्सोंको अनाज-रहित

घोषित किया गया है, वहांसे भी नियन्त्रित और उससे ऊंचे दामोंपर खरीद-दारी होनेकी खबर आयी है। स्थानीय कर्मचारी लोग भी खुलेआम यह कबूल कर रहे हैं कि अनाजकी भारी कमी रहते हुए भी अनाज नहीं मिल रहा है, यह समझ कर भी किसी प्रकारकी सहायता नहीं दी जा रही है। बंगालके तमाम हिस्सोंसे भयानक हालत होनेके समाचार आ रहे हैं। बाजार से चावल एकदम लोप हो गया है। अनगिनत लोगोंको भूखे ही दिन काटने पड़ रहे हैं। अगर बिना देरी किये इसको रोकनेकी कोशिश न की गयी, तो हालत रोक-थामके बाहर हो जायगी। समूचे सूबेको अनन्त दुर्गतिकी गोदमें ढकेल दिया जायगा। जरूरतके मुताबिक अनाज लानेकी जिम्मेदारी न लेकर गवर्नमेंटने जहां खरीददारी शुरू की है, वहां गड़बड़ीकी हालत पैदा हुई है।

सिर्फ चावलकी बात सोचनेसे ही काम न चलेगा; जिन सब जरूरी चीजोंके ऊपर मनुष्यका अस्तित्व निर्भर रहता है, उनमें प्रायः सभीकी कमी हो चली है। दृष्टान्तके तौरपर चीनीका जिक्र किया जा सकता है। वर्तमान समयमें चीनी पूरी तरहसे गवर्नमेंटके नियन्त्रणमें है। किन्तु बाजारमें चीनी के दाम नियन्त्रित मूल्यकी अपेक्षा बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों हुआ है? चीनी केन्द्रीय सरकारके द्वारा नियन्त्रित हो रही है। बंगालको दी जानेवाली मात्रा वहींसे तय होता है। बंगालकी चीनी सिर्फ बंगाल सरकारके चुने हुए व्यापारियोंके पास आती है। ये व्यापारी सिर्फ उन्हींको चीनी भेजते हैं, जिन्होंने बंगाल सरकारसे लाइसेंस पाया है। बाजारमें अथवा और कहीं भी ऐसा कोई तीसरा पक्ष नहीं, जो आकर नियन्त्रणमें गड़बड़ी डाल सके। इस

लिये यह बेखटके कहा जा सकता है कि इस मूबेमें चीनी मंगवानेवालोंका चुनाव देशवासियोंके हितोंके प्रति लक्ष्यकर नहीं किया गया, राजनीतिक और दलगत व्यापारकी ओर निगाह रखकर किया गया है। बिक्रीके लिये जिन लोगोंको लाइसेन्स दिया गया है, उनके सम्बन्धमें भी इसीके अनुरूप ढंग काममें लाया गया है। यह बात मैं नहीं कहना चाहता कि जिन्हें लाइसेंस मिला है, वे सब खराब लोग हैं। किन्तु जितने बड़े-बड़े आढ़तिये और छोटे-छोटे व्यापारी हैं, उनमेंसे कइयोंका चुनाव देशके हितोंका विचार कर नहीं किया गया है। मूल्य-नियन्त्रण चालू हुआ है, गवर्नमेंटने परिकल्पनाका कार्यक्षेत्रमें प्रयोग किया है, पर आम लोगोंके साथ उसका कुछ भी लगाव नहीं। सामान-के आयातके स्रोतपर सरकारी-नियन्त्रण कायम है, तब भी चोर-बाजार और मुनाफेकी तिजारत बेरोक-टोक चल रही है—तब भी बाजारमें चीनी नहीं मिल रही है।

कुछ दिन पहले एक व्यापारीने भारत-सरकारका एक आदेश-पत्र मुझे दिखाया। उन्हें सरसोंका तेल लानेको कहा गया है। सरसोंके तेलका नियन्त्रित मूल्य फी-मन ३७) रु० या ३८) रु० है। बंगाल-सरकारने ५०) मनके भावसे तेल मंगवाना चाहा।

[सुहरावर्दी साहब बोले कि सरसोंके तेलकी वही मंजूरशुदा दर है!]

सुहरावर्दी साहब कह रहे हैं कि बंगाल-सरकारने पचास रुपया कीमत मंजूर कर दी है। यह भी मजेदार बात है। भारत-सरकारने सरसोंके तेलकी कीमत ३८) रुपया मन स्थिर कर दी है, और मैंने अपनी आंखों उनका आदेश-पत्र देखा है कि वे पचास रुपयेके भावसे खरीदना चाहते हैं।

तो अब कौन चोर-बाजारकी सृष्टि कर रहे हैं? कौन अति-लाभका पथ प्रशस्त कर रहे हैं? एक ओर बंगालके मन्त्रिमण्डलकी व्यवस्था, और दूसरी ओर भारत-सरकारका नियन्त्रण-विभाग! इनके हाथोंमें बंगालके लाखों भूखसे पीड़ित लोगोंको बचानेकी कौन-सी सूरत हो सकती है?

बंगालमें मौजूदा वक्तमें जो वितरणका ढङ्ग चल रहा है, वह नितान्त असन्तोषजनक है। पिछले कुछ हफ्तोंसे यह प्रचार किया जा रहा है कि भारतके विभिन्न भागोंसे खाद्य-सामग्री आ रही है। खाद्य-सामग्री अगर सचमुच ही पहुँच रही है, तो सब वर्गोंके लोगोंमें उसका न्यायपूर्ण बंटवारा होना उचित है। इसके लिये गवर्नमेंटकी योग्यता और सच्चाईके ऊपर जो विश्वास रहना ज़रूरी है, वर्तमान गवर्नमेंटके ऊपर वह हम लोगोंमें नहीं रहा। बंगालको बचानेका एकमात्र उपाय है, मालके आयातके ऊपर पूर्ण-नियन्त्रण जमाना एवं जिनके ऊपर आम जनताका विश्वास है, ऐसे लोगोंके द्वारा वितरण-व्यवस्थाको चलाना।

लोक-कल्याणके लिये व्यवसायियों और आम लोगोंका आवाहन करना होगा, एवं गवर्नमेंटके ऊपर सब वर्गोंका पूरा-पूरा विश्वास होना जरूरी होगा। सरकारी कर्मचारियों, व्यापारियों और आम जनताके बीचसे अनाचार और बुराईका बेरहमीके साथ दमन करना होगा। जो सब अन्याय और दुर्नीति चल रही है, उसे ढूंढ़कर दूर भगानेकी जिम्मेदारी गवर्नमेंटके ऊपर है। अन्याय और दुर्नीतिको दूर भगानेके लिये हम दृढ़-संकल्प हैं—यह बात एक ओर मुंहसे कहकर और दूसरी ओर अन्य तरहसे उन्हें बढ़ावा दिया जाय, तो दण्ड देनेकी व्यवस्था अथवा डर दिखाना एकदम ही फिजूल हो जाते हैं।

बंगालमें बहुत असह्य गड़बड़ अवस्थाकी सृष्टि हो गयी है। सब दर्जेके लोगोंके सहयोगके बिना इस हालतसे उबरना असम्भव है। गवर्नमेंटकी परिकल्पना-हीन शासन-व्यवस्था जिस तरह चलायी जा रही है, उसमें संकट-मोचनका कोई उपाय न रहेगा। रोग और भूखसे जितने लोग मौतके मुंहमें जा पड़े हैं, उसका एक-सवां हिस्सा भी अगर लंदन, आक्सफर्ड या एडिनब्राके रास्तोंपर मरते तो इङ्गलैंडका हरेक आदमी गवर्नमेंटके ऊपर बिगड़ उठता; मन्त्रियोंको अधिकारकी गद्दीसे दूर हटा देता। किन्तु यहां खबरें दबा दी जाती हैं, औरोंपर झूठे मनोरथ आरोपित किये जाते हैं। जो मन्त्रियोंकी नालायकीका पर्दा फाश करते अथवा समालोचना करते हैं, उनके लिये जेलका फाटक खुल जाता है।

भीतर-बाहर मुझपर यह आक्रमण किया जाता है कि खानेकी मैं राज-नीतिक कलहका हथियार बनाकर काममें ला रहा हूं। यूरोपियन-दल, जो आज गवर्नमेंट-दलमें शामिल है, उनमेंसे बहुतोंने इस तरहकी आलोचना की है। भूतपूर्व मन्त्रिमण्डल खाद्य-समस्याके समाधानमें असफल रहा है, यह कहकर उसे गिरानेके लिये ही ये लोग छ महीने पहले संघ-बद्ध हुए थे। उस वक्त ये ही कहा करते थे कि देशवासियोंके कल्याणके लिये, लोक-हितके लिये, इस तरहका दल बनाया जा रहा है।

हम किसीसे भी दयाकी भीख नहीं चाहते। आज हमारा पहला कर्त्तव्य है बंगालको भिखारियोंका देश बनने देनेसे रोकना। लोगोंको खिलाकर कम से कम जिन्दा रखना होगा, इसमें सन्देह नहीं। किन्तु बंगालके आर्थिक-

जीवनकी फिरसे प्रतिष्ठा करने एवं हमारी भावी सन्तानको जरा और दुर्भाग्यके हाथसे बचानेकी कोशिशमें सरकार तिलभर भी विलम्ब न कर सकेगी।

खूब साफ तौरपर मैं अपनी बात कह रहा हूँ। खाद्यको हम राजनीतिक खिलवाड़की वस्तु नहीं बनाना चाहते। संकटको दूर करनेकी हम प्राण-पणसे चेष्टा कर रहे हैं। किन्तु हम समझते हैं कि मौजूदा वक्तकी विपज्जनक हालतके लिये गवर्नमेंटद्वारा बर्ती गयी नीति ही जिम्मेदार है। उस नीतिकी और गवर्नमेंटकी समालोचना हमें करनी ही होगी। राजनीतिक गुलामी ही हमारी मौजूदा आर्थिक गड़बड़ीका मूल कारण है। बंगालके ऊपर जो प्राण-घातक चोट पड़ रही है, वह चोट खाली प्रकृतिके हाथसे नहीं पड़ी है। इस आर्थिक गड़बड़ीकी जड़में है शासन-व्यवस्थाका राजनीतिक दोष। जबतक हम राजनीतिक और आर्थिक स्वाधीनताके अधिकारी नहीं हो जाते, तबतक इस समस्याका असल समाधान नहीं होगा। केन्द्र और सूबोंमें अगर यथार्थ क्षमतापूर्ण और जिम्मेदार राष्ट्रीय सरकार प्रतिष्ठित होती, तो भारतवर्ष और बंगालमें खाद्य-समस्याका समाधान बहुत आसानीसे हो सकता था।

किन्तु आजके इस अत्यन्त बुरे वक्तमें मैं इस भारी समस्याकी बात नहीं चलाना चाहता। दलगत राजनीतिक कलहकी बात भी नहीं उठाऊंगा। आज जो एक दल-विशेषकी गवर्नमेंट बंगालमें राज कर रही है, उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं। अगर यह गवर्नमेंट नौकरशाहीकी साझीदार बन बैठे और ब्रिटिश शासकवर्गके कुछेक प्रतिनिधि हमारे हितोंके प्रति उपेक्षा दिखा कर इस दलबन्दीके मामलेमें जकड़े हों, तो उसके लिये भी हम जिम्मेदार नहीं। हम बेधड़क कह सकते हैं कि खाद्य-परिस्थितिको संभालनेमें

असफल होकर इस सूबेका शासन करनेके नैतिक अधिकारसे गवर्नमेंट वञ्चित हो गयी है। गवर्नमेंट यह शिकायत कभी नहीं कर सकती कि विरोधी-दल समालोचना करनेमें ही वक्त काट रहा है। वास्तवमें हमारी रचनात्मक राये कदम-कदमपर उपेक्षित हुई हैं। इस समय एक ऐसी हालत आ गयी है कि गवर्नमेंट अपनी गलत नीति और करतूतोंके उलझे हुए जालमें अपने-आप ही फंस गयी है।

विरोधी-दल अकपट, सदिच्छा और सेवाका आग्रह लेकर सहयोगका हाथ बढ़ा रहा है। गवर्नमेंटकी नीति इस तरीकेपर निर्धारित हो कि जिससे वह सब दलों और सब वर्गोंके लोगोंको अपनानेके लायक हो सके। यह होनेपर, मौजूदा स्थिति सुधारनेके लिये हम यथासाध्य चेष्टा करनेको प्रस्तुत होंगे। किन्तु गवर्नमेंट अगर अपनी भेद-नीतिको काममें लाती चले और अपनी जिम्मेदारीपर परिकल्पनाको तैयार कर प्रबन्ध चलाये, तो हम वर्तमान समयकी तरह, जिस समय भी सहयोगको उचित समझेंगे, सहयोग करेंगे, और व्यापक हितके लिये जब विरोधको ठीक समझेंगे, तब कठोर विरोध करनेमें भी नहीं हिचकिचायेंगे।

वर्तमान समयका सबसे पहला कर्तव्य है मिलन और मानसिक एकत्व-बोध। जो लोग आज अधिकारके आसनपर आरूढ़ हैं, वे अगर अनुकूल आबोहवा तैयार कर सकें एवं देशके जो असली स्वामी हैं, वे खाली मुंहसे नहीं, कामके द्वारा दिखा दें कि बंगालको बचानेके कार्यमें, कमसे-कम सामयिक तौरपर ही सही, गवर्नमेंट और आम जनताके हितोंके ऐक्यकी स्थापना हुई है, तो सब राजनीतिक वितर्क रोककर हम सम्मिलित रूपमें इस सूबेकी धन-सम्पत्ति और जन-सम्पत्तिको एकत्र करनेके काममें लग जायेंगे।*

---

* १७ सितम्बर १९४३ को बङ्गाल धारा-सभामें दी गयी वक्तृता।

खुली चिट्ठी

सर जॉन हर्बर्टके बीमार होनेपर, उनकी जगह बिहारके गवर्नर सर टामस रदरफोर्ड बंगालके गवर्नर होकर आये। ७ सितम्बर सन् १९४३ को उन्हें यह खुली चिट्ठी भेजी गयी।

प्रिय सर टामस रदरफोर्ड ! बंगालके इतिहासमें अतिशय संकटकी घड़ीमें बिल्कुल अस्वाभाविक दशाके बीच, आप शासक होकर आये हैं। इस सूबेके रहनेवालोंकी भयानक गिरी हुई हालतके बीच, सेवा करनेके अकपट आग्रहको लेकर, संस्कार-मुक्त चित्तसे आप आये हैं, यही आशा कर आपको यह खुली चिट्ठी लिखनेका साहस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको आम जनताकी आस्था अर्जन करनी होगी, और सब तरहके भिन्न-भिन्न मतोंकी बात सुननी होगी; आप निजको नौकरशाहीका मुखिया अथवा मंत्रियोंके कार्यका निर्लिप्त दर्शक समझकर विचार न करेंगे।

इस सूबेका आज दिनका सबसे बड़ा जरूरी काम है, दलका खयाल न कर, सरकारी-गैरसरकारी समूची सम्पदा और जन-शक्तिको सार्वजनीन सेवाके आदर्शमें सजग कर देना। अतीत कालमें जो सब भूलें हुई हैं, उनकी आलो-

चना करना मेरा उद्देश्य नहीं। फिर भी भविष्यमें जिससे उनकी पुनरावृत्ति न हो जाय, उसके लिये जो जरूरी है, उतना तो हमें याद रखना ही होगा। नीचे लिखे विषयोंके सम्बन्धमें आप बिना देरी किये प्रत्यक्ष रूपसे ध्यान दें, इसीलिये आपसे यह अनुरोध है।

(१) अभाव और भूखके कारण जिससे लोगोंके प्राण और स्वास्थ्यकी हानि न हो, उसके लिये गवर्नमेंटको खाद्य और अन्यान्य जरूरी सामान ढोने की पूरी जिम्मेदारी ग्रहण करनी होगी। युद्ध और युद्ध-कार्यसे सम्बन्धित सब प्रकारकी व्यवस्था अटूट रखनेके ऊपर ही अबतक ज्यादा जोर दिया गया है। खास कर इसी कारण वर्त्तमान बुरी दशा आयी। गवर्नमेंट पहलेसे ही आम लोगोंके कल्याणकी ओर दृष्टि रखनेकी जिम्मेदारीके विषयमें सतर्क न हुई। गैर-फौजी आम जनताको बचाये रखना राष्ट्रकी पहली जिम्मेदारी है। युद्धके समय मुल्ककी आन्तरिक शान्ति और खुशहाली बहुत आवश्यक है। सिर्फ इसीलिये भी यह अनिवार्य है। भविष्यमें इस सम्बन्धमें कोई लापरवाही न होनी चाहिये।

(२) भारतवर्षके अन्य भागोंसे नियमित ढंगसे माल लानेकी व्यवस्था करनी होगी। भारत-सरकारने बंगालके लिये मंजूरशुदा खाद्यकी मात्रा कम कर दी है; उसे बढ़ाना होगा। पिछले ६ महीनेसे हम यही बात कहते चले आ रहे हैं कि भारतके बाहरसे—खासकर आस्ट्रेलियासे बंगालके लिये खाद्य-सामग्री मंगानेका प्रबन्ध करना होगा। यह प्रबन्ध आज तक भी क्यों नहीं किया गया, बंगाल यह बात जानना चाहता है। यदि देखा जाय तो अन्य स्थानोंसे आनेवाला अनाज जरूरतके मुताबित काफी नहीं। यह होनेपर भी

पिछले साल अन्तर्जातीय रेड-क्रासकी मार्फत यूनानने जिस तरह अनाज प्राप्त किया था, उसी तरह बंगालके लिये चावल पानेकी चेष्टा करनी चाहिये।

(३) व्यापार-सम्बन्धी रोकके कुण्ठित होनेके बाद आस-पासके हिस्सेसे बंगाल-सरकारने जिस तरहसे चावल खरीदनेकी कोशिश की थी, वह बहुत ही गलत था। बिना टेण्डर लिये, मुस्लिम लीगसे सम्बन्धित किसी कृपापात्र व्यापारी संस्थाको इस कामके लिये छांट लिया जाता है। उस संस्थाको आज तक चार करोड़ पचास लाख रुपया दिया जा चुका है। बंगाल-सरकारके हाथ, जिसे कमसे-कम दामपर यह चावल बेचा जाता है, उसके सम्बन्धमें कोई शर्त्त नहीं रखी गयी है, अथवा देशवासियोंके हितकी रक्षाके लिये किसी खास व्यवस्थाका अवलम्बन नहीं किया गया है। किसी तटस्थ विचारक-मंडल द्वारा इसकी जाँचपड़तालका प्रबन्ध करनेके लिये हम आपसे अनुरोध करते हैं। हमारा ऐसा विश्वास करनेका युक्तिसंगत कारण है; सारा काम-काज यथावत ढंगसे एवं बंगालके निवासियोंके हितोंकी ओर लक्ष्य रखकर परिचालित नहीं हो रहा है। अगर निरपेक्ष जाँचका प्रबन्ध हो तो हम यह दिखा सकेंगे कि वर्तमान मन्त्रिमण्डलने बंगालके प्रति किस तरह अन्यायपूर्ण आचरण किया है,—देशवासियोंके कल्याणका विचार न कर वह किस तरह दल-विशेषको अनुग्रह-वितरणमें तत्पर हुआ।

(४) बंगालके अन्दर अनाज इकट्ठा करनेके लिये सरकारद्वारा जो इन्तजाम किया गया है, हमें उससे खास तौरपर रंज हुआ है। पिछले जूनमें बंगालके अन्दर जो अति प्रचारित खाद्य-आन्दोलन हुआ था, उसकी बाबत आम लोगोंका क्या खयाल है, उसे आपलोगोंको मालूम करना होगा। आन्दोलनका

उनहत्तर

नतीजा आज भी प्रकाशित नहीं हुआ। हम दावा करते हैं कि वह बिना विलम्बके अब प्रकाशित हो। सरकारी हिसाबके मुताबिक किसी हिस्सेमें कमी और किसी हिस्सेमें बढ़ती तक है। यह बात जाननेका हमारे पास कोई उपाय नहीं! व्यापारी और बड़े-बड़े आढ़तियोंको भिन्न-भिन्न हिस्सोंसे ऊँचे दामोंपर बेरोक-टोक चावल खरीदने देकर बंगालको सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचाया गया है। देहातोंमें जो अनाज जमा था, इसके फलस्वरूप वह वहाँसे हट गया। असलमें सरकारी नीतिने ही इस तरहकी बेरोक-टोक खरीदारीको बढ़ावा दिया है। इससे बहुत व्यापक दुर्गतिकी सृष्टि हुई है। माल ढोनेकी ठीक व्यवस्था न किये बिना ही, गवर्नमेंटने मूल्य-नियंत्रण शुरू कर दिया। नियंत्रण आरम्भ होनेसे पहले बड़े-बड़े आढ़तियों और खरीददारोंको देशके भिन्न-भिन्न हिस्सोंमें घूम-घूम कर चावल और धान खरीदनेके लिये एक हफ्तेसे भी अधिकका समय मंजूर किया गया। इसका लाजिमी नतीजा हुआ चोर-बाजार और सट्टा-बाजारका जन्म। जहाँ भी सरकारने चावल खरीदा है, वहीं दुर्गति और मूल्य-वृद्धि दिखलाई दी। मैं यह अस्वीकार नहीं करता कि कमी वाले हिस्सोंका अभाव दूर करनेके लिये, गवर्नमेंटकी ओरसे खरीददारी न किये बगैर काम न चलता। किन्तु, गवर्नमेंटकी खरीददारोंके वास्ते अनाजके बाजारमें आने पर, आम लोगोंमें खाद्यके न्यायपूर्ण बँटवारेकी जिम्मेदारी लेनेके लिये भी उन्हें तैयार रहना होगा। वर्तमान सरकारी क्रय-नीतिमें जड़से सुधारकी जरूरत है। दिसम्बरके महीने अमन फसलका धान चलनेसे पहले यदि यह सुधार न हुआ, तो हमारी फिर खैरियत नहीं।

(५) वितरण-व्यवस्थाके विषयमें भी खोज करनेके लिये हमारा आपसे

अनुरोध है । मैं समझता हूं कि यह व्यवस्था विशेष रूपसे खराब है । सरकारद्वारा प्रचारित एक साम्प्रदायिक इश्तिहारके मुताबिक, स्थानीय कर्मचारी ही वितरणके लिये एजेण्टोंको नामजद करेंगे ! एजेंटोंको नामजद करते समय जिन सब बातोंका ख्याल किया जायगा, उनमें साम्प्रदायिक विचार खास तौरपर रखा जायगा । वितरणकी नीति निर्धारित करते वक्त सरकार अगर दलबन्दी अथवा साम्प्रदायिक बुद्धिसे चले, तो इसका फल खतरनाक होगा । सरकारने किस मात्रामें अनाज खरीदा है, अथवा जरूरी प्रयोजनके लिये रोककर रखा है, इसका हमें कोई इल्म नहीं । जो सामान बाहरसे आया है, उसके वितरण-प्रबन्धके सम्बन्धमें सही-सही जांच-पड़तालकी जरूरत है । 'इस सूबेके युद्ध-विभागका कितना अनाज-संग्रह है, तथा रेलवे और बड़े-बड़े व्यवसायी-मंडलोंने कितना माल जमा कर रखा है, यह भी मालूम नहीं ! भारत-सरकार कमीको पूरा करेगी, यह वचन देकर जमा मालका एक हिस्सा क्या गैर-फौजी (सिविल) आम जनताके कामके लिये छोड़ा नहीं जा सकता ?

(३) इस समय बंगालमें अनाजकी कमी है, इस बातमें कोई भी शक नहीं । अनाजकी कमी नहीं—इस बातकी जिम्मेदार मन्त्रियोंने पिछले कईएक महीनोंतक घोषणा कर, जिस तरह कीमती वक्त बर्बाद किया और लोगोंको चरका दिया, वह सचमुच ही बहुत अफसोसकी बात है । अमन धानके न चलनेतक सूबेको कितने अनाजकी जरूरत होगी, यह निर्णय करना एवं न्यायपूर्ण और विचारसंगत वितरण-व्यवस्थाको चलाना मौजूदा वक्तके लिये सबसे पहला फर्ज है । अनाजका आयात जब सीमाबद्ध हो, उस समय राश-

निङ्गका प्रबन्ध करना ही बाकी एक रास्ता है। दुख उठाने और कुर्बानी करनेके लिये लोग तैयार हैं, किन्तु किसी खास आदमीका विचार न कर सभीको स्वार्थ-त्याग करना होगा। ठीक ढङ्गसे चलायी हुई वितरण-व्यवस्था ही इसकी नींव होगी।

(७) बंगालके लोग आज जिस बेहालीमें पड़े दुख भोग रहे हैं, उसकी चिन्ताजनक हालतके विषयमें मैं कोई आलोचना नहीं करना चाहता। कल-कत्तेमें ही हम जो देख रहे हैं, वह यथेष्ट मार्मिक है। बंगालके भिन्न-भिन्न हिस्सोंसे जो खबरें आ रही हैं, वह और भी डरावनी हैं। एक वर्गके लोगोंकी हालत अत्यन्त शोचनीय हो चली है—ये हैं गरीब मध्यवित्त वर्गके लोग। ये लंगरखानेमें भोजन ग्रहण कर नहीं सकते। सरकारसे दान भी नहीं ग्रहण कर सकते। ये ही बंगालके राजनीतिक और सामाजिक जीवनकी रीढ़की हड्डी हैं। ये ही अगर दलित और दुर्बल हो जायँ तो इसका नतीजा खतरनाक होगा। गैरसरकारी संस्थाएँ उनकी दुर्दशाको दूर करनेके लिये अपनी ताकत भर चेष्टा कर रही हैं। भारतके कोने-कोनेसे हमने जो सहा-यता और सहानुभूति पायी है, उसने हमारे ऊपर गहरा असर डाला है। इन सब गैरसरकारी प्रयत्नोंका पूरा-पूरा समर्थन करना सरकारका कर्त्तव्य है। पर इस विराट समस्याके समाधानकी जितनी जरूरत है, गैरसरकारी प्रयत्न उसका मामूली हिस्सा ही कर सकते हैं। गवर्नमेंटको ही बाकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी होगी। सब श्रेणियोंके लोगोंका सहयोग लेकर काम करना होगा। बंगालका वर्त्तमान मंत्रिमंडल दल-विशेषका ही प्रतिनिधि है। उसके द्वारा किया आवेदन आम जनताकी सहायता और सहयोग पानेमें सफल न होगा।

यह मंत्रिमंडल जनताके एक बड़े हिस्सेका विश्वासपात्र नहीं, इस बातमें कोई सन्देह नहीं। जन-साधारणके हितोंकी रक्षाके काममें यह पूरी तरहसे असफल रहा है। इस पत्रमें मैं दलबन्दीके सवालको नहीं उठाना चाहता; किन्तु एक बातको याद रखनेका आपसे अनुरोध करूंगा। खाद्य-संकट सिर्फ प्राकृतिक दुर्योगके कारण नहीं पैदा हुआ; शासन-व्यवस्थाकी राजनीतिक गलती ही इसके लिये जिम्मेदार है। जो गवर्नमेंट सब लोगोंकी पूरी विश्वासपात्र हो और जो अनाज लाने तथा दामोंके पूर्ण नियंत्रणमें समर्थ हो, वही गवर्नमेंट इस अवस्थाका प्रतिकार कर सकती है। भारत-शासन विधानके अनुसार ऊंचे-ऊंचे अधिकारियोंके हाथमें जो असली सत्ता है, इस प्रकारकी सरकारके ऊपर, उनका भी पूर्ण विश्वास स्थापित करना होगा। अगर प्रतिनिधित्वपूर्ण राष्ट्रीय सरकार न बनायी जाय, या उस प्रकारकी राष्ट्रीय-सरकारके ऊपर विश्वास न किया जाय, तो ब्रिटिश सरकारके प्रतिनिधि-रूपमें, सामयिक व्यवस्थाके रूपमें, आपको ही समूची जिम्मेदारी लेनी होगी। खुद आप ही अपनी परिकल्पना और कार्यक्रम लेकर बंगालकी जनताके सामने आयेंगे। ब्रिटिश-सरकार अभीतक भी भारतवासियोंका मालिक होनेका दावा रखती है। अतएव एक सभ्य सरकारकी पहली जिम्मेदारीका पालन करनेके लिये शासक-वर्ग ही बढ़ कर सामने आयें।

(८) मैं आखिरमें जोर देकर यही कहना चाहता हूं कि लाखों आदमी गरीबीके अन्तिम स्तरपर आ पहुंचे हैं। इस बीच मौतोंकी तादाद भी डरावनी हो चली है। इनकी जानें बचानेके लिये बिना विलम्बके, जरूर ही अनाज मँगवानेकी आवश्यकता है। किन्तु, अनाज इकट्ठा करना ही अकेली

समस्या नहीं। बंगाली जिससे भिखमंगोंकी जातिमें परिणत न हो जायं, इस विषयमें हमें विशेष प्रबन्ध करना होगा। योग्य और दूरदृष्टि वाले कुछ लोगोंका गवर्नमेंटको पूर्ण सहयोग लेकर काम करना होगा। बंगालको आर्थिक ह्रास और विनाशसे बचानेके लिये एक दूरन्देशी कार्यक्रम तैयार करना होगा। सामयिक जरूरतको पूरा करनेके लिये हमारा जो यह उद्वेग है, उसके बीच समस्याकी दूर-प्रसारी दिशाको हम कहीं भूल न जायं। अधिक अनाज पैदा करनेके लिये सरकारी आन्दोलन एक बड़ी भारी असफलतामें समाप्त हो चुका है। इस विभागका फिर संगठन करने और इसे शक्तिशाली बना देनेकी बड़ी जरूरत है। केवल एक मिसाल देता हूँ ; जिला बर्दमानमें ही चार लाख एकड़ जमीन दामोदर नदीकी बाढ़में नष्ट हो गयी है। इस सारी जमीनमें बरसातका धान हो सकता था। कुछेक हफ्ते पहले इस बाढ़-पीड़ित हिस्सेसे लौटने पर, मैंने एक वक्तव्यमें कहा था कि अकटूबरके आखिर तक, पानीके उतर जानेके साथ ही साथ, इस बड़े भारी हिस्सेमें जौ, गेहूं और उड़द पैदा हो सकते हैं। इसके लिये बीज बांटनेका प्रबन्ध बिना देरी किये किया जाना जरूरी है। स्थानीय किसानोंने इस प्रकारकी मददके लिये हमसे कातर प्रार्थना की थी। गवर्नमेण्टने इस ओर कोई रचनात्मक प्रबन्ध नहीं किया। यह सिर्फ एक ही मिसाल है। जरूरत होने पर और भी अनगिनत मिसालें दी जा सकती हैं।

(९) इस पत्रमें और-और समस्याओंपर लम्बी-चौड़ी आलोचना नहीं करना चाहता। बच्चों और स्त्रियोंका उद्धार करना, बेघर लोगोंके लिये रहने का इन्तजाम करना, जो हजारों लोग मलेरियासे मौतके मुंहमें जा रहे हैं—

विशेषकर मेदिनीपुर जिलेमें—उनके इलाजका प्रबन्ध करना, इस तरहकी अन-गिनत समस्याएँ हैं।

(१०) मौजूदा वक्तमें देशके अन्दर अनुकूल वातावरण तैयार करनेकी खास जरूरत है। इसके लिये राजनीतिक व्यवस्था भी अनिवार्य है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप साहसके साथ सारे राजनीतिक कैदियोंको रिहा करें। इस मुसीबतके समय देशकी सेवा करनेके लिये उनकी प्रबल इच्छा है। छूटनेपर उन्हें यह मौका मिलेगा। मैं अपनी निजी जानकारीसे कह सकता हूँ कि अगर इस तरहकी व्यवस्था की जायगी, तो बंगालकी आर्थिक और राजनीतिक अवस्थामें अभूतपूर्व उन्नति होगी। हमारी और बहुत-से अन्य लोगोंकी यह राय है कि भारतवर्ष आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिसे स्वाधीन न होने तक, हमारी समस्याओंका स्थानीय समाधान न हो सकेगा। आपके स्वदेशके नर-नारी जिस धारणाको रखकर गर्व अनुभव करते हैं, हम भी ठीक उसी धारणाको रखते हैं—वह यह कि पूर्वमें हो या पश्चिममें, विदेशी प्रभुत्वको सहना किसीके लिये भी उचित नहीं। वर्त्तमान संकटपूर्ण अवस्थाकी असलियतको हम भूल नहीं रहे हैं; बंगालके लोगोंकी रक्षा करनी ही होगी। वे अगर गरीबी और भूखसे मर जायँ तो बंगालका भी अस्तित्व मिट जायगा।

(११) कर्त्तव्य बहुत कठिन है। गवर्नमेंट और आम लोगोंके हित अगर पूरी तरह एक ही हो जायँ, तभी इसका समाधान हो सकता है। आज अकपट सदिच्छा लेकर विरोधका अन्त करनेका समय आ गया है। भारत-वर्षमें जो शासन-व्यवस्था चल रही है, अच्छेसे-अच्छे शासक भी उसके जालमें

उलझ सकते हैं। आप किस तरह कार्य-परिचालन करेंगे, किस तरह कठोर कर्त्तव्य-पालनका कार्यक्रम सोच रहे हैं, यह मालूम नहीं। किन्तु यह बात कहकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ कि बंगालके लोगोंका यथार्थ रूपमें आवाहन करनेका साहस और राजनीतिक दूर-दृष्टि यदि आपमें हों, तो सभी सहयोगका हाथ बढ़ाकर मौजूदा संकटका समाधान करनेकी चेष्टामें सम्मिलित होंगे।

प्रतिकारका उपाय

—:-※-:—

हालमें बंगालके अन्दर जो दुर्दिन दिखाई दिया है, भारतवर्षके आधुनिक इतिहासमें वह अभूतपूर्व है। लगभग दो सदियोंसे फैली हुई गुलामीके फल-स्वरूप, मामूली समयमें भी, भारतवासी गरीबी और आंशिक भूखके बीच दिन बिताते हैं। इसपर आज बंगालमें और भी विषम संकट घिरा आ रहा है—युद्धकी चोट और भारी राजनीतिक दुर्भाग्य।

सन् ४३ का अकाल दैवी दुर्घटना नहीं है। यह ठीक है कि बाढ़ और तूफानसे कई जिलोंमें फसलको नुकसान पहुँचा है; किन्तु समूचे बंगालमें इकट्ठी जो दयनीय बीभत्सता दिखाई दी है, उसका अलग कारण है। चुगली और दोषारोपण इस निबन्धके उद्देश्य नहीं। ब्रिटिश-सरकार अभी भी भारतका मालिक होनेका दावा करती है। मैं चाहता हूं कि उसके उद्योगसे एक रायल कमीशन बैठे। निरपेक्ष और होशियार व्यक्ति उस कमीशनके सदस्य होकर अकालके मूल-कारणोंकी खोज करें। तब मालूम होगा कि नौकरशाही शासन-प्रणालीमें कितना खोट, कितना अनाचार और अयोग्यता है। ब्रिटिश सरकारके प्रतिनिधियोंके हाथमें जो असल सत्ता टिकी है, उनकी गैर-जिम्मेदारी

भी, उससे प्रकट हो जायगी। समझमें आ जायगा, प्रान्तीय स्व-शासन का छूँछापन। एक ओर है मन्त्रिमण्डल—उसकी जिम्मेदारी बहुत भारी है, किन्तु क्षमता कुछ नहीं। दूसरी ओर हैं लाट-साहब और नौकरशाही। वे सर्वशक्तिमान हैं, किन्तु जिम्मेदारीकी कोई बला नहीं! वाद-प्रतिवाद, आपसमें एक-दूसरेके प्रति दोषारोपण, काफी हुआ है। अगर सचाईका फैसला करना हो, तो जांच-पड़तालका भार देना होगा ऐसे सब सुयोग्य लोगोंके ऊपर, जो श्रद्धाके योग्य हों, देशवासी जिनके ऊपर पूर्ण विश्वास करें।

बंगालको बचानेके लिये हमने आवेदन किया था। उसके फलस्वरूप भारतके कोने-कोनेसे धारणातीत प्रत्युत्तर मिला है। सभी वर्गोंके लोगोंसे स्वतः उमड़नेवाली सहायताकी धारा बहती आ रही है। बंगालियोंके हृदय-को इसने गहरे तौरपर स्पर्श किया है। किन्तु मैंने बार-बार कहा है कि केवल जन-साधारणकी चेष्टासे मुसीबतका अन्त नहीं हो सकता। गवर्नमेंटका सबसे पहला काम है, देशवासियोंके लिये भोजन जुटाना। इस कर्तव्यका पालन करनेके लिये गवर्नमेंटको मजबूर करना होगा।

हमलोगोंकी कोशिशोंसे, कमसे-कम, दो काम हुए हैं। प्रथम यह कि बंगाल और दूसरे-दूसरे सूबोंमें, यहांतक कि भारतके बाहर भी, लोकमत तैयार हो गया है। खबरोंको दबाने और हालतको बहुत छोटा बनाकर दिखानेकी काफी चेष्टा हुई थी। किन्तु सत्य छिपा नहीं रहता। सारे सभ्य संसारकी नजर आज बंगालपर पड़ी है। भारतके ऊपर ब्रिटिश शासनके फलाफलको लेकर देश-विदेशमें कटु समालोचना हो रही है।

दूसरे, अबतक सरकारकी ओरसे बहुत मामूली कोशिश हो रही थी। सिर्फ हम यही सुनते चले आ रहे थे कि घर-घरमें खूब अधिक अनाज छिपा हुआ जमा पड़ा है। गैरसरकारी संस्थाओंके उद्योगसे मन्त्रिमण्डलका अब सुर बदला है। लोभी व्यापारियों और जमाखोर गृहस्थोंके मत्थे दोष मढ़ कर अब आगे जिम्मेदारी न मिट सकेगी। सरकारकी आंखें खुलवा दी गयी हैं कि देशवासियोंको बचानेकी पहली जवाबदेही उसीके ऊपर है। गवर्नमेंटको ओरसे अबतक खूब अधिक काम हुआ हो, यह बात नहीं। तब भी फायदा यह हुआ है कि सारी दुनियाके सामने अधिकारियोंको लगातार जवाब-देही करनी पड़ रही है। जनताका शासन करनेका जो दावा रखते हैं, जनताकी जीवन-रक्षाकी जिम्मेदारीसे वह किसी तरह भी छुट नहीं पा सकते।

बंगालकी समस्या आज बड़ी भयंकर है। केवल सदावर्त्त खोलनेसे इसका समाधान न होगा। देहाती हिस्सोंसे अनाज एकदम गायब हो गया है। पेटकी ज्वाला और दुर्दशासे खदेड़े जानेपर लोग देहात छोड़कर दलके-दल शहरकी ओर आ रहे हैं। उन्हें उम्मेद यह है कि शहरमें आनेपर खाना मिलेगा। मौतों और मृतप्राय लोगोंकी तादाद दिन-ब-दिन बढ़ रही है। लाखों स्त्री-पुरुष जीवनी-शक्तिकी आखिरी सीमापर पहुँच गये हैं। इनमें मध्यवित्तके भले परिवार भी हैं। बिना विलम्बके अगर उपाय न किया गया, तो वे एकदम ही बे-निशान हो जायँगे।

लोग घर-द्वार छोड़ बाहर निकल रहे हैं। बेघर होकर कौन कहां जा पड़ रहा है, यह ठीक नहीं। रिश्तेदारीके बन्धन टूटते चले जा रहे हैं। बंगालका सामाजिक और आर्थिक चौखटा तेजीसे टूटा जा रहा है।

उनासी

रोगी कंकालवत् बच्चोंने बंगालका भविष्य शंकामय कर दिया है। गैर-सरकारी संस्थाएं, जहांतक जल्दी मुमकिन है, सहायताका प्रबन्ध कर रही हैं। स्थानीय लोगोंके बीच भी उन्होंने अनुप्रेरणा जगा दी है। किन्तु अनाजके अभावने सारी कोशिशोंपर रोड़ा अटका दिया है। फिर अनाज ही अगर किसी तरह इकट्ठा हो जाय, तो उसे ढोनेके लिये सवारी न मिलनेसे उसे यथा-स्थान पहुंचाना भी कठिन हो उठा है।

सरकारकी ठीक की हुई व्यवस्थासे कोई खास काम हो सकेगा, यह मालूम नहीं होता। चार आदमियोंको लेकर आपसी तौरपर मिल-जुलकर काम करनेकी उसमें गुञ्जायश नहीं। किसी भी दामपर चावल खरीदना होगा—इस बेपरवाह नीतिका फल आज खतरनाक हो उठा है। बंगालमें अनाजकी बड़ी कमी है। इस हालतमें सरकारको सामान मंगवाने और बांटने, दोनोंका ही पूरा भार अपने ऊपर लेना होगा। ये दोनों काम इस तरह चलाने होंगे, जिससे अनाजके अभावमें किसी भी दर्जेके लोगोंको भूखा न रहना पड़े। किन्तु इसके लिये चाहिये, ऐसी गवर्नमेंट जिसके ऊपर देशके सभी वर्गोंका विश्वास हो; तभी जातीय कल्याणकी यह नीति सफल हो सकती है।

इस डरावनी हालतसे छुटकारा पानेके लिये मैंने अपनी परिकल्पना इसके पहले ही गवर्नमेंट और देशवासियोंके सामने उपस्थित कर दी है। कलकत्ता और आसपासके कल-कारखानोंवाले भागमें बंगालकी तमाम आबादीके सिर्फ सात फी-सदी लोग निवास करते हैं। बंगालके गांवोंकी संख्या प्रायः एक लाख है, जो पांच हजार यूनियन बोर्डोंमें विभक्त है। इसके अलावा म्यूनि-सपिल बोर्डोंकी संख्या भी प्रायः एक हजार होगी। यह विराट् देहाती हिस्सा

आज एकदम चावल-शून्य हो गया है। गांववाले तिल-तिलकर मौतका स्वागत कर रहे हैं। बंगालको बचानेके लिये इन पांच हजार यूनियन बोर्डों और एक हजार म्यूनिसिपल केन्द्रोंमें अविलम्ब चावल, आटा और दूसरी-दूसरी खानेकी चीजें भेजनी होंगी। हरएक केन्द्रमें मोटे हिसाबसे कमसे-कम हजार मन भेजकर (कुछेक शहरोंमें अधिक भेजनेकी जरूरत होगी) गवर्नमेंट जल्दी ही काम शुरू कर दे। स्थानीय सहायता और बाहरसे जो कुछ मिलेगा, उसके द्वारा लगातार इस प्रबन्धको मजबूत बनाना होगा। जरूरतके मुताबिक क्रमसे और भी माल लानेकी व्यवस्था रहेगी। राज्य और आम-लोगोंकी मिली-जुली चेष्टासे इस प्रकार व्यापक सहायता विलम्बके बिना अगर आरम्भ न की गयी, तो पौषके महीने अमनकी फसल आनेपर वह देश-वासियोंके काम न आ सकेगी। उसके संग्रह और वितरणमें गड़बड़ी फैलेगी, अकाल देशके बीच स्थायी हो जायगा।

हरएक केन्द्रमें सरकारी गोदाम होना चाहिये। एक जिम्मेदार सरकारी कर्म-चारी उसकी देखभाल करे। वह स्थानीय यूनियन बोर्ड या म्यूनिसिपल बोर्ड एवं खास-खास व्यक्तियोंकी सहायतासे, साम्प्रदायिक और दलबन्दीके सवालको जरा भी अमलमें न लाकर, मदद पहुंचानेका प्रबन्ध करेगी। लोग आज भोजनकी आशामें घर-द्वार छोड़ रहे हैं; इस प्रकारकी व्यवस्थासे इसे रोका जा सकता है। मुहताज गांववालोंके लिये जो अनाज-गोदाम खुलेगा, उसमें अनाजकी मात्रा जरूरतके मुताबिक काफी न होनेपर भी, इस तरहके इन्तजामके फलस्वरूप, आम लोगोंकी सामाजिक-चेतना जाग्रत होगी। गोदाम-को मजबूत बनानेके काममें वे ही आखिर सजग हो उठेंगे। अकालने बंगालकी

पहलेसे चली आती हुई जीवन-शैलीको नष्ट कर दिया है। सिर्फ इसी उपायसे उसकी पुनः प्रतिष्ठा सम्भव है।

कलकत्ता और अन्य कई-एक बड़े शहरोंके लिये अनाज-गोदाम पूरी तरह नये तरीकेसे बनाने होंगे। देहातोंको भूखा रखकर शहरोंको जिन्दा रखना, यह बात जिससे फिर कभी न हो सके ऐसा करना होगा।

अनाजके संग्रह और वितरणके सम्बन्धमें इस परिकल्पनाके खिलाफ सरकारी ओरसे दो आपत्तियां होंगी—प्रथम यह कि माल कहां है? दूसरे, (सामान ढोनेको) गाड़ियां आदि कहां हैं? गवर्नमेंटके पास किस परिमाणमें अनाज जमा है; आम लोगोंको यह कभी भी बताया नहीं जाता। पिछले दो महीनोंसे बंगालमें काफी माल आया है, किन्तु 'ततः किम' – यह तथ्य हमारे लिये एकदम रहस्याच्छन्न है। जिस किसी भी तरह हो, अनाज तो चाहिये ही। विभिन्न सूबोंसे—भारतके बाहरसे भी सरकार अविलम्ब अनाज मँगवानेकी व्यवस्था करे। लड़ाईके बहुत जरूरी प्रयोगसे बहुतसे व्यापार-मण्डलोंको पांच-छ महीनेका खाद्य जमा रखनेकी अनुमति दी गयी है। रेल-कम्पनी, पोर्ट-ट्रस्ट, कल-कारखानोंके मालिक और फौजी अधिकारियोंका सहयोग मांगा जाय कि वे जमा अनाजका कुछ अंश, आरजी तौरपर उधार देकर, राष्ट्रकी जान बचानेमें सहायता करें। अनाज-गोदामोंको फिर भर दिया जा सकेगा; पर लोगोंके प्राण चले जानेपर फिर कैसे लौटेंगे? नयी फसल आनेपर यह कर्जा चुका दिया जायगा। भारत-सरकार इस बातकी जिम्मेदारी ले। पिछले आठ महीनोंमें हमने बार-बार विदेशसे अनाज

लानेके लिये कहा है। यह प्रस्ताव खुलेआम हुआ है। इसके लिये कौन जिम्मेदार है, यह सोचकर देखनेकी जरूरत है।

पत्र-पत्रिकाओंके द्वारा बतलाया जाता है कि मित्र-राष्ट्रोंने अपार खाद्य-भाण्डार जमा कर रखा है। जो सब अभागी जातियाँ इस वक्त धुरी-राष्ट्रोंके अधीन हैं, उनके आजाद होनेपर उस सब खाद्यसे उनकी सहायता की जायगी! किन्तु हम सौभाग्यशाली आज ब्रिटिश-राजमें निवास करते हुए भी, हजारोंकी तादादमें मरते जा रहे हैं। उस विपुल खाद्य-भाण्डारका कुछ हिस्सा हमें क्यों नहीं दे दिया जाता?

कैनबरासे रूटरके तारसे (२८ सितम्बर, १९४३) मालूम होता है—

"कृषि और व्यापार-मंत्री मि० विलियम जोन्स स्कोलेने कहा है, कि मित्र-राष्ट्र अगर जहाज जुटा सकें, तो अकेला आस्ट्रेलिया ही, पीड़ित भारतके लिये जितना गेहूं चाहिये, उतना वह सब पहुँचा सकता है। रवाना करनेके लिये गेहूँ जमा किया रखा है; अब जहाज मिलनेकी ही बात है। जहाज मिलेंगे या नहीं, मित्र-राष्ट्रोंकी ओरसे इस सम्बन्धमें कोई आवाज नहीं सुनाई देती। आस्ट्रेलिया माल रवाना करनेके लिये तैयार बैठा है। अन्दाजन अस्सीसे लेकर इकासी मिलियन बुशल गेहूँ आस्ट्रेलियामें है। फिर कुछेक महीनोंके अन्दर नयी फसल भी तैयार होगी। अतएव हिन्दुस्तानको भेजनेके लिये काफी गेहूँ वहां है।"

मि० स्कोलेने कुछेक सप्ताह पहले एकबार कहा था कि भारतको पचास हजार टन गेहूँ रवाना किया गया है, जहाज मिलनेपर और भी रवाना किया जायगा।

अतएव पता चला कि अढ़ाई करोड़ मन गेहूँ आस्ट्रेलियामें जमा है।

भारतवर्षको गेहूँ रवाना करनेके लिये वह तैयार है। फिर भी जहाजका इन्तजाम नहीं हो रहा है। ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहे तो बंगालके इस संकटका अन्त कर सकती है। इच्छा हो तो रास्ता भी निकल आयगा।

मेरी परिकल्पनाके सम्बन्धमें दूसरी आपत्ति यह हो सकती है कि माल ढोनेके लिये गाड़ियोंकी कमी है—गांव-गांवमें खाद्य किस तरह पहुंचाया जायगा? किन्तु यह आपत्ति एकदम बेबुनियाद है। इसे जरूरी काम समझकर देखनेसे गाड़ियां वगैरहका अभाव न रहेगा। पन्द्रह दिनके लिये एक व्यापक कार्य-क्रम ग्रहण किया जाय। सारा साधारण काम-काज बन्द रखकर रेल, स्टीमर, नौका, मोटर, फौजी और गैर-फौजी लारी—यहां तक कि बैलगाड़ी तकको अनाज ढोनेके काममें लगा दिया जाय। बंगालके लाखों भूखोंके लिये अन्न-भाण्डार तैयार करना—इससे बढ़कर जरूरी काम वर्तमान समयमें और क्या है? आज अगर बंगालपर दुश्मनका हमला होता, तो गाड़ी वगैरहके अभावसे क्या हम चुपचाप बैठे रहते? अकाल और महामारी जापानी हमलेसे किसी कदर कम खतरनाक नहीं। इस मामलेको भी युद्ध-सम्बन्धी जरूरी काम मानना पड़ेगा। बंगाल आज प्रायः अन्तिम दशाको पहुंच गया है। अब भी अगर उसे बचानेकी अकपट आन्तरिक चेष्टा शुरू की जाय, तो सब वर्गोंके आम लोग सहायता देनेमें कंजूसी न करेंगे। जरूरत है—उद्यम, दूरदर्शिता और अदम्य इच्छा-शक्तिकी।

प्रतिदिन—प्रत्येक घड़ी इस वक्त बेशकीमती है। बंगालके भिन्न-भिन्न हिस्सोंसे दुख, दुर्गति और अभावके अत्यन्त डरावने समाचार आ रहे हैं। इस दारुण दुखके समय लोक-हितकी चेष्टामें नौकरशाहीकी अकर्मण्यता और

उदासीनताकी कहीं मिसाल ही नहीं। हम लोगोंपर दोषारोपण होता है कि इस खाद्य-संकटके मामलेको हम लोग राजनीतिक क्षेत्रमें खींच लाये हैं। वास्तवमें, राष्ट्रीय पराधीनताके कारण ही तो भारतवर्षकी यह आर्थिक दुर्दशा हुई, एवं इसी कारण बंगाल आज दुर्गतिकी चरम सीमाको पहुँच गया है।

खाद्यको हम किसी तरह भी राजनीतिक खेलवाड़की चीजमें परिणत करना नहीं चाहते। किन्तु जब मालूम होता है कि इस अकालका मूल-कारण है शासकवर्गकी त्रुटि और नासमझी, तो उस बातको कहकर, गलत नीतिको बदलनेका दावा करना, क्या भारतीय होनेके नाते हमसे महापाप हुआ है?

अङ्गरेज इस अवस्थामें पड़ते तो इङ्गलैण्डमें आज क्या होता? भूख, महामारी और मौतसे पीड़ित अगर इसी प्रकार एक काउण्टीसे दूसरी काउण्टी और एक शहरसे दूसरे शहरतक झुण्डके-झुण्ड नर-नारी मरियल होकर डोलते फिरते, ठठरी-जैसे नंगे बच्चोंके आर्त्तनादसे लन्दनके रास्तोंपर अगर ऐसे ही मरघटकी छाया छा जाती, हाइड-पार्क, हैम्पस्टेड-हीथके ऊपर मल-मूत्रसे गन्दे जमीनके बिछौनेपर सैकड़ों शव पड़े रहते, तो डाउनिंग-स्ट्रीटकी क्या दशा होती? कैबिनेट कितनी देर टिकता?

भारतवर्षकी आज क्या हालत है? लड़ाईके धन्धेमें लगे हुए मुट्ठी-भर भाग्यवानोंको छोड़कर बाकी सारे देशवासियोंकी अवस्था मार्मिक हो गयी है। हमारा जातीय भविष्य अन्धकारमय है। फिर भी इस दुर्गतिके

विरोधमें एक उंगली भी उठानेकी क्षमता किसीमें भी नहीं ! देश-प्रेमी हजारों नर-नारी जेलखानोंमें बन्द हैं। और इसके ऊपर है हमारा अस्तिमज्जागत भाग्यवाद--सब दुःख-दुर्दशाके लिये हम दुस्तर नियतिको जिम्मेदार मानते हैं ! इन्सान ही हमारे जन्मसिद्ध अधिकारोंको रोके खड़ा है, इस निर्मम सत्यको हम भूल जाते हैं। राजनीतिक पराधीनता, आर्थिक संकट, चित्तकी कमजोरी, बुद्धिकी जड़ता—सारी बाधाओंको लांघकर भारतवर्षको आज नवीन संजीवनी-मंत्रकी दीक्षा लेनी होगी।

———

संग्रह

—:-०-:—

टाउन हॉलमें दी गयी वक्तृता (६ जून; १९४३)

मंत्रिमण्डलको शासनाधिकार पाये सात महीने हो चले, फिर भी खाद्य-समस्याके समाधानमें वह कोई सम्पूर्ण नीति आजतक भी आम जनताके सामने न रख सका। यह दुखकी बात है। बंगालमें अनाजका असलमें अभाव नहीं, बार-बार यही यथार्थ-विरोधी बात कह उसने (मंत्रिमण्डलने) काफी नुक-सान पहुँचाया है। आम लोगोंके लिये कमसे-कम खाद्य जुटाना सरकारकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। बंगाल और भारतवर्षका यह शोचनीय दुर्भाग्य है कि यहां लाखों देशवासियोंके हितोंकी ओर निगाह रख सरकारी खाद्य-नीति निर्धारित नहीं होती। अनेकों भारतवासी अमन-चैनके वक्त भी सारे साल आधा पेट खाकर रहते हैं। जो लड़ाई-सम्बन्धी व्यापारमें जुटे हैं, उनकी जरूरतोंकी ओर अत्यन्त अधिक जोर देकर गैर-फौजी अधिवासियोंके हितोंकी उपेक्षित किया गया है। बंगालके मंत्रियोंने जो युक्तिहीन घोषणा की, उसीकी वजहसे पार्लामेंटमें मि० एमरी यह कह सके कि अनाज जमा करनेके कारण ही खाद्य-संकट आ पड़ा है। दोष इस प्रकार गवर्नमेंटके कंधेसे पीड़ितोंके

ऊपर थोप दिया गया। कुछ परिमाणमें गल्ला जमा हुआ है, इसे मैं अस्वी-कार नहीं करता। किन्तु जो सब बड़े-बड़े आढ़तिये और मुनाफाखोर सरकारी सहायताके बलपर बढ़ते जा रहे हैं उन्होंने ऊंचे दामोंपर अनाज खरीद कर बाजारमें गड़बड़ी डाल दी है। आगामी खाद्य-आंदोलन उनके खिलाफ न चल कर, जमा अनाजकी खोजमें देहातोंमें चलेगा।

जमा हुए अनाजके परिमाणका निर्णय करना सच ही बहुत जरूरी है। किन्तु खोज होनेसे पहले ही देहातोंमें काफी जमा माल है, अथवा जैसा कि एक सरकारी इश्तहारमें कहा गया है कि एक श्रेणीके लोग गरीबोंको पीस रहे हैं—इस तरहकी धारणा लेकर काममें लगना एकदम अन्याय है। संचयका नाम-निर्देश किया गया है, किन्तु शिक्षा, चिकित्सा और धर्ममें हरएक कुनबे का जो सब जरूरी खर्चा होता है, उसके सम्बन्धमें कोई विचार नहीं किया गया। यहां-वहां कहींपर दो-एक हजार मन अनाज मिल जानेसे भी समस्याका कोई हल नहीं निकलेगा। अनाज कुछ खास मिलेगा, ऐसा नहीं मालूम होता; लोगोंकी परेशानी ही इससे बढ़ेगी। विश्वास-योग्य लोगोंके द्वारा हिसाब ग्रहण करनेका प्रबन्ध हो। हिसाब-ग्रहण जब तक पूरा न हो जाय, मुनाफा उठानेकी नीयतसे माल जमा किया है, यह बात पूरी तौरपर साबित जब तक न हो—गृहस्थोंके स्वल्प-संचित अनाजको तबतक ले लेना अनुचित होगा।

मौजूदा मंत्रिमण्डल मि० जिन्ना और पाकिस्तानके प्रति अनुसरणके बन्धनसे बँधा है। लड़ाई और एक बड़े खाद्य-संकटके रहते हुए भी वह बंगालके विभिन्न हिस्सोंमें पाकिस्तान सम्मेलनोंका आयोजन कर रहे हैं।

किन्तु भाग्यके मजाकसे, उन्हींको कल्पित पाकिस्तानके बाहरी सूबोंसे, अनाजकी सहायताके लिये दौड़-धूप करनी पड़ रही है! पाकिस्तानकी आर्थिक व्यर्थता समझ कर, मुसलिम लीग मंत्रिमंडल, इस संकटके मौकेपर क्या अपनी भेद और अनैक्य-सूचक कार्यावलीसे विरत होगा?

पूर्वी अंचलमें वाणिज्यकी बाधा दूर हो गयी है। किन्तु आस-पासके हिस्से डर गये हैं कि अकाल-पीड़ित बंगाल बहुत ऊँचे दाम लगाकर उनका सारा अनाज खींच लेगा; अकाल उनके बीच भी फैल पड़ेगा। इन सब हिस्सोंमें कुछ हद तक सहायता आयगी, इसमें सन्देह नहीं; किन्तु मंत्रिमण्डल अब भी इस विषयमें किसी निश्चित सिद्धान्तपर नहीं पहुँच सका है।

देहातोंमें ऐसे सब लोगोंके बीच खाद्य-आन्दोलन चलेगा, जो खुद ही अभाव और मुसीबत भोग रहे हैं। इसपर भी बड़े-बड़े आढ़तियों और मुनाफाखोरोंको सूबेके जिस किसी भी हिस्सेसे, जिस किसी भी दामपर, बेरोक-टोक चावल खरीदनेको अनुमति दे दी गयी है! दरिद्र कुनबेवाले लोगोंके उपकारार्थ हरएक हिस्सेको स्वावलम्बी बनानेकी परिकल्पना हुई है! यह किस तरह मुमकिन हो सकेगा, यह हमारी समझसे बाहरकी बात है।

अभी हाल कुछेक हफ्तोंसे बंगालके बाहरसे चावल खरीदा गया है; उसका पूरा हिसाब लेना जरूरी है। किस कीमतपर किसके द्वारा यह चावल खरीदा गया है? यह चावल बेच कर बेचने वाला जिससे नाजायज मुनाफा न ले, उसके लिये सरकारने क्या प्रबन्ध किया है? हम इसका जवाब चाहते हैं। जिन सब व्यापारियोंने बंगालके बाहरसे कम दामोंपर चावल खरीदा है, गवर्नमेंटने क्या उनको ज्यादे दाम दिये हैं? गवर्नमेंटका

साफ-साफ फर्ज यह है कि बाहरसे आनेवाले चावलके ऊपर पूर्ण नियंत्रण जमायें और पीड़ित हिस्सोंमें नियंत्रित-दुकानोंकी मार्फत, जिससे वाजिब दामोंपर वह बिके, इस बातका प्रबन्ध करे।

अधिक खाद्य-उत्पादन आन्दोलन फैले, यह सभी चाहते हैं। विभिन्न हिस्सोंसे खबर आ रही है कि लोगोंने अगली फसलका बीज खा डाला है। बीज नहीं मिल रहा है। जिससे यह शोचनीय बातें न हो सकें, जल्दी ही इस बातका इन्तजाम करना गवर्नमेंटको उचित है। लोग चावलके बदले दूसरा अनाज खायें, गवर्नमेंट इस बातके लिये प्रचार कर रही है। कमसे-कम उन सब दूसरे अनाजोंको जुटानेके सम्बन्धमें गवर्नमेंटको भरोसा दिलाना होगा, नहीं तो प्रचार-कार्य फिजूल हो जायगा। चावलके बदले आटा खानेको कहा जा रहा है। इसलिये गेहूं कई गुना अधिक बढ़ाकर मँगवाना होगा। केन्द्रीय सरकार बंगालको बाईस लाख टन गेहूं देना चाहती है। मौजूदा मुसीबतसे बचनेके लिये, बंगालको कमसे-कम दस लाख टन गेहूं और ऊपरसे जरूरी होंगे। जो गेहूं मंजूर हुआ है, वह आखिर बंगालमें पहुँचेगा कि नहीं, और अतिरिक्त गेहूं भेजा जायगा या नहीं, इस सम्बन्धमें गवर्नमेंटकी ओरसे हम साफ-साफ जवाब चाहते हैं। जरूरत होने पर समुद्र-पारसे गेहूं मँगानेका प्रबन्ध करना होगा। साधारण समयमें भी मुल्ककी पैदावारसे हमारी जरूरत पूरी नहीं होती। इस समय लड़ाईके सिलसिलेमें और समुद्र-पारके देशोंको अनाज रवाना करनेसे हम और भी कंगाल हो गये हैं।

बरमामें अंगरेजोंकी हार हमारी दुर्गतिका प्रधान कारण है। बरमासे चावल नहीं आ रहा है। इसके लिये कोई दूसरी व्यवस्था करनी होगी। बंगालके

लड़के

अनाजको मित्र-राष्ट्र युद्धके प्रयोजनके अन्दर गिनकर विचार करेंगे। शासक-वर्गको यह बात याद रखनी जरूरी है कि बंगाल की मुसीबत मित्र-शक्तियोंकी उद्देश्य-प्राप्तिमें अनुकूल न होगी। इस सूबेमें अनाजका अभाव नहीं, लोगोंका अति संचय ही वर्त्तमान संकटका कारण है—मंत्रिमंडल इस बातकी घोषणा कर समस्याको जटिल बना रहा है। इस तरह इच्छा-निर्मित आत्म-प्रतारणासे वह विरत हो।

एक बात मंत्रिमंडलको विशेष रूपसे याद कराये देता हूँ। खाद्य-आन्दोलन चलानेका उसने संकल्प किया है, किन्तु यह आन्दोलन कहीं किसी तरह राजनीतिक या दलबन्दीके उद्देश्यको पूरा करनेमें न चले। बंगालके हरएक यूनियनमें मुसलिम-लीगकी शाखा संगठित करनेके लिये बंगाल प्रांतीय मुसलिम लीगसे एक इश्तहार हालमें जारी किया गया है। फिर इस ओर हर-एक दो थानोंमें एक खाद्य-कमेटी बनानेकी व्यवस्था हो रही है। लीगकी उपरोक्त प्रचेष्टाके साथ इस मामलेका कोई सम्पर्क है कि नहीं, यह मैं नहीं कह सकता। खाद्य-कमेटियाँ जिससे सचमुचमें प्रतिनिधिमूलक हों, जिससे किसी तरह दलबन्दीकी या सांप्रदायिक असन्तोषकी सृष्टि न हो सके, देशवासियोंको इसके लिये हमेशा सजग रहना होगा। इस परिकल्पनाके सम्बन्धमें विभिन्न दलों और संस्थाओंका मत ग्रहण करनेकी मंत्रिमंडलने जरूरत महसूस नहीं की। वर्त्तमान संकटके समयमें भी वह खाली दलगत स्वार्थ और दलके अनुसरणकी ही बात सोच सकते हैं। उनके लिये जनताको ऐक्यबद्ध करना और आम लोगोंमें खाद्य-नीतिके सम्बन्धमें उत्साहका संचार करना एकदम असम्भव है।

आप लोगों और गवर्नमेंटके हित अगर एक न हों, तो खाद्य-समस्याका

कोई समाधान नहीं हो सकता । असली तथ्य जिससे छिपाये न जायँ, इस सम्बन्धमें हमें भरोसा देना होगा । जरूरत होनेपर गवर्नमेंटकी नीति और कार्यकलाप आम जनताको बताने होंगे । मालका ठीक-ठीक आयात और वितरणको छोड़ इस संकटको टालनेका और कोई उपाय नहीं । उसके लिये राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था आवश्यक है । सम्मिलित रूपमें हम उसका दावा पेश करेंगे ।

वक्तव्य (२४ अगस्त, १९४३)

बर्दमान और नदियामें बाढ़ और अकाल--पीड़ित कुछ हिस्सोंको देखकर चार दिन बाद मैं अभी वापस आया हूं । जो दृश्य देख आया हूं और विश्वस्त सूत्रसे विनाश, दुर्गति और भुखमरीके जो संवाद मुझे मिले हैं, वह बहुत ही भयावह हैं । गवर्नमेंटने जो सेवा-कार्य आरम्भ किया है, जितनेकी जरूरत है, उसके मुताबिक वह बहुत ही मामूली है । विभिन्न गैर-सरकारी संस्थाएँ लोगोंके दुख-निवारणकी चेष्टा कर रही हैं, किन्तु उनकी ताकत सीमित है । और भी आवश्यक बात यह है कि वे अनाज इकट्ठा करनेमें समर्थ नहीं हो रहे हैं । अनाज न मिले तो लोगोंकी भूख कैसे मिटे ? बेशुमार नर-नारी भूखे मर गये हैं ; लोग अपने बच्चों और अपने पाले हुओंको बेच रहे हैं और छोड़ रहे हैं । चारों ओर असहाय अवस्था फैली हुई है ।

भूख और कम गिजा मिलनेसे लोगोंकी जीवनी-शक्ति इतनी कम हो गयी है कि जल्दी ही अगर ठीक प्रबन्ध न हुआ तो बंगालका सर्वनाश हो जायगा । आश्रयहीन लोग भिखमंगे बन रहे हैं । और एक श्रेणीके लोगोंके लिये कोई प्रबन्ध नहीं हो रहा है; ये हैं गरीब मध्यवित्त श्रेणीके लोग ।

लंगरखानेमें आकर ये भोजन नहीं ग्रहण कर सकते, भीख नहीं ले सकते। एक ही रास्ता इनके सामने फैला हुआ है—भूखसे तिल-तिल करके मृत्युको वरण करना।

देशके विभिन्न भागोंमें अनेक गैरसरकारी सहायता-समितियां संगठित हुई हैं। इस तरहकी कई समितियोंको मैं देख आया हूँ। वे सबकी-साथ सहयोगसे काम करें, और दो बातोंका विशेष प्रकारसे खयाल रखें। प्रथम यह कि सरकारकी तरफसे जो सहायताकी चेष्टा हो रही है, उसकी ओर सतर्क दृष्टि रखनी होगी, कि वे लोक-हितके मुताबिक चलायी जायें। दूसरे यह कि स्थानीय लोगोंसे जहांतक सम्भव हो, पैसा और सामान इकट्ठा करना होगा। स्थानीय सम्पद एकत्र कर सहायताका प्रबन्ध व्यापक बना देना होगा।

मैंने बार-बार कहा है कि आम लोगोंके लिये भोजन जुटानेकी पूरी जिम्मेदारी गवर्नमेंटको ही अपने ऊपर लेनी होगी। जन-साधारण अपनी ताकतके मुताबिक उसमें सब तरहसे सहयोग देंगे। गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है वह बहुत ही मामूली है। अनेक आयोजनोंके पीछे कोई परिकल्पना नहीं। नीचे बताये तरीकेसे गवर्नमेंट नीति परिचालन करे; इसके लिये जन-साधारणकी ओरसे दावा पेश करना होगा :—

(१) जिन सब जिलोंमें तीव्र अन्नाभाव है, अभी भी वहांसे चावल खरीदकर अन्यत्र ले जाया जा रहा है। पिछले जूनके महीनेका अनाजका हिसाब-ग्रहणका नतीजा अबतक गवर्नमेंटने प्रकाशित नहीं किया। खाद्य-आन्दोलनके समय कमीवाले हिस्सोंसे भी चावल दूसरी जगहोंको भेजा गया है। वर्द्धमानकी भयंकर बाढ़के बाद भी उस जिलेसे हजारों मन चावल बाहरको

ढोया गया है ! नवद्वीप और कृष्णनगरसे भी इसी तरहकी खबरें आयी हैं। जिन सब हिस्सोंमें लोग भूखसे मर रहे हैं, वहांसे भी ऊंचे दामोंपर धान-चावल खरीदकर धनी व्यवसायी एवं मिलिटरी-कंट्रैक्टर लोग बाहरको ले जा रहे हैं। इस सम्बन्धमें हमारे पास अनेक मार्मिक शिकायतें आयी हैं।

घोषणा की गयी है कि गवर्नमेंट बरसातका अतिरिक्त धान खुले बाजारसे खरीदेगी। इससे सभीके मनमें अवर्णनीय आतंक और असन्तोषकी सृष्टि हुई है। इस घोषणाके मुताबिक काम होने पर जो विनाश और गड़बड़ीकी हालत दिखलाई देगी उससे उबरनेकी उम्मीद बाकी न रहेगी। हम बराबर कह रहे हैं कि गवर्नमेंट अनाज खरीदनेकी जरूरत महसूस करे, तो सब श्रेणीके लोगोंको खाना देनेकी पूरी जिम्मेदारी ले ले, तभी वह ऐसा कर सकती है। किस हिस्सेमें अनाजकी कमी है या कहां कितना ज्यादा है, उसके सम्बन्धमें गवर्नमेंटका हिसाब हमें मालूम नहीं। मैं मंत्रिमण्डलको सतर्क किये देता हूं कि अगर वह जिद्द करके बेपरवाह खरीदारीकी नीति चलाते रहे तो हालत बहुत भयंकर हो जायगी। बाढ़से पीड़ित हिस्सोंमें लोग बेहालीकी आखिरी हद तक पहुंच गये हैं। उन सब हिस्सोंसे चावल बाहर ले जाना एक-दम बन्द करना होगा।

(२) पश्चिम बंगालमें गवर्नमेंटने जो सब लंगरखाने खोले हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। हमारा दावा है कि मेदिनीपुर और बर्दमानके हरएक गांवमें एक या अधिक लंगरखाने खोलने होंगे। अन्य दुर्गतिवाले हिस्सोंमें भी हरएक यूनियनमें कमसे-कम एक-एक लंगरखानेकी सख्त जरूरत है। उन सब हिस्सोंमें गैर-सरकारी सहायताका प्रबन्ध हो रहा है, प्रस्तावित सर-कारी प्रबन्ध उसके अतिरिक्त होगा।

(३) बेघर नर-नारीकी झोपड़ियोंकी मरम्मत करवानेका प्रबन्ध नहीं हुआ। जो सहायता दी जा रही है, जरूरतके मुताबिक वह कुछ भी नहीं है।

(४) गैर-सरकारी संस्थाओंको नियमित रूपसे गवर्नमेंटसे सस्ता चावल नहीं मिल रहा है। यह मामूली सहायता हरएक संस्थाको मिलना चाहिये। जो काम ये लोग कर रहे हैं, असलमें यह गवर्नमेंटको ही करना चाहिये था।

(५) बहुतसे मध्यवित्त कुलबोंको उपवास करना पड़ रहा है। उनको सहायता पहुँचानेकी कोई व्यवस्था नहीं है। सहायताका प्रबन्ध कर इन्हें बचाना होगा। जिन सब गैरसरकारी संस्थाओंने एक दिशामें काम शुरू किया है, सस्तेमें अनाज पहुँचाकर गवर्नमेंट उनकी सहायता करे।

(६) चिकित्सा-सम्बन्धी सहायताकी भी जरूरत है। मलेरिया और पेटकी पीड़ाके लिये व्यापक तौरपर इलाजके प्रबन्धकी आवश्यकता है। कपड़े बांटनेके लिये कोई व्यवस्था नहीं। वस्त्रहीन असंख्य लोग—उनमें स्त्रियाँ भी हैं—लाज ढँकनेकी कोई साधन नहीं पा रहे हैं।

(७) कृषि-ऋण दिया जा रहा है; किन्तु बीज कहांसे मिले, लोगोंको यह मालूम नहीं। इस विषयकी सरकारी परिकल्पना जन-साधारणको शीघ्र ही बतलानेकी बड़ी जरूरत है। अकेले बर्दमान जिलेमें ही तीन लाख एकड़ जमीनका असनका धान बाढ़में नष्ट हुआ है। इस ज़मीनमें जल्दी ही फिर से काश्तकी व्यवस्था करनी होगी। अक्टूबरके आखिर तक जल उतर जायगा। तब गेहूँ, जौ, चना और उड़द पैदा करनेके लिये, काफी मात्रामें बीज मिल जाय, इस बातका इन्तजाम करना होगा। जमीन खूब उर्वर है; गेहूँकी खेती के लिये वह खासकर कामकी है। इस विशाल हिस्सेमें काफी अनाज पैदा हो

सकेगा। अगर शीघ्र ही अच्छा प्रबन्ध न किया गया तो छ महीने बाद बर्द्धमानको अधिकांशमें खतरनाक अवस्थाका सामना करना होगा। जहाँ-जहां मैं गया हूँ, स्थानीय विशिष्ट लोगोंसे मैंने इस सम्बन्धमें आलोचना की है। किसानोंको बीज इकट्ठा करनेमें दिक्कत हो रही है। इसके लिये सभीने व्याकुलता प्रकट की। कईएक गैरसरकारी संस्थाओंके साथ मैं इन्तजाम कर आया हूं कि वे इसकी बाबत खास तौरपर कोशिश करेंगे। गवर्नमेंटसे एक बड़ा अनुरोध यह है कि बीज-संग्रह और वितरणके सम्बन्धमें परिकल्पना स्थिर कर, बेहाल आम जनताको वह शीघ्र ही बतला दी जाय।

लाखों भूखसे पीड़ित लोगोंके लिये बहुत जल्दी भोजन जुटाना ही असली समस्या है। गवर्नमेंट जन-साधारणकी बगलमें आकर खड़ी नहीं हो सकती। वर्तमान मन्त्रिमण्डल, स्थायी सरकारी कर्मचारी लोग और भारत-सरकारमें आजकी इस हालतके लिये किसकी कितनी जवाबदेही है, उसकी इस समय आलोचना नहीं करना चाहता। चावलकी भारी कमी हो चली है। जो चावल मौजूद है, उसका सब श्रेणियोंमें सम-भावसे बँटवारा करनेकी जरूरत है। जिन हिस्सोंमें कमी है, गवर्नमेंट उन स्थानोंसे बहुत जल्दी सामानका निर्यात बन्द करे। आम लोगोंके पेट भरनेकी जिम्मेदारी लिये बगैर उसे बिलकुल ही चावल खरीदना उचित नहीं। बंगालमें जो संकट दिखलाई दिया है, वह रोजमर्रा बढ़ता ही जा रहा है। देशके नर-नारी सब प्रकारकी वस्तुएं— चाहे वह कितनी ही मामूली क्यों न हो—बेहाल लोगोंको बचानेके लिये इकट्ठी करें। लोकमतको जगा दें, जिससे गवर्नमेंट आम लोगोंके प्रति अपना फर्ज अदा करे। निडर होकर इसका दावा करना होगा। इस देश

और इङ्गलैंडकी गवर्नमेंट समझे कि भूखा-प्यासा बंगाल उन्हींके अपने हितके प्रति विपदका कारण हो सकता है। भारतके और-और हिस्सोंसे, खासकर बहिर्भारतसे—अनाज मंगवानेसे शीघ्र ही इस अवस्थाका अन्त हो सकता है।

देशके शासनके काममें हम देशवासियों और शासकोंके बीच शोचनीय स्वार्थ-विरोध देखते आ रहे हैं। इस स्वार्थको पूरी तरह एकीभूत करके गवर्नमेंट अगर साहस और दृढ़-संकल्पके साथ लोकहितके लिये अग्रसर हो, तभी वर्तमान समस्याका समाधान हो सकता है। वर्तमान मन्त्रिमण्डलने आम लोगोंके हितोंकी रक्षा करनेके काममें असफलताका परिचय दिया है। जो असली शासक हैं, वे रहते हैं पर्देके पीछे। मंत्रिमण्डल अगर सम्मान-सहित पदत्याग करता, तो तभी वे लोगोंकी नजरके सामने प्रकट हो जाते। जो ब्रिटिश गवर्नमेंटके असल प्रतिनिधि हैं, भूखसे पीड़ित देशके खुले मंचपर उपस्थित होकर, जिससे वे आम लोगोंके सामने सफाई देनेको मजबूर हों, इसकी व्यवस्था करनी होगी। ग्रेट-ब्रिटेनके अधिवासियोंसे मैं पूछना चाहता हूँ कि पिछले कुछेक महीनोंसे खाद्यके अभावसे हम जो दुख भोग रहे हैं, वे अगर इसका मामूली हिस्सा भी भोगते, तो अपने देशकी गवर्नमेंटके सम्बन्धमें वह क्या इन्तजाम करते ?

वक्तव्य (५ नवम्बर, १९४३)

पिछले अढ़ाई महीनोंसे बंगालके दुखको दूर करनेके लिये हम जी-जानसे कोशिश कर रहे हैं। भारतवर्ष और भारतके बाहरसे जिन दाता महानु-भावोंने रुपया-पैसा और सामानसे सहायता की है और कर रहे हैं, उनके प्रति इस मौकेपर फिर एक बार कृतज्ञता प्रकट करता हूं।

गैर-सरकारी संस्थाएँ यथासाध्य आफतजदोंकी मदद कर रही हैं। बंगाल रिलीफ कमेटी और बंगाल-प्रान्तीय हिन्दू महासभाके कामके साथ मैं प्रकट रूपसे सम्बन्धित हूँ। आजतक बंगाल रिलीफ कमेटीने नकद और सामानके रूपमें बीस लाख रुपया और बंगाल प्रान्तीय हिन्दू महासभाने चार लाख रुपया इकट्ठा किया है। * बंगाल रिलीफ कमेटी बंगालके बीस जिलोंमें एक साथ पचीस केन्द्रोंमें हर रोज प्रायः स्त्री-पुरुषोंकी सेवा कर रही है। कितनोंको ही मुफ्त पका हुआ खाना दिया जाता है। फिर, कितनोंको ही मुफ्त या कम कीमतपर अनाज दिया जाता है। इसके अलावा दवाई और कपड़े वगैरहसे भी सहायता की जा रही है। दिसम्बरके महीनेतक इसी तरह काम चलानेके लिये, जो बीस लाख रुपया मिला है, उससे कहीं अधिक खर्च हो जायगा।

बंगाल प्रान्तीय हिन्दू-महासभा बीस जिलोंमें एक साथ पचीस केन्द्रोंमें हर रोज साठ हजारसे ज्यादा लोगोंकी सेवा कर रही है। बहुतसे सामयिक आश्रय-स्थान और अस्पताल चालू किये गये हैं। कपड़े और दवा-दारू भी बांटे जा रहे हैं। घरेलू-उद्योगके प्रचारकी ओर हमने विशेष तौरपर ध्यान दिया है। सहायताके बदलेमें पीड़ित लोग जिससे कुछ काम-धन्धा करें, सहायता केन्द्रोंसे इस विषयमें प्रोत्साहन दिया जा रहा है। पीड़ित मध्यवित्त कुनबोंकी सहायताके लिये अबतक हमने चालीस हजार रुपयासे अधिक खर्च

* इसके बाद और भी काफी रुपया जमा हुआ है। बंगाल रिलीफ कमेटी और बंगाल प्रान्तीय हिन्दू महासभा रिलीफ कमेटीका हिसाब परिशिष्टमें दिया गया है।

किया है। राजनीतिक कैदी और पाठशालाओंके पण्डितोंके परिवारोंको इस रूपमें सहायता दी गयी है।

जो भारी कार्य-भार ग्रहण किया गया है, उसके लिये और भी काफी धनकी आवश्यकता है। आम जनतासे हार्दिक अनुरोध है कि बंगाल रिलीफ कमेटी और बंगाल प्रान्तीय हिन्दू-महासभाको वे और भी रुपयेकी सहायता करें। सेवाके कामका विस्तृत ब्यौरा शीघ्र ही अलग प्रकाशित होगा। हरएक दाताके पास यह ब्यौरा भेजा जायगा।

हम और बहुत-सी गैरसरकारी संस्थाएँ वर्त्तमान संकटमें अपनी ताकत भर काम कर रहे हैं। किन्तु समस्या इतनी विराट् है कि उसका पूरा-पूरा समाधान करना हमारी ताकतके बाहर है। जरूरतके मुकाबलेमें हमलोग थोड़ा ही कर सके हैं। फिर भी मैं बेधड़क यह कह सकता हूँ कि बंगालकी दशाके सम्बन्धमें आज जो सारा भारतवर्ष और बाहरकी दुनियाकी नजर पड़ी है, वह हम लोगोंकी चेष्टासे ही हुआ है। सरकार भी आखिरमें इस संकटके मौकेपर अपनी बड़ी जिम्मेदारीको महसूस कर सकी है, यह नहीं मालूम हो रहा है। सन् ४३ का अकाल भारतमें ब्रिटिश-शासनका कलंक है। इसकी जाँच करवाकर इसका कारण मालूम करनेके लिये हम बार-बार दावा कर चुके हैं। दुख-दुर्गतिकी भयावह कहानी इसी बीच समस्त भारतमें फैल गयी है। इसे मैं नये सिरेसे और नहीं कहना चाहता। मृत्यु-संख्या तेजीसे बढ़ती जा रही है। रात-दिन अनेक हृदयको चीरनेवाली खबरें पहुँच रही हैं।

बंगालके लाखों स्त्री-पुरुषोंके कल्याणके प्रति लक्ष्य रखकर एक सुनियंत्रित नीतिसे चलनेवाली सरकारी और गैर-सरकारी प्रचेष्टाके बीच योग-स्थापन करनेकी व्यवस्था करनी होगी ; अन्यथा परित्राणका और कोई उपाय नहीं । मैं कुछेक खास-खास विषयोंका जिक्र यहां कर रहा हूँ । इसकी बाबत जल्दी ही सरकार और आम जनताको ध्यान देना जरूरी है ।

[१] कलकत्तासे भूखोंको बाहर ले जानेकी व्यवस्था हुई है । किन्तु कुनबेके हिसाबसे श्रेणी-विभाग न होनेसे भारी गड़बड़ी मच रही है । लोगों-को बाहर ले जाते वक्त बल-प्रयोग भी हो रहा है । जो लोग पड़े रह गये, वे अपने कुनबेवालोंसे एकदम ही बिछुड़ गये । कुनबेके और सब लोगोंको कहां ले जाया गया, यह मालूम करनेका किसी तरहका कोई उपाय नहीं रहता । मैंने बहुत बार कहा है कि भूखे लोगोंको आखिरकार उनके निजी घरोंमें समाजके जीवनके अन्दर पहुँचा देना होगा । इसके लिये हरएकको उसके घर-गांवके निकटवर्ती आश्रय-केन्द्रमें ले जाना उचित है । प्रत्येक हिस्सेमें खाद्य और अन्यान्य कामकी चीजें पहुंचानी होंगी । इस विषयमें ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं, देशवासियोंको यह जानना जरूरी है । सरकारको इसका विस्तृत ब्योरा प्रकाशित करना होगा । गैरसरकारी लोगोंको बीच-बीचमें आश्रय-केन्द्र देखनेकी सुविधा देनी होगी । कलकत्तासे जो लोग निकाले जारहे हैं, खाद्यकी कमीसे अगर वे मर गये, तो इससे हालत और भी उलझन वाली हो जायगी ।

[२] यह बात जरा भी न भूलनी होगी कि भोजनके अभावसे ही ये सब लोग पथके भिखारी बने हैं । इसी तरह कितने ही और लोग गांवों और

शहरोंमें रहकर भूखसे चुपचाप मौतको अपना रहे हैं! महीने भर पहले मैंने प्रस्ताव किया था, कि कुछेक गांव लेकर एक-एक केन्द्रका सङ्गठन करना होगा। इसी प्रकार हरएक केन्द्रके लिये अनाज-गोदाम स्थापित करना होगा। प्रत्येक शहरके लिये भी उसीके मुताबिक अनाज-गोदाम होगा। इन सब गोदामोंसे मुफ्त अथवा वाजबी कीमतपर अनाज बांटा जायगा। यह सब कुछ भी नहीं हुआ। हमारे प्रयोजनके लिये कमसे-कम अनाज मंगवानेकी क्षमता सरकारमें है या नहीं, इस विषयमें आज जनसाधारणकी आस्था शिथिल हो गयी है। केवल वक्तव्यके बाद वक्तव्य और इश्तहारोंको निकाल कर इस अवस्थाको फिरसे जमाना सम्भव नहीं। हरएक हिस्सेमें अनाज जमा करके जन-साधारणको आँखोंके सामने दिखाना होगा। इसीसे उनके मनोभावमें परिवर्तन दिखलाई देगा। तब वे लोक-रक्षामें सर्व-शक्तियोंकी एकाग्रताकी प्रेरणा पायेंगे। सरकारी हिसाबके मुताबिक पिछले सात महीनोंमें (अप्रैलसे अक्टूबर तक) सरकारी खातेमें, बंगालके बाहरसे चार लाख पचहत्तर हजार टनसे अधिक अनाज आया है। किन्तु दुखकी बात है कि कहीं भी स्थानीय प्रयोजनके लिये अनाज जमा नहीं किया गया है। संकट क्रमसे बढ़ता ही चला जा रहा है। जिन सात महीनोंकी बात हो रही है, यह याद रखना होगा कि वह वर्तमान मन्त्रियोंका ही शासन-काल है।

यह अनाज कहां और किसके इस्तेमालके लिये गया है, सरकारकी ओरसे इस विषयमें साफ-साफ उत्तर हम चाहते हैं। पिछले तीन महीनेसे अनाज कहां चला जा रहा है? केवल जिलोंका नाम कह देने भरसे काम न चलेगा—

कौन महकमा, कौन थाना, कौन यूनियन—यहाँतक कि गाँवका नाम जाननेका भी इशारा रहता है। हरएक हिस्सेके लोगोंको असली हालत मालूम होने दी जाय। न्याय-युक्त वितरण-नीति अनुसार हर विभिन्न देहाती केन्द्रोंमें अनाज पहुंचाना होगा। बिना परिकल्पनाके गड़बड़ीके तरीकेसे रेल और सड़कोंसे अनाज पहुंचानेसे कुछ भी नतीजा न होगा। जहाज भरकर अनाज कलकत्तेमें आता है, किन्तु वितरणका ढंग एकदम ही त्रुटिपूर्ण है। किसी सुनिश्चित कार्यक्रमके अनुसार अनाज क्यों बन्दरगाहसे ही गाड़ी, स्टीमरके जरिये जल्दी मुफस्सलमें नहीं भेजा जाता है? कपड़े और अनाजको निकालकर खाली न करनेकी वजहसे कितने दिनतक सरकारी एजेण्ट उस सब मालका भार न ले सका? मन्त्रिमण्डलसे मैं इस विषयमें एक वक्तव्यका दावा करता हूं। अनेक स्थानोंमें कोई खास एजेण्ट कितने ही दिनतक माल उतारते हैं, फिर वह सरकारके अनुग्रहीत जमा करनेवालेके पास भेजा जाता है। नतीजा यह होता है कि पीड़ित हिस्सोंमें माल पहुंचनेमें नाजायज देरी हो जाती है। इस बातकी सफाईमें सरकार क्या कहेगी? हम जानते हैं कि ये जमाखोर कमीशनके रूपमें लाखों रुपयेका फायदा उठाते हैं। यह पक्षपात और अयोग्यता और कबतक सहारा पाकर पीड़ित देशवासियोंका सर्वनाश करेंगे? हम दावा करते हैं कि जल्दी ही एक परिकल्पना तैयार की जाय जिसके फलस्वरूप प्रधान सहायता-केन्द्रोंमें कपड़ा और अनाज पहुंचनेमें विलम्ब न हो। प्रधान केन्द्रसे वह विभिन्न शाखा-केन्द्रोंमें सुनिर्दिष्ट नीतिके अनुसार बहुत जल्द बांट दिया जाय। आमलोगोंकी जानकारी और जांचके लिये हर हफ्ते कार्यका पूरा ब्यौरा प्रकाशित करना होगा।

[७] सबसे पहली जरूरत यह है कि सहायताके लिये स्थानीय सामग्री जो भी मिल सके उसे इकट्ठा किया जाय। गवर्नमेंटको वर्त्तमान बेपरवाह खरीद-दारीकी नीतिको फिर एकदम ही त्याग देना होगा। आजके इस संकटमें बंगालके लाखों नर-नारियोंका जीवन नष्ट हो रहा है। बेपरवाह खरीददारीकी नीति संकट लानेका प्रधान कारण है। खबर मिली है कि गवर्नमेंटके एजेण्ट लोग अभी भी मुस्तैदीके साथ क्रय कर रहे हैं। जहांपर भी उन्होंने खरीद की है या खरीदकी चेष्टा की है, वहीं चीजोंकी एकाएक कीमत बढ़ी है। गवर्नमेंट खरीद करना चाहे तो साथ ही साथ उसे वितरणकी जिम्मेदारी भी अपने ऊपर लेनी होगी। इस मामलेमें किसी तरहकी गड़बड़ न चल सकेगी। वर्दमानके एक पीड़ित हिस्सेमें गवर्नमेंटने लाइसेन्स-प्राप्त व्यापारियोंका माल रोक लिया, किन्तु उससे पीड़ित लोगोंके बीच उसे बाँटनेका हुक्म नहीं दिया। कुछेक दिन पहले इन व्यापारियोंके पास जुबानी सरकारी हुक्म आया कि गवर्नमेंटके खातेमें उनका सारा माल इस्पहानी-कम्पनीको देना होगा। अन्यान्य पीड़ित हिस्सोंसे यहां तक कि मेदिनीपुर और बाँकुड़ासे भी गवर्न-मेंटके एजेण्ट लोग ऐसे ही चावल खरीद रहे हैं। लोगोंकी हालत एकदम असहाय हो चली है।

[८] सरकारने असमके धानको खरीदनेका इरादा किया है। इसके बारेमें विवरण प्रकाशित हुआ है। यह खरीददारीकी नीति बहुत गुरुत्व-पूर्ण है। असमकी फसल इसबार बहुत अच्छी हुई है। परन्तु सिर्फ इसी धानसे बंगाल बच न पायेगा। फिर भी यथावत् वितरण होनेसे लोगोंका कष्ट बेशक कम होगा। हम सरकारको विशेष प्रकारसे चेतावनी दिये देते हैं कि

आमन धानके सम्बन्धमें उनकी पुरानी क्रय-नीति आगे न बर्ती जाय। पहले कुछेक अनुग्रहीत व्यवसायियोंकी तरफदारी करनेमें बहुत नुकसान हुआ है। फिर उसको कहीं दुहराया न जाय। हरएक गांवमें साल भरके कामका काफी अनाज मौजूद रहे। गांवके लोगोंको ही इस विषयमें ध्यान रखना होगा। अगर अनाजमें कुछ बढ़ती भी हो, तो सिर्फ वहां औरोंके काममें लाया जा सकेगा। लोग अपने-आप ही ऐसा करें कि एजेण्ट लोग जिससे बेपरवाह तरीकेपर खरीद न कर सकें अथवा तथाकथित बढ़तीवाले मालको लेकर कहीं खींचतान शुरू न हो। कलकत्ता और आसपासके कारखानोंवाले हिस्सेको एकदम अलग हिस्सा समझा जाये। बंगालके बाहरसे जो अनाज आयगा, भारत-सरकार उसीमेंसे इन हिस्सोंको माल पहुंचानेकी जिम्मेदारी लेगी। बृहत्तर-कलकत्ताके लिये अलग इन्तजाम हो, और गवर्नमेंट तथा सट्टा-बाजारके खरीददार मुफस्सलके बाजारसे कुछ समयके लिये हट जायं, तो साथ-साथ यह संकट भी दूर हो जायगा; देशकी स्वाभाविक हालत फिरसे जल्दी लौट आयगी।

मुल्कमें सर्वत्र मालके आने-जानेके सम्बन्धमें जिससे यथोचित सतर्कता अमलमें लायी जाय, गवर्नमेंटको इस विषयमें कड़ी नजर रखनी होगी। व्यापारियों और जमाखोरोंको बाध्य करना होगा कि वे जमा मालका सही हिसाब दें। मुनाफाखोरी और अति-संचयकी चेष्टा कड़े हाथसे बन्द करनी होगी। बृहत्तर कलकत्ताको छोड़ कर भी, आमनके धानसे कितने दिन काम चलेगा, यह कहना मुश्किल है। किन्तु हालतको जांचनेके लिये और पूरे सन् १९४४

को और भविष्यकी व्यापक खाद्य-नीतिको निर्धारित करनेके लिये समय मिल जायगा, यह कुछ कम बात नहीं।

[५] चिकित्सा-सम्बन्धी सहायता देना सबसे जरूरी काम है। हैजा, आतिसार और मलेरिया व्यापक रूपमें दिखलाई दे रहे हैं। बंगाल रिलीफ कमेटी और बंगाल हिन्दू महासभामें करीब एक लाख आदमियोंको हैजा रोकनेकी दवा दी जा चुकी है। किन्तु जितनी जरूरत है, उसके मुकाबलेमें यह बहुत कम है। इस ओर भी सरकारी और गैरसरकारी संस्थाओंके बीच मिलकर काम नहीं हो रहा है। यह सचमुच शोचनीय है। इस मामलेमें गवर्नमेंटकी चेष्टा बहुत धीमी और सीमित है।

एक और जरूरी वस्तु है——कपड़ा। जाड़ा आ गया, अब कपड़ेकी जरूरत ज्यादा बढ़ जायगी। बच्चोंकी हालत बहुत दर्दनाक है। उनको बचानेके लिये अच्छी तरह विचारी हुई व्यवस्थाकी जरूरत है। जबतक स्वाभाविक अवस्था नहीं लौट आती, तबतक उन्हें वहीं रखकर खिला-पिला और कपड़ेसे ढंककर बड़ा करना होगा।

हालत बहुत निराशाजनक है। तब भी मैं एकनिष्ठताके साथ कह सकता हूं कि इस मुसीबतको ऐसे रास्तेपर डाला जा सकता है कि जिसके फलस्वरूप हमारी बंग-भूमिकी आर्थिक और सामाजिक हालत नया रूप धारण कर लेगी। साधारण कंगालीकी हालत असलमें बहुत ही शोचनीय है। उसके ऊपरसे मनुष्य-कृत इस अकालकी चोट बंगालियोंको बिलकुल ही पीस गयी है। कईएक गांवोंको लेकर हमें समवाय संस्थाएँ [को-आपरेटिव]

बना कर खड़ी करनी होगी । नीचे दिये विषयोंके सम्बन्धमें हम एकदम संलग्न होंगे—

[क] स्थानीय और बाहरके हिस्सोंमें अनाज संग्रह और वितरण करना होगा ।

[ख] अधिक अनाज पैदा करनेके लिये आन्दोलन चलाना ।

[ग] स्वास्थ्य, अर्थनीति और शिक्षाके सम्बन्धमें फिरसे संगठन करनेका प्रबन्ध करना होगा ।

सावधानीके साथ एक कार्यक्रम तैयार करके जितनी जल्दी हो, काम शुरू करना होगा । कारण यह कि बंगाल तेजीके साथ विनाशके रास्तेपर बढ़ा चला जा रहा है । आजके संकटके समय सरकारी नियम-प्रबन्ध पूरी तौरपर नाकामयाब हुए हैं । अगर लोक-चेष्टाके साथ सरकारी चेष्टाका मेल न बैठाया जायगा, तो भविष्यमें भी वे इसी तरह व्यर्थ साबित होंगे । दलगत राज-नीतिक सवालको उठानेका हमारा उद्देश्य नहीं । किन्तु बंगालको नष्ट होनेसे बचानेके लिये राजनीतिक दलबन्दी एकदम बन्द करनी होगी । ऐसी आबो-हवाकी सृष्टि करनी होगी कि जिससे हमारी एकताकी कोशिशें ठोस सूरत ले सकें । मंत्रिमण्डलने कर्त्तव्य-पालनमें अपनी अक्षमता दिखलायी है, इसीसे आज आमलोगों और सरकारके बीच भारी अन्तर मौजूद है । यह भेद किस तरह दूर किया जाय ? ब्रिटिश सरकारके जो सब प्रतिनिधि अधिकारको जकड़े बैठे हैं, इस भयंकर समयमें भी उन्होंने दमन-नीतिको छोड़ा नहीं है । वे आम लोगोंपर विश्वास नहीं कर सकते—उन्होंको इस सवालका

अकाल क्या फिर आयगा ?

:o:—

बहुत-से लोगोंका ऐसा खयाल है कि बंगालका संकट कट गया है, वह धीरे-धीरे स्वाभाविक अवस्थामें लौटा चला आ रहा है। हालत चाहे जो भी हो, इस समय जिस तरह सरकारी काम-धन्धा चल रहा है, अगर वह चलने दिया जाय, तो फिर गड़बड़ी होनेका डर है। इस विषयमें विशेष खबरदारीकी जरूरत है।

बंगालको बचानेके लिये व्यापक चिकित्सा-प्रबन्धकी बड़ी आवश्यकता है। उसीके साथ सामाजिक और आर्थिक स्थितिको फिरसे सुधारनेके लिये दृढ़ प्रयत्न होने चाहिये। बड़ी खबरदारीके साथ चलना होगा कि कहीं किसी तरह मौजूदा साल-जैसा खाद्य-संकट फिर न आने पाये। पिछले छः महीनेके अरसेके अन्दर अन्नके अभावसे बेशुमार जानें गयी हैं। जो किसी तरह बच गये हैं, उनमेंसे लाखों रोगके कौर बन रहे हैं। लोगोंकी जीवनी-शक्ति एकदम नष्ट हो गयी है, इसी कारण रोगका सब जगह ऐसा भयंकर प्रकोप है। इसपर लत्ते-कपड़े की कमी है; दवा मिलती नहीं, मरीजोंके कामका पथ्य आदि भी दुर्लभ है। इससे देशवासियोंके दुखकी कोई हद ही नहीं रही।

अकाल क्या फिर आयगा ?

लाखों कुनबे कुछ भी कमानेकी ताकत खो बैठे हैं। चावल की मन अगर दस या आठ रुपयेसे भी गिर जाये, तब भी लोग अपना पेट न भर पायेंगे। देशके हरेक हिस्सेसे दुःख और कष्टके दर्दनाक समाचार आ रहे हैं। पीड़ितोंमेंसे बहुतोंकी शारीरिक शक्ति खो गयी है; और अगर किसी में शक्ति भी हो तो अनेकों काम नहीं पा रहे हैं। सभी उम्रोंके और सभी सम्प्रदायोंके अनगिनत स्त्री-पुरुषोंकी यही चिन्ताजनक हालत है। एक दल और भी है—इसमें स्त्रियां और बच्चे ही ज्यादा हैं—अपने अपने कुनबोंसे बिछुड़ कर ये शहरों और गांवोंमें फिर रहे हैं। ये लोग धीरे-धीरे पूरे ही भिखमंगे होते चले जा रहे हैं। समाजकी आर्थिक बुनियाद चकनाचूर हो गयी है। सिर्फ सस्ते दामोंपर अनाज आनेसे ही काम न चलेगा। सामाजिक जीवनको फिरसे बनानेके लिये शीघ्र ही ध्यान देना होगा। दुःखग्रस्त लोगोंको खिलाने और लत्ता-कपड़ा और रुपया पैसा देकर संकटका स्थायी समाधान नहीं हो सकता। पेटकी ज्वालासे इन्सान भिखमंगेका काम ग्रहण कर रहा है। इसका नतीजा यह है कि एक पूरी जातिके बीचसे आत्मविश्वास और आत्मसम्मानकी भावना लापता होते जा रही है।

सभीकी कोशिशों और सहयोगसे एक ठोस सहायताकी स्कीम बनानी होगी। स्थानीय अवस्थाका विचारकर भिन्न-भिन्न हिस्सोंमें उसका प्रयोग करना होगा। कईएक गांवोंको लेकर एक-एक रिलिफ़ कैम्प बनाना होगा। जो लोग बेघर और एकदम कमजोर हैं, उन यतीमखानोंमें उन्हें खाना और आश्रय दिया जायगा। मेहनतके बदलेमें उन्हें रुपया-पैसा और अनाज वगैरह दिया जायगा।

कारीगर लोग भी एकदम गरीब हो गये हैं। उन्हें अपने-अपने धन्धोंमें फिरसे लगाने की कोशिश भी साथ ही साथ करनी होगी। मध्यवित्त श्रेणीमें भी लाखों कुनबे हैं, जो कुछ कामोंसे रहित दशामें पड़े हैं अथवा मामूली आयसे धीरे-धीरे मौतके कौर बनते जा रहे हैं। इन्हीं मध्य वित्त लोगोंने ही बंगालकी सांस्कृतिक और आर्थिक जीवनमें सबसे ज्यादा काम किया है। इनकी रक्षा करना सरकारकी प्रधान जिम्मेदारी है।

आर्थिक स्थितिका उद्धार और सामाजिक जीवनमें मनुष्यको फिरसे जमाने के काममें अगर और लापरवाही हुई तो अकाल फिर प्रकट हो उठेगा, ऐसी संभावना है। जिन्होंने घटनाओंकी परम्पराको देखा है, उन्होंने एक ही वाक्यमें कहा है कि सन् १९४३ में बंगालने जो बेहद दुख भोगा है, उसके मूलमें थी सरकारी कर्मचारियोंकी अकर्मण्यता, अव्यवस्था और दुर्नीति। सचको छिपानेके लिये सरकारी तरफसे काफी कोशिशें हुई हैं। घटनाको तोड़ मरोड़ कर दिखानेमें एमरी साहबका कोई जोड़ीदार नहीं। यह होते हुए भी बंगालकी बेहालीकी खबर सब ओर फैल चुकी है। इस मामलेमें सरकारी इज्जतको भी खूब भारी चोट पहुंची है।

बंगालके बेशुमार लोगोंकी मौतके लिये वर्तमान मन्त्रि-मण्डलकी कितनी जिम्मेदारी है, यह आलोचना मैं इस वक्त नहीं करना चाहता। आशा करता हूं कि एक दिन इस विषयमें निरपेक्ष जांच होगी। तब सारा सत्य खुल जायगा। किन्तु एक बातकी ओर मैं सभीका ध्यान खींचना चाहता हूं। फजलुलहक साहबको चाहे कितनी भी त्रुटि क्यों न हो, उनकी मंत्री-सभाने सन् १९४३ के मार्चमें दुनियाके लोगोंके सामने यह घोषणा की थी कि

बंगालमें भयानक खाद्य-संकट आनेवाला है ; बंगालको बचानेके लिये बाहरसे खाद्य-सामग्री मँगवानी होगी । क्योंकि कुछेक हफ्ते बाद किसी-किसी ऊँची ताकतके षड्यन्त्रके फलस्वरूप वह मंत्री-सभा दूर की गयी । सर नाजीमुद्दीनकी मंत्रि-सभा, कायम होनेके समयसे लेकर कुछेक महीनेके अन्तसे झूठे वक्तव्य निकालने लगी कि बंगालमें अनाजकी कमी नहीं; कुछ लोगोंने काफी परिमाण में अनाज जमा कर रखा है, यह संकट उसीका नतीजा है । जमा अनाजको बाहर निकालनेके लिये जूनमें मंत्रि-सभाने खूब जोर-खरोशके साथ खाद्य-आन्दोलन चलाया। यह आन्दोलन शोचनीय रूपमें असफल हुआ है । मंत्री लोग आजतक भी आन्दोलनके नतीजेको प्रकट करनेका साहस न कर सके ।

मन्त्री-सभाने अपने कृपापात्र व्यापारियोंको चावल खरीदनेमें बढ़ावा दिया । इसके फलस्वरूप देहात एकदम चावल-शून्य हो गया । दामोंकी स्वाभाविक दर गड़बड़ीमें पड़ गयी । लोग सरकारी इन्तजामके सम्बन्धमें आस्थाहीन हो गये । लन्दनमें बैठे-बैठे एमरी साहब उस वक्त वक्तव्यपर-वक्तव्य देने लगे कि बंगालकी हालत अच्छी है, किसी तरहकी गड़बड़ी नहीं ! फिर बंगालमें और हिन्दुस्तान भरमें जी-हुजूरोंका दल उस ध्वनिकी आवृत्ति और पुनरावृत्ति करने लगा ।

वर्तमान मन्त्रिमण्डलके खिलाफ मेरा अभियोग है कि उसने सन १९४३ के अप्रैलसे बहुत कीमती समयकी फिजूलमें बर्बादी की है । फजलुल हक साहबने मार्चके महीनेमें चावलके अभावकी बात जोरोंके साथ कही थी । यह मन्त्रिमण्डल भी अगर इसी मार्गका अनुसरण करता, तो बंगालमें इस तरहकी भयावह हालत न होती । फौजी और गैर-फौजी अधिकारी लोगोंने भुखमरोंके

लये भोजन जुटाने और उसे बांटनेमें पिछले दो-तीन महीनेसे खूब मुस्तैदी दिखलायी है। अगेलसे ही यह परिश्रम क्यों नहीं शुरू हुआ? नये मन्त्री लोग उस वक्त खुद सिर्फ अपनेको समेटनेके काममें लगे थे, यह बात भी नहीं। सामने खड़ी मुसीबतको महसूस करके जिन्होंने इस सम्बन्धमें आगाह होनेके लिये सतर्क-वाणीका उच्चारण किया था, उनको दबाकर रखा गया। गैर-सरकारी पक्षसे सहायताकी चेष्टा न होती, तो बंगालकी दुःख-दुर्दशाकी बाबत और भी अधिक समयतक बाहरके लोग कुछ न जान सकते थे। बहुत देरीसे सरकारी अधिकारियोंके खयालमें बात आती।

इस बार आमनका धान काफी फला है। यह होते हुए भी, बहुतसे लोगोंकी धारणा है कि अगर मन्त्रिमण्डलकी वर्तमान नुकसानदेह नीतिको चलने दिया जाय, तो बंगालमें दुबारा अकाल पड़ेगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट और भारत-सरकारने पूरी जिम्मेदारी ली है कि सन् १९४३ का कलंकित दुर्दैव फिर न दुहराया जा सकेगा। अतएव तथाकथित प्रान्तीय स्वायत्त-शासनकी दुहाई देकर अब एमरी साहब अपना पिण्ड न छुड़ा सकेंगे। अकालके समय चावलका जो दाम था, इस समय उससे जरूर दाम कम हो गये हैं। किन्तु बंगालमें सब जगह दाम फिर बढ़ते ही जा रहे हैं। सरकारने जो दर बांध दी है, उससे बहुत ऊंचे दामोंपर चावल बिक रहा है। इसी जनवरीके महीनेमें चावलकी इतनी इफरात होनेपर भी, गवर्नमेंट नियन्त्रित दामोंको बनाये नहीं रख पा रही है। इससे शासन-व्यवस्थाका खोट और मन्त्रि-मण्डलके बेहद निकम्मेपनका परिचय मिल रहा है। अनाज इकट्ठा करनेके लिये जो कार्यक्रम अमलमें लाया जा रहा है, वह विशृंखल और चलताऊ

अन्नकी आशामें।

यह आदमी दुश्मनके सामने छाती खोलकर खड़ा हो सकता था।
कलके बङ्ग देशका निर्माणकर्ता यह शिशु !
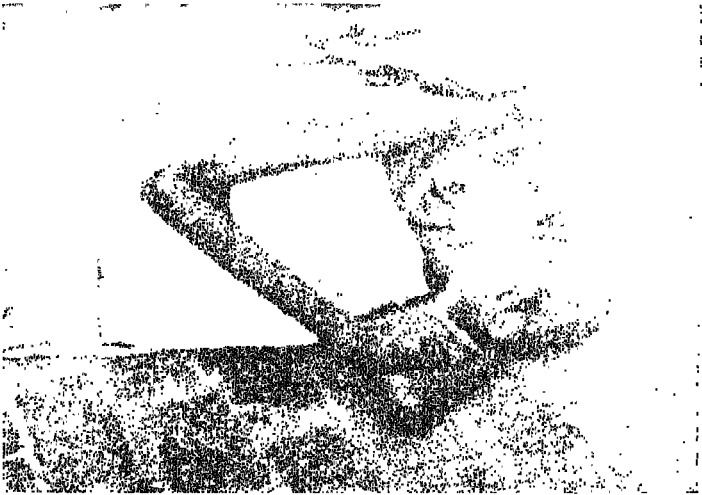
मुट्ठी भर भातके लिये रास्तेपर पड़े-पड़े इन्सान मर रहा है।
सभ्यताभिमानी कलकत्ता शहर !

ढङ्गका है। लोक-हितके लिये और व्यापारियों तथा आम लोगोंमें आस्था-का सञ्चार करनेके लिये वह काममें नहीं आ रहा है।

जनताके मनमें भरोसा पैदा करने और देशव्यापी संकटके खिलाफ संग्राम करनेके लिये पिछले चार महीनेसे मैं कहता आ रहा हूँ कि गवर्नमेंट थोड़े से गांव लेकर एक-एक अनाज-गोदाम खोल दे। पहलेसे चली आनेवाली वाणिज्यकी धाराको, जहांतक हो, अटूट रखना होगा। बुरे समयके लिये अनाज जमा है, आंखोंके सामने यह देखकर लोगोंके मनमें फिरसे भरोसा लौट आयगा। बंगालके हरएक हिस्सेको लेकर यह प्रबन्ध करना होगा। इसके लिये गवर्नमेंटके साथ आम लोगोंका पूर्ण सहयोग जरूरी है। सभीके हितोंका एकीकरण होनेपर ही इस तरहका कार्यक्रम सफल हो सकेगा। किन्तु आज दिनतक इस तरहकी कोई व्यवस्था ही न हुई, बल्कि कुछेक अपने प्यारे व्यापारियोंकी मार्फत, तबियतके मुताबिक चावल खरीदकर, एकताकी चेष्टाको शिथिल किया जा रहा है। साथके व्यापारियोंके बीच इससे ईर्ष्याका उद्रेक हो रहा है। पीड़ित हिस्सोंमें तत्परताके साथ चावल ढोनेके लिये कोई सिलसिलेवार इन्तजाम नहीं। बंगाल आज जिस विराट संकटसे कातर हो रहा है, इस तरहकी व्यवस्थासे उसका प्रतिकार नहीं हो सकता।

कलकत्ता और उसके आस-पासके कल-कारखानोंके हिस्सेके तीस लाखसे भी अधिक लोगोंको खिलानेका भार भारत-सरकारने अपने ऊपर लिया है। इस राशनिंगका बन्दोबस्त करनेमें भी बंगालका मन्त्रिमण्डल गड़बड़ी कर रहा है। उनका उद्देश्य लोक-सेवा नहीं ; जिन राजनीतिक और साम्प्रदायिक दलोंने उसे खड़ा किया है, वर्तमान संकटका सुयोग लेकर वह (मन्त्रिमण्डल)

उन दलोंकी ताकत बढ़ाना चाहता है। मन्त्रिमण्डलकी नीयत यह थी कि प्रचलित दुकानोंके प्रसारको एकदम नष्ट करके, अनुग्रह-पुष्ट सरकारी दुकानोंकी मारफत राशनिंग चलाया जाय। भारत-सरकारने उसके बेतुके कार्यक्रममें रद्दोबदल किया है। ग्रेगरी-रिपोर्टके उस कार्यक्रमके खिलाफ होनेपर भी न मालूम किस युक्तिके बलपर, मन्त्रिमण्डलने अपना दावा बनाये रखनेके लिये बराबर जिद्द दिखलायी है। भारत-सरकारने निर्देश दिया है कि सौमें पचपन दुकानें सरकारी नियन्त्रणके अधीन रहेंगी और पैंतालीस साधारण व्यवसाइयोंके हाथमें रहेंगी। किन्तु सरकारी दुकानोंमें बहुत ज्यादा खरीददार घुसेड़नेकी व्यवस्था करके, भारत-सरकारके निर्देशको दूसरी तरफसे बेकाम किया गया है। राशनिंगका प्रबन्ध भी अगर न्याय-नीतिके अनुसार न होकर, इस तरह दलके स्वार्थ-विचारपर चले, तो मैं सवाल करूँगा कि खाद्यके मामलेमें राजनीतिको कौन खींचकर ला रहा है?

कलकत्तेमें या दूर देहातोंमें ही हो—बंगाल-सरकार और गैरसरकारी आम लोगोंके बीच किसी तरहका मेलजोल नहीं। भारत-सरकारने कलकत्ता और उसके आस-पासके कल-कारखानेवाले हिस्सेको खिलानेका भार लिया है। बंगालके अन्यान्य हिस्सोंमें जरूरतके मुताबिक काफी फसल फली है। इस हालतमें भी लोग अब भी क्यों कष्ट भोग रहे हैं? सन् १९४४ में बंगालके अन्दर क्यों खाद्य-संकटकी आशंका होगी? मंत्रिमण्डलकी अकर्मण्यता और दुर्नीतिके कारण अगर सचमुच ही इस तरहकी बात हो, तो उसकी जिम्मेदारी भारत-सरकारके ऊपर होगी। एक दल-विशेष की मंत्री-सभा, जो साम्प्रदायिक भेदके द्वारा परिचालित है—कभी भी आमलोगोंका विश्वास नहीं

प्राप्त कर सकेगी। जिसके खिलाफ विश्वास-भ्रष्टताका इतना दारुण अभियोग है, लाखों जानोंको लेकर उसको क्रीड़ा करने देना यह कभी भी न हो सकेगा।

बंगालके लोग भीख नहीं चाहते; जिन्दा रहनेका जो मनुष्यका अधिकार है, उसीका वे दावा करते हैं। किसी भी सभ्य नामधारी सरकारका यह पहला फर्ज है। लार्ड वेवल और मि० केसी निरासक्त पक्षपातहीन दृष्टिसे बंगालकी समस्याकी जाँच करें; ऐसी हालत पैदा करें, जिससे सरकार और आम जनताके बीच खुद-ब-खुद पैदा होनेवाली सहयोग-प्रवृत्ति जाग उठे; राजनीतिक या साम्प्रदायिक कोई भी विवेचना कहीं लोक-मंगलको न ढँक सके, तभी संकटसे बंगालका छुटकारा होगा।

एकता चाहिये

मन्त्रिमण्डलने पिछले साल कीमती समयको भद्दे तरीकेसे बरबाद किया था, नहीं तो संकट इतना भयंकर न होता। आज सन् १९४४ में भी प्रायः वही हालत है। जो वक्तव्य निकल रहे हैं, वे सब पिछले सालकी तरह ही भरोसा दिलानेके छूंछे बोल हैं। दोनों वर्षोंके वक्तव्योंको पास-पास रख, मिलाकर देखनेसे समझमें आ जायगा कि घटना फिरसे दुहरायी जा रही है।

मन्त्रियोंने इस बातकी चेष्टा की थी कि बंगालकी संकट-गाथा बाहर न जा पाये। गैरसरकारी तरफसे पहले-पहल सहायताकी चेष्टा शुरू हुई थी। बंगालमें और बंगालके बाहर सहायताके लिये आवेदन किया गया। उस आवेदन और वक्तव्योंमेंसे बहुतोंको भारत-रक्षा-कानूनके घेरेमें अटका देनेकी चेष्टा हुई थी। किन्तु आखिरमें हालत छिपी न रह सकी। लोकमत जाग गया। कितने ही अखबार—खासकर 'स्टेट्समैन'—संकटकी खबर आम लोगोंके सामने प्रकट करने लगा। ऐसा न होता तो और भी बहुत देरीसे सरकारी अधिकारियोंकी नींद टूटती।

बंगाल रिलीफ कमेटी और हिन्दू-महासभा रिलीफ कमेटी, इन दो गैर-सरकारी सेवा करनेवाली संस्थाओंके साथ मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध है। इन्होंने पीड़ितोंकी सहायतामें लाखों रुपया खर्च किया है। उसमें निन्यानवे फी-सदी हिस्सा गैर-मुस्लिमोंका दान है। किन्तु सहायताके काममें जाति-वर्गका भेद नहीं किया गया है। मेरे पास कागजात हैं, जिससे निस्सन्देह यह बात साबित होगी। किन्तु गवर्नमेंटकी तरफसे गुप्त 'सरक्यूलर' गया था कि उसकी सहायता-कमेटियोंमें मुसलमानोंमेंसे केवल मुस्लिम लीगके ही लोगोंको लेना होगा! सरकारका रुपया आता है सभी श्रेणीके लोगोंसे। मुस्लिम लीगका दल आज बंगालमें राज कर रहा है; किन्तु रुपया तो लीगका नहीं, मन्त्रियोंका भी अपना नहीं है। फिर भी सहायता-दान और परिचालनके मामलेमें विषमताकी सृष्टि की गयी थी।

गये सालकी इन सब कड़वी बातोंकी आलोचना करनेसे कोई लाभ नहीं। आजका पहला फर्ज यह है कि सन् १९४४ में कहीं अकाल फिरसे न दुहराया जाय; और सब तरहसे इसका उपाय निर्धारित करना। एक तरहसे जरूर उसके दुहराये जानेकी बात उठती भी नहीं, क्योंकि अकाल अभी भी है ही। चावलका दाम पहले क्या था और आज क्या है? गवर्नमेंटके हिसाबके मुताबिक ही फी-मन पन्द्रह-सोलह रुपयेसे कम नहीं। यह तो अकालकी ही हालत हुई।

खाद्य नीतिके सम्बन्धमें आखिरी जवाबदेही मन्त्रियोंकी है। मौजूदा मंत्री एक खास दलके प्रतिनिधि हैं—सर्वसाधारणके नहीं। इनकी कर्मठता और शासन-नीतिके ऊपर अनगिनत देशवासियोंका अविश्वास पैदा हो गया

है। आम जनताके दिलमें आस्था न रहनेकी वजहसे संकटमोचन नहीं हो सकता। मौजूदा मन्त्रिमण्डलके लिये यह कभी भी मुमकिन नहीं।

एसोशियेटेड प्रेसने २२ मार्चकी (१९४४) बांकुड़ाकी खबर दी है कि भग्न-स्वास्थ्यवाले पीड़ित लोग फिर झुण्डके-झुण्ड शहरकी ओर धावा कर रहे हैं। रङ्गपुर रोडके ऊपर एक लाश कईएक घंटों तक पड़ी रही। स्टेशनके सामने सड़कपर देखा गया कि और एक लाशको सियार-गीध खा रहे हैं।

चटगांवमें सौमेंसे पन्द्रह लोगोंके लायक अनाज मंजूरशुदा दुकानोंकी मार्फत आ रहा है। चावलका कंट्रोल-दाम वहाँपर सोलह रुपया मन है। हजारों लोगोंकी उस दामपर चावल खरीदकर खानेकी हैसियत नहीं। फिर, वह भी सौमेंसे केवल पन्द्रह लोगोंके लिये है। बाकी पचासी आदमियोंको तकदीरके ऊपर छोड़ दिया गया है। उन्हें चावल खरीदना पड़ रहा है, बाइस और छब्बीस रुपये मनके हिसाबसे।

कलकत्ता गजटमें (१६-३-४४) ८ वीं तारीख मार्च तकका, बंगालके अलग-अलग जिलों और सब-डिवीजनोंका विवरण प्रकाशित हुआ है। ८९ जिले और सबडिवीजनोंमेंसे २९ के सम्बन्धमें सरकारी तरफसे स्वीकार किया गया है कि उन सब हिस्सोंमें चोर-बाजार गरम है ? बाजारकी साधारण अवस्थाके बारेमें कोई भी खबर नहीं। त्रिपुरा, चटगांव, ढाका आदिकी यही हालत है। हिन्दुस्तान भरमें एवं दुनिया भरमें हमने यह ढोल पिटवाया है कि बंगालमें इसबार काफी धान फला है। यह होते हुए भी इसी मार्चके महीनेमें ही देशके लोगोंकी ऐसी हालत है ! लोकमतको ठुकराया जाता है। विरोध

करनेवालोंका जबरदस्ती मुँह बन्द किया जाता है; किन्तु इससे तो लोगोंको जिन्दा नहीं रखा जा सकता। पिछले साल ठीक यही तरीका काममें लाया गया था, सारे देश भरमें तभी इतना बड़ा सर्वनाश फैल गया।

बांकुड़ाके पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्टने बर्दमान रेंजके डिप्टी इन्सपेक्टर जनरल आव पुलिसको, कुछ दिन हुए, बतलाया है कि चावल और खरीजकी हालत ठीक-ठीक पिछले सालकी जैसी हो चली है। चावलका दाम चढ़ रहा है, बाजारसे चावल और खरीज लोप हो रही है। पुलिसके लोग गवर्नमेंट स्टोरसे जो चावल पा रहे हैं, वह एकदम ही खानेके लायक नहीं। चार किस्मका चावल इकट्ठा मिला हुआ, और उसमें काफी कंकड़-पत्थर। इसे खाकर सब पेटके दर्दसे पीड़ित हैं। इस तरहका चावल अगर दिया जाता रहा तो पुलिस-दल काम करनेकी ताकत खो बैठेगा।

सुहरावर्दी साहबने बार-बार कहा है कि बंगालमें जो खराब चावल आ रहा है, उसके लिये केन्द्रीय सरकार जिम्मेदार है। केन्द्रीय सरकारने तेज आवाजमें इसका प्रतिवाद किया। नयी दिल्लीकी धमकी खाकर सुहरावर्दी साहब तब सुर बदल कर कहने लगे कि उड़ीसा-गवर्नमेंटकी गलतीसे यह बात हुई है। २४ मार्च को (१९४४) उड़ीसा-गवर्नमेंटका वक्तव्य प्रकाशित हुआ है। देखा गया है कि उसके ऊपर भी झूठा दोष लगाया गया। इस मामलेमें उड़ीसा-गवर्नमेंटकी जरा भर भी जिम्मेदारी नहीं। तो दोष किसका है? खराब चावल लानेके लिये किसको जिम्मेदार बनाना होगा? सिविल-सप्लाइज मन्त्रीने कलकत्तेमें विराजकर एक बात कही है। उन्होंने दूसरी ओर एक प्रान्तीय सरकारके ऊपर दोष लगाया है। यही सब करके मन्त्रिमण्डलने आम जनताकी आस्था खो दी है।

हमने शिकायत की थी कि हजारों मन धान जैसोरके स्टेशनपर पड़ा-पड़ा बर्बाद हो रहा है। सुहरावर्दी साहबने उस वक्त कहा कि इसका क्या इलाज है? गाड़ी वगैरह नहीं मिल रही हैं। दिल्लीसे सर एडवर्ड बेंथलने इसका जवाब दिया है। वह हिन्दू नहीं, मुसलमान भी नहीं; विरोधी दलके साथ उनका मेल-जोल भी नहीं। उन्होंने कहा है कि बंगाल-सरकारके तय किये हुए कार्यक्रमके मुताबिक ही केन्द्रीय-सरकारने गाड़ी वगैरहकी व्यवस्था की है। जो कार्यक्रम बंगाल-सरकारने भेजा था, उसमें जैसोरके इस जमा पड़े हुए धानका जिक्र भी नहीं। लाखों आदमियोंके जीने-मरनेके मामलेमें इस तरह बेरहम लापरवाही करके वह संकटको और बढ़ा रहे हैं।

भयंकर दुखके मौकेपर भी गवर्नमेंटका लाभका कारोबार चला है। दूसरे सूबोंसे सस्ता गेहूं खरीदकर बंगालके भुखमरोंको वह ऊँचे दामोंपर बेचा गया है। इससे लाखों रुपयेका फायदा हुआ है। सुहरावर्दी साहब कहना चाहते हैं कि वह मामला तो अब बीत चुका है—फिर क्यों? किन्तु २१ फरवरी-को मि० पी० आर० सेनने कौन्सिल आव स्टेटमें भाषण देते हुए कहा है कि हालमें भी कई महीनोंसे वही कारोबार चल रहा है। सुहरावर्दी साहब और मन्त्री लोग इसे इनकार करते हैं, किन्तु लोगोंमें अब भरोसा रहा नहीं।

हम हृदयसे चाहते हैं कि इस मौजूदा सालमें कहीं पिछले सालकी-सी हालत न हो। गवर्नमेंटके ऊपर आम लोगोंका हटा हुआ विश्वास जबतक लौट नहीं आता, तबतक इस विषयमें निःसंशय नहीं हुआ जाता। केन्द्रीय असेम्बलीमें एक अद्भुत चेष्टा दिखलाई दी कि लोक-हितके लिये वहांपर मुसलिम-लीग दलने और दलोंके साथ हाथ बंटाया है। देशके भविष्यका

खयाल कर बंगालका मुसलिम लीग-दल भी क्या इसी तरह साहस और दूर-न्देशीका परिचय देगा ? दलबन्दीको भूलकर आज ऐक्य-बद्ध न होंगे, तो बंगालका भविष्य अन्धकारपूर्ण होगा, खाद्य-संकटका स्थायी समाधान किसी तरह भी न हो सकेगा।

इसी बीच धारा-सभामें एक दिन सुहरावर्दी साहबने फरमाया है कि मैं यूरोपियन-दलकी सहायता मांगने गया था। उस दिन मैं (सभामें) मौजूद न था। इसीलिये जवाब न दे सका। यूरोपियन दलके साथ मेरा और अन्य दो मित्रोंका कुछ वार्तालाप हुआ था। किसी दलगत स्वार्थके लिये हमने उसकी सहायता नहीं चाही। बंगाल धारा-सभामें भारतीय सदस्यगण दो दलोंमें बंट गये हैं। हिन्दू और मुसलान प्रायः हम सब मिलकर—विरोधी दलमें हैं। और भी दस आदमी जेलमें कैद हैं, वे भी हमारे ही दलमें हैं। सरकारी दलमें भी हिन्दू-मुसलमान सब मिला कर दस या पन्द्रह आदमी होंगे। फिर तीस और हैं—वे हिन्दू भी नहीं, मुसलमान भी नहीं। ये ही गवर्नमेंटके दलको भारी करके उसके ऊपर अपना असर डाले हुए हैं। हमने यूरोपियनोंसे कहा था कि हम विरोधी दलके लोग देशके इस संकटके मौकेपर सरकारी दलसे मिल-जुलकर खाद्य-समस्याका समाधान कराना चाहते हैं। आप लोग ही दलबन्दीको जिलाये हुए हैं। मिलकर काम करनेके अलावा हमारी रक्षाका और कोई रास्ता नहीं, किन्तु आप लोग ही मेलमें बाधाकी सृष्टि कर रहे हैं।

हाईकोर्टके एक प्रधान विचारपतिकी एक अभी हालकीही रायके सम्बन्धमें मैं उल्लेख करूंगा। वे विरोधी दलके कुछ नहीं होते, उनकी कलम और

मतके ऊपर विरोधी दलका कुछ भी प्रभाव नहीं है। धारा-सभाके एक सदस्य विरोधी दलमेंसे थे। उनके खिलाफ फौजदारी चल रही थी। इन्हें लोभ दिखाया गया कि सरकारी दलमें शामिल होनेपर फौजदारीका मामला उठा दिया जायगा। सरकारके किसी एक विभागके सेक्रेटरीको आदेश हुआ कि (किसने आदेश दिया, उसका नाम प्रकट नहीं है) जिला मजिस्ट्रेटके पास जाकर उस मामलेमें लम्बा समय लिया जाय। प्रधान विचारपति चिट्ठी और कागजात देखकर मामलेके सम्बन्धमें निःसंशय हो गये।

यह सिर्फ एक ही मिसाल है। इसी तरह सौ-सौ मिसालें दी जा सकती हैं। इसीके फलस्वरूप आम जनताने मन्त्रिमण्डलमें विश्वास खो दिया है।

हम चाहते हैं कि इस भारी दुःखके मौकेपर यथार्थ शक्तिशाली गवर्नमेंट गठित हो। जो शासन-कार्यमें सहयोग देना चाहें, इस तरहके सब दलोंके प्रतिनिधियोंको उसमें स्थान हो। यह होनेपर संकटका अन्त होगा। हम हृदयसे सहयोगका हाथ बढ़ा रहे हैं। जो दल आज मन्त्रिमण्डलको यथार्थमें बचाये हुए हैं, विश्वास है कि इस आह्वानका वे प्रत्युत्तर देंगे। अनाजकी यह हालत है कि देशवासी दिलका साहस और उद्यम खोते जा रहे हैं। युद्ध-की गति तेजीसे पलट रही है, इस दशामें चली आनेवाली शासन-व्यवस्थाको चलने देना खतरनाक भूल होगी।

विपत्तिके सामने हम ऐक्यका रास्ता ग्रहण करेंगे। आनेवाली सन्तान जिससे कह सके कि हमने वाद-विवाद किया है, किन्तु जातिके दुःसमयमें सम्मिलित शान्तिसे दुर्दमनीय भी हुए हैं। हिन्दू-मुसलमान-ईसाई—सभी-

की परमप्रिय मातृभूमिकी रक्षाके लिये हममेंसे हरएक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत नफा-नुकसान और साम्प्रदायिकताको छोड़कर इस आड़े वक्तपर आपसमें एक होकर महाजातिके रूपमें साथ खड़े होंगे ।*

---

* २६ मार्च सन् १९४४ को बंगाल धारा-सभामें दी गयी वक्तृताका सारांश ।

परिशिष्ट

बंगाल रिलीफ कमेटी

कमेटीने २७,४२,३६३) रु० ४ पाई और नीचे लिखे सामानका संग्रह किया है—

अनाज ५४,४४७ मन ५ सेर
बनियान ४,५२६ दर्जन
धोती और साड़ी ८,७३७ जोड़ा
ब्लाउज ५४
मार्किन २०० थान
पुराने कपड़े २७ गाँठें
सुजनी ७,१७८
दूध १,६३२ पाउण्ड
कम्बल ३,४५०
बिस्कुट १३ बस्ते

नीचे लिखे परिमाणमें सामानसे कमेटीने पीड़ितोंकी सहायता की है—

अनाज १,४२,८६३ मन ५ सेर
पुराने कपड़े ५४ गाँठें
धोती और साड़ी १,४४,८७४
दूध १,६३२ पाउण्ड
मार्किन १,७७० थान
बिस्कुट १३ बस्ते
सुजनी ७,१७८
गुड़ २,२१३ मन ११॥ सेर
कम्बल ६८,५३९
घुटन्नो २,७६०
बनियान ६१,६९२
कमीज़ १०,०००
ब्लाउज ४,७५४

परिशिष्ट

दाताओंने जो अनाज भेजा है और जो कलकत्तामें खरीदा गया है, ऊपरके हिसाबमें सिर्फ वही शामिल है। इसके अलावा कमेटीके विभिन्न मुफस्सल केन्द्रोंमें बांटने और कम दामोंपर बिक्री करनेके लिये काफी परिमाण-में अनाज खरीदा गया है। उसका हिसाब अभी आया नहीं है।

कमेटीने विभिन्न खातोंमें निम्नलिखित रूपमें खर्चा किया है—

अनाज वितरण, कम दामोंपर नुकसान उठाकर अनाजकी बिक्री और दूधका वितरण ११,१७४५३) रु० ६ पाई

कपड़ा ४,१०,८३४) रु०

संस्कृत-पण्डित और विद्यार्थियोंकी सहायता दाताओंकी मर्जीके मुताबिक ५५,२६३)

पुनर्गठन स्कीमके मुताबिक २०,४०७)

कुछ सेवा-समितियोंको आर्थिक सहायता १,७०,८६६) रु० ३ पाई

चिकित्सा १,१९,४०६) रु० ९ पाई

विद्यार्थियोंकी सहायतामें दान ६,००३) रु०

शिशु-निवास ३६,१०५) रु०

कृषकोंको बीज और खाद ५,१२२) रु० ६ पाई

छात्र-निवास १९,४६१) ६ पाई

आने-जानेका रेल किराया, लोगोंका वेतन, प्रचार-व्यय डाक-खर्च, तार और टेलीफोन इत्यादि खर्च १२,६९४) रु०

कुल जमा ७,६९,७१८) रु० १० पाई

बंगाल प्रान्तीय हिन्दू-महासभा रिलीफ कमेटी

कमेटीने २९ फरवरी १९४४ तक कुल ७,६१,०७६ रु० ९ पाई संग्रह किया। व्यय किया है ६,३९,१३६ रु० ४ पाई। नीचे लिखे विभिन्न खातोंमें यह रुपया व्यय हुआ—

अनाजकी खरीद २,९९,६१२)

कपड़े, कम्बल आदिकी खरीद ६४२४७) १० पाई

सूत इत्यादिकी खरीद ९,४४)

सूद और बैंक खर्च ९०७)

शिक्षक, पाठशालाओंके पंडित और मध्यवित्त लोगोंकी सहायता १९,६६८)
व्यक्तिगत सहायता ७,६५०)
गोदामका किराया २५०)
देख-रेख आदिकी बाबत २,५००)
विभिन्न सेवा-समितियोंको सहायता १, १०,९१९) रु० ६ पाई
राजबन्दियोंकी सहायता ३५,७१२) रु०

१३ मार्च १९४४ तक निम्न-लिखित परिमाणमें अनाज संग्रह और व्यय किया गया है—

खरीदा गया	१३,३८७ मन (५१२९ बोरे)
सहायताके रूपमें प्राप्त हुआ	२२,२८९ मन (८८९१ बोरे)
कुल	३६,६७६ मन (१४०३० बोरे)
बाँटे गये	३२,४४५ मन (१२,७७६ बोरे)
जमा	३,२३१ मन (१,२५२ बोरे)

श्रीयुत हृदयनाथ कुंजरूका वक्तव्य

ढाका, नारायणगंज, मुंशीगंज, ब्राह्मणबड़िया और चाँदपुरका दौरा करके लौटनेपर २२ अक्टूबर, १९४३ को कुंजरूजीने जो वक्तव्य दिया, यह उसीका सारांश है। दूसरे सूबेके एक निरपेक्ष विशिष्ट व्यक्तिने बंगालके अकालको किस तरह देखा है, इससे इस बातका परिचय मिलेगा।

सभी जगह दुर्वस्था ऐसी भयावह है कि अपनी आँखों देखे बिना उसपर विश्वास करना कठिन है। शहरों और देहातोंमें भूखे रहना आजकल लोगोंकी किस्मतमें ही जुड़ गया है। शहरकी अपेक्षा देहातोंकी हालत अधिक खराब है। गाँवमें रहने वालों—विशेषतः स्त्री और बच्चोंकी बेहालीको देख

कर आँखोंमें आँसू आ जाते हैं। माँ-बाप सन्तानको त्याग रहे हैं, पति पत्नीको छोड़ रहा है—इस तरहकी घटनाएँ दिन-ब-दिन बढ़ती ही चली जा रही हैं। सामान्य खेतिहर और बे-जमीन मजदूर लोग भोजन खरीदनेके लिये नाममात्र दामोंपर घर-द्वार बेच रहे हैं। भूखसे कमजोर ग्रामीण लोग घरकी छाजनके टीन खोलकर बेच रहे हैं, नारायणगंजमें इस तरहका दृश्य देखनेमें आया।

ये सब बेघर लोग कोरमकोर हालतमें शहरमें चले आते, और लंगर-खानोंमें भीड़ लगाते हैं। किसानोंने चावल जमाकर रखा है—यह शिकायत मौजूदा हालतमें पूरी तौरपर गलत मालूम हुई। गाँव वाले भूखसे मर रहे हैं; उनके खिलाफ अनाज जमाकर रखनेका अभियोग लगाना बहुत ही ज्यादा बेरहमीका काम है। मैंने देहातोंके बाजारमें बहुत कम मात्रामें चावल बिकते देखा है। इस चावलका दाम कहीं भी ५०) रु० मनसे कम नहीं। शहरमें कीमत और भी अधिक है। चावलके मूल्य-नियन्त्रणसम्बन्धी जो आदेश सफल नहीं रहा, मैं समझता हूं कि उस आदेशको रद्द करनेसे मुफस्सलके बाजारोंमें कुछ चावल आ सकता है। इस सम्बन्धमें सिर्फ गैर-सरकारी लोग नहीं, अनेक सरकारी कर्मचारियोंके साथ भी मुझे मिलनेका मौका हुआ है। उन्होंने मुझसे कहा है कि उस तरहकी व्यवस्थासे भी काफी परिमाणमें चावल नहीं मिलेगा।

ढाका, चाँदपुर, नारायणगंज आदि कुछेक जगहोंमें आश्रय-केन्द्र खुले हैं। जो सब लोग सड़कोंपर पड़े मरते जाते हैं, उन्हें यहाँ लाया जाता है। मलेरिया, पेचिश, पेटकी पीड़ा और अन्यान्य रोगोंसे पीड़ित और भूखसे

पस्त लोगोंके लिये एमरजेन्सी अस्पताल खोले गये हैं। तब भी सड़कके किनारे जहां-तहां मुर्दे और मरते हुए लोग देखनेमें आते हैं। भूखसे कमजोर स्त्री-पुरुष सड़कपर चलते हुए शवकी तरह लगते हैं। ये अगर आखिर तक जान बचा भी सके, तो उसे दैवी-घटना समझना होगा। आश्रय-स्थानों और एमरजेन्सी अस्पतालोंमें जिन्हें जगह दी गयी है, उनके सम्बन्धमें भी ठीक यही बात लागू होती है।

कामन्स सभामें मि० एमरीने बंगालके अन्दर रोगकी व्यापकता और दवाइयोंका अभाव एकदम ही अस्वीकार किया है। उनका यह कथन यथार्थ घटनाके बिलकुल खिलाफ है। दवाइयोंकी खास कमी है; कुनीनको एक तरहसे अप्राप्य कहा जा सकता है। स्त्री-पुरुषोंने जीवनी-शक्ति खो दी, इससे बीमारी देश भरमें फैलती जा रही है।

सरकारी और गैरसरकारी लंगरखानोंसे काफी सहायताका काम हो रहा है। किन्तु इनकी संख्या बहुत ही कम है। खाद्य-वस्तुओंके अभावसे फिर वह जो हैं भी, बीच-बीचमें बन्द रखने पड़ते हैं। इन सब लंगरखानोंमें फी आदमी दोसे लेकर अढ़ाई छटाक तक खिचड़ी दी जाती है। दिये जानेवाले खाद्यका परिमाण सभी जगह बहुत कम है। ढाका सेंट्रल रिलीफ कमेटी ढाका शहरमें माल पहुँचानेके प्रबन्धको चला रही है। सेसन्स जज मि० दे कमेटीके सभापति हैं। सुननेमें आया है कि मोहल्ला-कमेटियोंने फी आदमी माहवारी बारह छटांक चावल और बीस छटांक आटा दिया है। सभी जगह खाली चावल ही नहीं, सभी प्रकारकी खाद्य वस्तुओंका अभाव है। निचली मध्यवित्त श्रेणीके लोग ही सबसे ज्यादा बेहाल हैं।

परिशिष्ट

बंगालमें आनेके पेश्तर मेरी धारणा थी कि बंगाल-सरकारपर बुरी तरहसे हमला करनेके लिये, राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी लोग अवस्थाका अतिरंजित विवरण दे रहे हैं। किन्तु अब मैं देख रहा हूँ कि बंगालके नेताओंने जो कुछ कहा है, उसका प्रत्येक अक्षर सच है। भारतवासियों और ब्रिटिश जनताके सामने सच्चा विवरण देकर उन्होंने देशका बड़ा भला किया है। कपड़ोंका अभाव खाद्यके अभावके समान ही है। केवल धोती-साड़ी नहीं—इस वक्त गरम कपड़ोंकी भी बड़ी जरूरत है।

मि० एमरीने कहा है कि, हफ्तेमें प्रायः एक हजार आदमी मर रहे हैं। किन्तु मेरी धारणा है कि मौतोंकी तादाद बहुत ज्यादा है। एक सब-डिवीजनके सम्बन्धमें मुझे कहा गया है कि फी हफ्ते साढ़ेसात सौसे लेकर एक हजार तक आदमी मर रहे हैं। शहरमें भी मौतका आहार बहुत अधिक है।

अमनकी फसलकी बाबत सरकार क्या नीति ग्रहण करेगी, इस सम्बन्धमें लोग बहुत बेचैनीमें पड़े हैं। वे समझते हैं कि सरकार द्वारा सारा अनाज खरीद लिये जानेपर नतीजा चिन्ताजनक होगा।

सरकारके खिलाफ और भी शिकायत है कि वह कलकत्तेवालोंकी जानें बचानेमें ही व्यस्त है; मुफस्सलकी बात वह सोचती भी नहीं।

अवस्थाके गुरुत्वके बारेमें सभीको आगाह हो जाना ठीक है। इस विषयमें केन्द्रीय सरकारकी भारी जिम्मेदारी है। लार्ड वैवलकी कार्य-कुशलताके ऊपर बंगालका भविष्य बहुत कुछ निर्भर है।

॥ इति ॥